हिन्दुस्तान 1936

भूलने के पीछे प्रदूषण

वायु प्रदूषण को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। एक नए शोध में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के नियमित संपर्क में रहने पर मनोभ्रंश का खतरा बढ़ जाता है। मनोभ्रंश अर्थात डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का दुनिया में बढ़ता खतरा इतना बड़ा है कि आगामी पच्चीस वर्ष में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या तीन गुना हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने वायु प्रदूषण में खासकर कार से निकलने वाले धुएं या उत्सर्जन को गंभीर माना है। द *लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ* पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से पता चलता है कि पीएम2.5 के प्रत्येक 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के चलते किसी व्यक्ति में भूलने के रोग का जोखिम 17 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। पीएम2.5 में पाए जाने वाले प्रत्येक एक माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर कालिख के चलते जोखिम 13 प्रतिशत बढ़ जाता है। यह कालिख वाहनों के धुएं और जलती हुई लकड़ी जैसे स्रोतों से आती है। चिंता इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि वायु प्रदूषण में समय के साथ लगातार वृद्धि हो रही है। रोकने के जितने समर्पित प्रयास विश्व स्तर पर होने चाहिए, नहीं हो रहे हैं।

यह बताते चलें कि फिलहाल भूलने की इस बीमारी से दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ 74 लाख लोग ग्रस्त हैं। ध्यान रहे यह महज दर्ज संख्या है। अगर वायु प्रदूषण को युद्ध स्तर पर घटाया नहीं गया, तो मनोभ्रंश के रोगियों की दर्ज संख्या साल 2050 तक तीन गुना बढ़कर 15 करोड़ 28 लाख तक पहुंच जाएगी। मनोभ्रंश की रोकथाम के लिए फिलहाल ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे हैं। औषधि के स्तर पर भी ज्यादा प्रयोग नहीं हो रहे हैं और वास्तव में यह बहुत दुखद सच्चाई है कि इस रोग का कोई पुख्ता इलाज मौजूद नहीं है। इस रोग की जो दवाएं उपलब्ध हैं, उनके कारगर होने पर स्वयं वैज्ञानिकों को संदेह है। नतीजा यह कि एक बार जब व्यक्ति इस रोग की चपेट में आता है, तो धीरे-धीरे याददाश्त छिनती चली जाती है। यह रोग पुराना है, पर आधुनिक दुनिया में इसके रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रथम लेखक डॉक्टर क्रिस्टियान ब्रेडेल आगाह करते हैं कि डिमेंशिया की रोकथाम केवल स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी नहीं है। ताजा अध्ययन इस तथ्य की तस्दीक करता है कि शहरी नियोजन, परिवहन नीति और पर्यावरण नियमन, सभी की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हमें ईमानदारी से सोचना चाहिए कि सुधार के पैमाने पर हम कहां खड़े हैं?

अगर वायु प्रदूषण को युद्ध स्तर पर घटाया न गया, तो डिमेंशिया के रोगियों की दर्ज संख्या साल 2050 तक तीन गुना बढ़कर 15 करोड़ 28 लाख तक पहुंच जाएगी।

ताजा शोध ने बहुत स्पष्टता के साथ प्रकाश डाला है कि वायु प्रदूषण मस्तिष्क में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बन सकता है। वायु प्रदूषण से शरीर में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिससे कोशिकाओं, प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचता है और इससे भूलने की बीमारी शुरू होती है। शोध ने सुधार की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट किया है कि वायु प्रदूषण से निपटने से स्वास्थ्य, सामाजिक, जलवायु और आर्थिक मोर्चे पर दीर्घकालिक फायदा हो सकता है। यह रोगियों, परिवारों और देखभाल करने वालों पर पड़ने वाले भारी बोझ को भी घटा सकता है। यह महा-अध्ययन लगभग 51 अध्ययनों के आधार पर किया गया है। इसमें लगभग तीन करोड़ लोगों को परखा गया है। यहां भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब उच्च आय वाले देशों में प्रदूषण और मनोभ्रंश की स्थितियां गंभीर हो रही हैं, तब भारत में हम बेहतर स्थितियों के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते, अर्थात हमें सबसे पहले वायु प्रदूषण का इलाज करना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 28 जुलाई, 1950

युद्ध फैलने का भय

कोरिया के संघर्ष में युद्ध फैलने का भय छिपा हुआ है। कोरिया की युद्ध-स्थिति पर जनरल मेकआर्थर की पहली रिपोर्ट सुरक्षा परिषद के सामने प्रस्तुत की गई है। उसमें बताया गया है कि इस समय केवल अमरीकी फौजें कोरिया में लड़ रही हैं। अवश्य ही, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नीदरलैंड ने अमरीकी फौजों को मदद पहुंचाने के लिए अपने समुद्री जहाज भेजे हैं। किन्तु कोरिया में युद्ध की सीधी झुलस अमरीकी फौजों को ही बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जनरल मेकआर्थर का कहना है कि साम्यवादियों के पास रूसी युद्ध-सामग्री है और उनके साधन उनकी आंतरिक क्षमता से अधिक हैं। युद्ध की अब तक की रफ्तार से यह तो स्पष्ट हो ही चुका है कि कोरिया में साम्यवादियों की ताकत साधारण नहीं है। वह न केवल दक्षिण कोरिया की फौजी ताकत से श्रेष्ठतर थी, बल्कि उसने अमरीकी फौजों को भी अपने जमे हुए मोर्चों से पीछे हटने को बाध्य किया है। साम्यवादी फौजें दो-तिहाई कोरिया को हस्तगत करने में कामयाब हो गई हैं। वे कोरिया के दक्षिण-पश्चिमी समुद्री तट तक जा पहुंची हैं।

जनरल मेकआर्थर कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की फौजों को, जो दूसरे शब्दों में अमरीकी फौजें ही हैं, उस समय तक कोरिया में बने रहना है, जब तक दक्षिण कोरिया के प्रजातंत्र की वैधानिक सत्ता पूर्णतया पुनः स्थापित नहीं हो जाती। अमरीकी फौजों का यह दृढ़ निश्चय बताया जाता है कि कम से कम वे तीस मील के इलाके में अपने पांव जमाये रखेंगी और पुसान बंदरगाह को अपने हाथों से नहीं निकलने देंगी, जो उनकी रसद पूर्ति का मुख्य साधन है। किन्तु युद्ध में सैनिक आवश्यकताओं के आगे बड़े-से-बड़े दृढ़ निश्चय बदल जाते हैं। इतना तो जनरल मेकआर्थर ने भी स्वीकार किया है कि जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पास युद्ध सामग्री और जनशक्ति विरोधी पक्ष की अपेक्षा अधिक नहीं होगी, तब तक साम्यवादी सेनाओं को पीछे नहीं धकेला जा सकेगा। यदि कहीं साम्यवादी सेनाओं ने अमरीकी फौजों को एक बार कोरिया छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, तो कोरिया की धरती पर पुनः उतरना तथा साम्यवादियों को 38 अक्षांश तक वापस हटाना बहुत व्यय-साध्य हो जायगा। अमरीकी राष्ट्रपति श्री ट्रूमन ने अमरीकियों से यह महसूस करने को कहा भी है कि कोरिया का युद्ध व्यय-साध्य होगा और जल्दी समाप्त नहीं भी हो सकता है।

व्यापार के नए दौर में भारत और ब्रिटेन

यहां सौन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज, लंदन

'ब्रेग्जिट' के बाद से ब्रिटेन का किसी देश के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण समझौता है। ट्रंप की टैरिफ नीति से पैदा हुई अस्थिरता को देखते हुए यह ज्यादा जरूरी हो गया था।

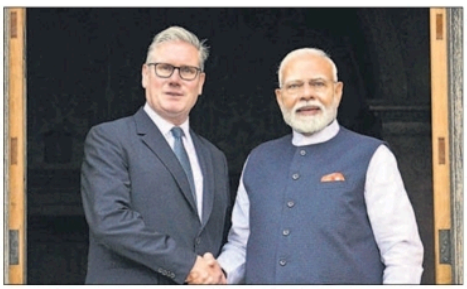

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ नया आर्थिक करार नई विश्व व्यवस्था में आपसी संबंधों का मजबूत आधार बनाने का काम करेगा। करीब तीन साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों देशों ने आखिरकार बीते गुरुवार को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यह संधि एक ऐसे वक्त पर हुई है, जब विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल है।

भारत और ब्रिटेन का मुक्त व्यापार समझौता कई अर्थों में बेहद महत्वपूर्ण और दोनों देशों के अनुकूल भी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यह समझौता ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा और ब्रिटिश कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। समझौते की शर्तों के मुताबिक, व्हिस्की, कार, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में काम करने वाली ब्रिटिश कंपनियां अब कहीं अधिक आसानी से भारत में निर्यात कर सकेंगी। इसके बरअक्स, करीब 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात वहां शुल्क-मुक्त कर दिए गए हैं। यहां से जाने वाले रत्न-आभूषण, समुद्री उत्पाद, वस्त्र, खाद्य तेल आदि उत्पादों पर अब कोई कर नहीं चुकाना होगा। यही वजह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते से व्यापार, निवेश, विकास व रोजगार-सृजन के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई है।

ब्रिटेन के नजरिये से देखें, तो उसे इस समझौते की बेहद जरूरत थी। खासतौर से 2020 के बाद से, जब वह यूरोपीय संघ से अलग हुआ था, उसे ऐसी बड़ी आर्थिक ताकतों की तलाश रही है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद कर सके। भारत इस पैमाने पर खरा उतरता है। भारत फिलहाल चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, जो जल्द ही शीर्ष तीन में शुमार होने वाला है। लिहाजा, यह ब्रिटेन के हित में है कि वह भारत का साथ लेकर आगे बढ़े। इधर, भारत की इच्छा समान सोच वाले देशों के साथ अच्छे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध विकसित करने की रही है। नई दिल्ली उन तमाम ऐसे देशों का साथ चाहती है, जिनसे भारत की आर्थिक क्षमता को बल मिले। इससे भारत की विकास दर में भी इजाफा होगा। जाहिर है, इस समझौते में दोनों देशों के हितों को पूरा करने की भरपूर संभावना दिखती है।

'ब्रेग्जिट' के बाद से ब्रिटेन का किसी देश के साथ यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्वाकांक्षी समझौता है। एक तरह से यह समझौता उसकी विदेश और आर्थिक, दोनों नीतियों को फिर से परिभाषित कर रहा है। अब उसके बाजार में आने वाले भारतीय उत्पादों की कीमतें घट जाएंगी। चूंकि 99 फीसदी भारतीय उत्पाद अब टैरिफ-मुक्त हो गए हैं, इसलिए वहां भारतीय कंपनियों को विस्तार करने का मौका मिलेगा। इसमें ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा में मिलने वाली तीन साल की छूट भी काफी मददगार साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि 75,000 भारतीयों को इसका लाभ मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था ब्रिटेन ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ के देशों के साथ ही कर रखी है।

देखा जाए, तो इस समझौते की एक बड़ी बुनियाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार की है। वह जब से व्हाइट हाउस में आए हैं, अपने टैरिफ संबंधी फैसलों से तमाम देशों की उलझनें बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि कई देश अमेरिकी बाजार से विमुख होने के बारे में सोचने लगे हैं और अपने उत्पादों के लिए नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन जैसे देश आर्थिक नीतियों में स्थिरता के हिमायती रहे हैं। इसीलिए, उन्होंने इस समझौते पर मुहर लगाई, जिसे व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता भी कहा जा रहा है। कुछ उद्योगों में भारत को काफी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनमें श्रम का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब उसमें भारत को फायदा मिल सकता है। ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों को जो औसतन 15 फीसदी शुल्क देना पड़ता था, वह भी घटकर पांच प्रतिशत पर आ गया है। इन सबसे एक नया आर्थिक रोडमैप तैयार होगा।

हालांकि, इस समझौते में पेशेवर कामगारों के आवागमन की चर्चा तो है, पर भारत ने वीजा व्यवस्था में जो रियायत की मांग की थी, विशेषकर आईटी और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों की सहूलियत का जो मसला उठाया था, वह उतना प्रभावी रूप से समझौते में शामिल नहीं हो सका। मगर भारत ने उदारता दिखाने का ही संकेत दिया है, ताकि बन रही 'ग्लोबल वैल्यू चेन' में वह बेहतर तरीके से शामिल हो सके। 'ग्लोबल वैल्यू चेन' का आशय किसी उत्पाद या सेवा के निर्माण व वितरण की उस शृंखला से है, जो कई देशों में फैली होती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसरा उत्पादन नेटवर्क है, जिसमें विभिन्न देशों में स्थित कंपनियां एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। चूंकि भारतीय उद्योग लगातार अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमारा शामिल होना फायदेमंद होगा।

हालांकि, इस समझौते का एक और पहलू भी है। 'ब्रेग्जिट' के बाद से ब्रिटेन ऐसी विदेश नीति की खोज में है, जिसमें नए अवसरों की उसकी तलाश पूरी हो सके। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से नए समीकरण बन रहे हैं, उसमें उसे भारत से बेहतर कोई दूसरा साथी नहीं मिल सकता था। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी यात्रा में इसकी तस्दीक भी होती है। इस दौर में आर्थिक समझौता तो किया ही गया, तकनीक, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा आदि पर भी आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच आम लोगों के जुड़ाव के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इस रिश्ते को भी नए ढांचे में गढ़ने की जरूरत बताई गई है। भारत-विरोधी अतिवादी समूहों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। चूंकि दोनों देश चरमपंथ से जूझ रहे हैं, इसलिए सरकारी और खुफिया तंत्रों के एक साथ काम करने पर भी उन्होंने हामी भरी है।

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक व सामरिक नजरिये से भी अहम रही। दोनों देश न सिर्फ आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, बल्कि एक-दूसरे के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर उत्साह दिखा रहे हैं। इसीलिए यह गलत नहीं कहा जा रहा कि नई विश्व व्यवस्था में दोनों देश आपसी संबंधों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पूरे देश में अब मुफ्त बांटी जाएं हेपेटाइटिस रोग की दवाएं

यहां सौन करें

चंद्रकांत लहारिया | वरिष्ठ चिकित्सक

आज (28 जुलाई) 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' है। इसी दिन 1965 में डॉ बारूच ब्लूमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, जो बीमारी की रोकथाम में बड़ी कारगर साबित हुई। बाद में इसके अन्य वायरस का भी पता चला। 1981 में दुनिया की पहली हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आ गई, जो बड़ी उपलब्धि है। इस संदर्भ में इस साल की 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' की थीम 'हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता' काफी मायने रखती है। हालांकि, हेपेटाइटिस सी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है, पर 2014 में इसके लिए अत्यंत प्रभावकारी दवाइयां आईं, जो भारत में न के बराबर कीमत पर मिल जाती हैं।

इतनी सफलताओं के बावजूद यह बीमारी आज भी एक बड़ी चुनौती है। साल 2022 में दुनिया भर में करीब 31 करोड़ लोग क्रोनिक हेपेटाइटिस बी व सी से पीड़ित थे और करीब 13 लाख लोगों की मृत्यु इस बीमारी से हुई। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमित रक्त, शरीर के तरल फ्लुइड्स या प्रसव के दौरान मां से बच्चे में फैलते हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी से फैलते हैं। दुनिया में इस बीमारी की वजह से होने वाली मौतों की संख्या टीबी से होने वाली मौतों के बराबर है, पर इस पर टीबी से कम ध्यान दिया जाता है। अगर भारत की बात करें, तो करीब तीन करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और 55 लाख हेपेटाइटिस सी के रोगी हैं। लंबे समय तक इनके संक्रमण रहने से लीवर सिरोसिस और लिवर कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है। एक बड़ी चुनौती यह है कि हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हर 40 में से सिर्फ एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है।

देश में करीब साढ़े तीन करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और सी के रोगी हैं। लंबे समय तक इनके संक्रमण से लिवर कैंसर की आशंका बढ़ जाती है।

साफ है, भारत में हेपेटाइटिस एक गंभीर समस्या है। इसीलिए साल 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) भी शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य 2030 तक इसके बी और सी टाइप का देश से पूरी तरह उन्मूलन कर देना है। 2007 के बाद से देश में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नवजात शिशुओं और बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका लगना शुरू हुआ। यूं तो सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी की जांच व इलाज की सुविधा बताई जाती है, लेकिन इनमें अब भी कई चुनौतियां बाकी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वे संक्रमित हैं, क्योंकि इसके लक्षण वर्षों तक दिखाई नहीं देते हैं। लोगों के मन में इससे जुड़ी कई भ्रांतियां होती हैं, जिससे वे इसे छिपाते भी हैं। अब समय है कि हम स्कूलों, कॉलेजों, कार्यस्थलों और जन-समुदायों में बीमारी के प्रकार, लक्षण और टीकाकरण के बारे में जागरूकता लाएं।

अभी हेपेटाइटिस बी का ज्यादा संक्रमण प्रसव के समय मां से होता है, जिसे जन्म के 24 घंटे के अंदर नवजात शिशु को टीका लगाकर रोका जा सकता है। इन टीकों को प्रचारित करने की जरूरत है। साथ ही हर स्तर पर सुरक्षित रक्तदान और इंजेक्शन द्वारा संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। खासतौर से अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित है, तो परिवार के अन्य सदस्य इसका टीका लगवाकर संक्रमण से पूरी तरह बच सकते हैं। संक्रमण का पता हो, तो हेपेटाइटिस सी को तो दवाओं से पूरी तरफ से ठीक किया जा सकता है और हेपेटाइटिस बी को रोकथाम व इलाज से। वहीं, हेपेटाइटिस ए और ई को साफ पानी, खाने में सफाई आदि से रोका जा सकता है। याद रखना होगा कि हेपेटाइटिस ई गर्भवती महिलाओं में खतरनाक हो सकता है।

दुखद है कि अभी भी हेपेटाइटिस बी या सी का इलाज लिवर विशेषज्ञ पर निर्भर है, जबकि जरूरत है कि इनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होना चाहिए। तभी यह आम जनता तक पहुंच सकेगा। जरूरत इस बात की भी है कि हर फैमिली फिजिशियन व जनरल फिजिशियन को इस बीमारी की रोकथाम व इलाज के लिए प्रशिक्षित किया जाए। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों की दवाएं भारत में उपलब्ध हैं और इनकी कीमत भी कम हैं। 'डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल ग्रुप' की दवाओं के 12 सप्ताह इस्तेमाल से हेपेटाइटिस सी लगभग 90 फीसदी लोगों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कुछ राज्यों में ये दवाएं सरकारी द्वारा सभी लोगों को मुफ्त में दी जा रही हैं। अब पूरे देश में इन दवाओं को मुफ्त करने की जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जीवन की परीक्षा जीवन

वर्तमान शिक्षा बच्चों को पढ़ने-लिखने के योग्य तो बनाती है, लेकिन जीवन जीने योग्य नहीं बनाती। कोई बच्चा कक्षा में कुशलता से जोड़-घटाव भले कर ले, जिंदगी में सुख को जोड़कर दुख को घटाने की कला नहीं जानता। उसे सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि यह किसी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है।

अगर शिक्षा सम्यक हो, तो कामों के साथ जो पद और प्रतिष्ठा जुड़ी है, वह विलीन हो जाएगी। एक आदमी जूते सीता है, एक रोटी बनाता है, एक ईंटें बनाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे लोग जिंदगी को मिल-जुलकर बना रहे हैं। जिंदगी में सब जरूरी है। इसमें ईंटें बनाने वाले लोग जरूरी हैं, इसमें सड़क साफ करने वाले लोग जरूरी हैं, इसमें एक मुल्क के हुकूमत करने वाले लोग जरूरी हैं और कोई किसी से कम नहीं है। सारे लोग मिलकर एक सहयोगी जिंदगी को पैदा कर रहे हैं।

भारतीय संस्कृति में उपनिषदों के गुरुकुल हुआ करते थे। ये हमारे प्राचीन विद्यालय थे। चूंकि वे ज्ञानी ऋषियों द्वारा चलाए जाते थे, शिक्षा की ओर देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कागजी शिक्षा को कभी महत्व नहीं दिया। एक उपनिषद की कहानी है, जिसे ओशो अक्सर सुनाते हैं- एक गुरुकुल से तीन युवक शिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे। उनकी सभी विषयों में परीक्षा ले ली गई थी। केवल 'धर्म' रह गया था। और वे हैरान थे कि धर्म की परीक्षा क्यों नहीं ली गई?

वे गुरुकुल से थोड़ी दूर ही गए होंगे कि सूरज ढलने लगा था और रात उतरने को थी। वे जिस पगडंडी से गुजर रहे थे, उस पर बहुत से कांटे पड़े थे। पहला युवक छलांग लगाकर कांटों की पार कर गया। दूसरा युवक पगडंडी छोड़ किनारे से निकलकर पार हो गया। लेकिन तीसरा वहीं रुक गया और उसने कांटों को चुनकर पास की झाड़ी में डाला और तब आगे बढ़ा। शेष दो ने उससे कहा कि यह क्या कर रहे हो, रात बढ़ रही है और हमें शीघ्र ही वन के पार हो जाना है। तीसरा युवक हंसा और बोला, इसीलिए कांटों को चुना कि रात उतरने को है और हमारे बाद जो भी इस राह पर आएगा, उसे ये कांटे दिखाई नहीं पड़ सकेंगे।

वे तीनों यह बात कर ही रहे थे कि उनके आचार्य झाड़ी के बाहर आ गए। वे झाड़ी में छिपे थे। उन्होंने तीसरे युवक को कहा- तुम धर्म की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। अन्य दोनों युवकों को लेकर वह गुरुकुल वापस लौट गए। उनकी धर्म की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी।

जो मात्र परीक्षाएं पास करके यह समझते हैं कि वे शिक्षित हो गए, वे भूल में हैं। वस्तुतः जहां परीक्षाएं समाप्त होती हैं, वहीं असली शिक्षा शुरू होती है, क्योंकि वहीं जीवन शुरू होता है।

जीवन की क्या परीक्षा है सिवाय जीवन के? और धर्म तो जीवन ही है। इसलिए जो मात्र परीक्षाएं पास करके यह समझते हैं कि वे शिक्षित हो गए, वे भूल में हैं। वस्तुतः जहां परीक्षाएं समाप्त होती हैं, वहीं असली शिक्षा शुरू होती है, क्योंकि वहीं जीवन शुरू होता है।

अमृत साधना

पोप लियो XIV | ईस्टर संदेश

जीवन में ठहरकर विचार करना, दैनंदिन की भागदौड़ को थामना, लोगों की जरूरतों व परेशानियों को देख द्रवित होना, उनकी मदद करना- यही हमें एक-दूसरे का पड़ोसी बनाता है, सच्चा भाईचारा पैदा करता है और नफरत की दीवारों को तोड़ता है।

लोभवश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते लोग

हमारी धरती अकूत प्राकृतिक संसाधनों से भरी पड़ी है। मगर इसके अकूत कहने का गर्व हम तब तक ही कर सकते हैं, जब तक हम इसकी सुरक्षा, संरक्षा और उचित दोहन को लेकर जागरूक रहते हैं। अपनी इस संपत्ति के प्रति हमारी सजगता घटी नहीं कि इसके लुप्त होने में देर नहीं लगेगी। हममें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति केवल सजगता की ही कमी नहीं है, बल्कि हम मनुष्यों का लोभ-लालच इतना बेकाबू हो चुका है कि अपनी विलासिता और अनावश्यक उपभोग के लिए अरबों वर्षों में निर्मित-संचित इस संपत्ति को अपने जीवनकाल में ही तबाह करने पर उतारू हो गए हैं। हम मनुष्य अपनी लालसा में यह भी ध्यान नहीं रख पाते हैं कि पृथ्वी ने इस संपत्ति को निर्मित-संचित कर रखा है, वह केवल हमारे लिए नहीं है। उसमें पृथ्वी के सभी चर-अचर जीवों और हमारी आने वाली असंख्य पीढ़ियों का भी हिस्सा है।

इसका वर्तमान द्वारा असीमित उपभोग असल में संहार की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। यहां हम महात्मा गांधी के प्रसिद्ध उद्धरण को प्रस्तुत करना चाहेंगे कि 'पृथ्वी के पास इतनी संपदा है कि वह सभी जीवों का भरण-पोषण कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के भी लोभ को नहीं मिटा सकती है।' हम प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की जगह न केवल इसका शोषण कर रहे, बल्कि इस शोषण के कारण प्रस्तुत संकट को झेलने के लिए भी अभिशप्त हैं। आज जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी धरती ही संकट में आ चुकी है। प्रकृति के साथ बेजा छेड़छाड़ करने का दुष्परिणाम ओजोन क्षरण के रूप में दुनिया को झेलना पड़ रहा है, जो अगर आगे भी जारी रहा, तो वर्तमान स्थिति में जीव-जंतु तो नहीं ही रह पाएंगे।

ऐसा नहीं है कि प्रकृति के संरक्षण को लेकर जागरूकता नहीं बढ़ी है। मगर इस दिशा में और सजगता बढ़ाने के लिए 28 जुलाई को दुनिया भर में 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' मनाया जाने लगा है। यह दिन हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा के महत्व की याद दिलाता है। यह एक आह्वान है, जो व्यक्तियों, समुदायों व सरकारों से हमारे ग्रह की भलाई सुनिश्चित करने वाली रीति-नीति की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का आग्रह करता है। हर किसी को हरित जीवनशैली अपनाने के लिए अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान, प्रोजेक्ट टाइगर, भविष्य के लिए मैंग्रोव (एमएफएफ) जैसे कुछ अभियान शुरू किए हैं, जो प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने वाले हैं। इनका उद्देश्य सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देकर खतरों को कम करना है।

राहुल रंजन शुक्ला, पौधशाला संचालक

अनुलोम-विलोम
प्रकृति संरक्षण दिवस

जरूरतों का भार प्रकृति को ही उठाना होगा

जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता की हानि, वनों की कटाई, प्रदूषण और जीवों के रहवास का विनाश जैसी बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। मगर इसके साथ ही प्रश्न उठता है कि आखिर धरती के जीव-जंतुओं को आहार और उपभोग के लिए जो वस्तुएं चाहिए, वे कहां से आएंगी? जहां तक प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और उसे बचाने की बात है, तो इसमें यह तथ्य भुला दिया जाता है कि आज दुनिया की आबादी आठ अरब के पार चली गई है। इसमें वृद्धि लगातार जारी है। इसके साथ ही उपभोग का स्तर हमने काफी बढ़ा लिया है, जो हमारी जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की प्रवृत्ति में यह विकास अनजाने में हो गया है। यह सब हमने जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने, मनुष्य को विकसित बनाने के नाम पर किया है। खान-पान, रहन-सहन, जीवन-दर्शन में भोग-विलास का ऐसा चस्का लगा है, जिसकी भरपायी के लिए हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर होना पड़ता है।

गौर कीजिए, दुनिया की आबादी जब आज की चौथाई नहीं थी, तब लोगों में अत्यधिक उपभोग की प्रवृत्ति भी नहीं थी। वह एक ऐसा कालखंड था, जब लोग 'रूखी सूखी खाइके ठंडा पानी पीव' के सिद्धांत पर चला करते थे। 1800 ईस्वी की शुरुआत में दुनिया की आबादी मात्र एक अरब थी।

ऐसे में, अब अगर प्रकृति के पास उपलब्ध संसाधनों का सहारा मनुष्य न ले, तो कहां जाए? इसे तो जैसे भी हो, जल-जंगल-जमीन से ही निकालना होगा। ऐसे में, यह उपदेश कि कुशल बहुतेरे' जैसा है। हां, इतना जरूर है कि यह दोहन जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो। फिर हम जितना संसाधन प्रकृति से लें, उसकी भरपायी भी करें। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने उपभोग के लिए जब वनों से पेड़ों की कटाई करें या खनिज पदार्थ का दोहन करें, तो उसकी प्रतिपूर्ति के तौर पर उसी जगह पर या अन्य स्थानों पर उतनी संख्या में पौधरोपण की जिम्मेदारी उठा लें और खनिजों के भी संरक्षण का ध्यान रखें, न कि उन्हें लापरवाही से अनदेखा कर दें। हमारे पास अभी जितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनको आगे के लिए बचाकर जरूर रखना होगा, लेकिन जरूरत के मुताबिक उसे खर्च भी करना पड़ेगा।

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके हम मानवता और पर्यावरण के बीच एक लचीला और सामंजस्यपूर्ण संबंध अवश्य बना सकते हैं।

अभिज्ञान नारायण, टिप्पणीकार

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 28-07-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH10 User: dilip.lal Time: 07-27-2025 22:32 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 28 जुलाई 2025

एक और भगदड़

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में एक अफवाह ने कई जानें ले लीं। किसी धार्मिक स्थल पर भगदड़ की यह पहली घटना नहीं, लेकिन अफसोस है कि पुरानी गलतियों से सबक नहीं लिया जा रहा।

एक साल में कई हादसे । पिछले एक साल पर नजर दौड़ाएं तो इस तरह के कई दुखद हादसे हो चुके हैं। पिछले साल जुलाई में ही हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। वहां आयोजक भीड़ को नहीं संभाल पाए। इस साल

मनसा देवी में हादसा

जनवरी की शुरुआत में तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के लिए हद से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए और पुलिस उनको काबू नहीं कर सकी। भगदड़ मची तो 6 लोगों की जान चली गई। इसी साल, मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में और उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हादसा हुआ।

क्राउड मैनेजमेंट । धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। अनुमान से ज्यादा लोग जब एक जगह जुट जाते हैं, तब हल्की-सी भी चूक जानलेवा बन सकती है। इन सारे मामलों में यही वजह रही - कोई अफवाह, भीड़ का अनियंत्रित हो जाना और निकलने की जगह न मिलना। किसी भी बड़े आयोजन का सबसे अहम हिस्सा है क्राउड मैनेजमेंट। जरूरी नहीं है कि भीड़ के बारे में लगाया गया अनुमान हमेशा सही साबित हो। ऐसे में रियल टाइम मॉनिटरिंग अहम हो जाती है, जिससे स्थिति के हिसाब से तुरंत निर्णय लिया जा सके।

धार्मिक स्थलों पर अव्यवस्था । इस तरह की कोई दुर्घटना होने की सूरत में बचाव की योजना पहले से तैयार रहनी चाहिए। लेकिन, देखा गया है कि ज्यादातर मौकों पर पहले से की गई प्लानिंग बेकार हो गई, क्योंकि इंतजाम नाकाफी थे। तमाम धार्मिक स्थलों पर फैली अव्यवस्था को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिसलन भरे रास्ते, संकरी जगह, आने-जाने का एक ही मार्ग जैसी बातें लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ऐसे में जब किसी खास मौके पर भीड़ बढ़ती है तो स्वाभाविक ही हादसे की आशंका भी बढ़ जाती है, जैसा सावन पर मनसा देवी में हुआ।

समन्वय और जागरूकता । बेंगलुरु में RCB के इवेंट में हुए हादसे के बाद कर्नाटक सरकार क्राउड कंट्रोल पर एक बिल लेकर आई है, जिसमें जिम्मेदारियां तय की गई हैं। ऐसे कानून की हर जगह जरूरत है। साथ ही, ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए आयोजकों, पुलिस-प्रशासन और जनता को समन्वय में काम करना होगा। बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता की जरूरत है, जिससे लोगों को बताया जा सके कि भीड़ के बीच उन्हें किस तरह का व्यवहार करना है।

आजकल

शतरंज का स्वर्ण युग

प्रशांत अस्थाना

पिछले महीने एक विडियो काफी वायरल हुआ। जब नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन भारत के डी. गुकेश से हार गए, तो उन्होंने गुस्से में शतरंज की बिसात पर मुक्का मार दिया। गुकेश की प्रतिक्रिया भी लाजवाब थी। 10 सेकंड का यह विडियो शतरंज में भारत की नई बादशाहत का प्रतीक बन गया। पिछले कुछ सालों में भारत में शतरंज की एक क्रांति सी आ गई है। भारत की दिव्या देशमुख और कोनेरू हंपी के बीच जॉर्जिया में वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाना है। मतलब साफ है, चेस की दुनिया में भारत ने बेमिसाल कामयाबी हासिल कर ली है। यह भारत के गली-मोहल्लों, गांवों और डिजिटल दुनिया तक फैली एक मौन क्रांति है। इसकी शुरुआत की थी विश्वनाथन आनंद ने। 2000 के दशक में विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने देशभर में एक विचार की नींव रख दी कि शतरंज हमारे डीएनए में है। आज भारत के पास सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि दर्जनों विश्वस्तरीय ग्रैंडमास्टर्स हैं। प्रग्नानंदा ने जब मैग्नस कार्लसन को मात दी, पूरी दुनिया ने भारत के भविष्य को महसूस किया। गुकेश, निहाल सरीन, आर अर्जुन, लियोन मेंडोंका, आर वैशाली जैसे नाम हर बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

कोविड-19 के दौरान जब हर खेल थम गया था, तब Chess.com, Lichess, YouTube और ChessBase India जैसे माध्यमों ने गांवों तक यह खेल पहुंचा दिया। चैंपियन गुकेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि कोविड पीरियड ने हमें अपना गेम मजबूत बनाने का टाइम दिया था। आज भारत से हर महीने हजारों नए खिलाड़ी ऑनलाइन टूर्नामेंट्स में भाग ले रहे हैं। भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना और राज्यों की खेल नीतियों ने चेस को जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। निजी एकेडमीज, जैसे WestBridge Anand Chess Academy, Velammal Academy और ChessBase India Foundation देश भर में बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत में शतरंज की यह लहर किसी क्षणिक उत्साह का परिणाम नहीं, बल्कि लंबी सोच, सांस्कृतिक जुड़ाव और सामूहिक प्रयास की उपज है। आज हम न केवल चैंपियन बना रहे हैं, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो विचारों से दुनिया को दिशा दे सकती है। शतरंज ही वह शक्ति है जो हमें दुनिया की बौद्धिक महाशक्ति बनाने की ओर ले जा रही है।

एकदा

गोखले की आत्मनिर्भरता

तब देश में आजादी की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। एक बालक अपने माता-पिता से दूर शहर के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। आमदनी कम थी और खाने वाले ज्यादा। किसी तरह परिवार वाले उसे हर महीने 8 रुपये पढ़ाई और अन्य खर्च के लिए भेजा करते थे। वह बालक इस बात को

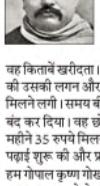

अच्छी तरह समझता था। माता-पिता के आर्थिक संकट से उसे बहुत कष्ट पहुंचता। उसे घर से रुपये लेना अच्छा नहीं लगता था। उसने खर्च में कटौती करने की सोची। इसके लिए वह दिन में केवल एक बार भोजन करने लगा। रात में वह स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। इस तरह वह घर से भेजे गए 8 रुपयों से भी बचत करने लगा। इस बचत से वह किताबें खरीदता। धीरे-धीरे उस बच्चे की मेहनत रंग लाई। पढ़ाई की उसकी लगन और अनुशासन के कारण उसे कॉलेज से छात्रवृत्ति मिलने लगी। समय बीतता गया। उसने घर से आर्थिक सहायता लेना बंद कर दिया। वह छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा। इससे उसे हर महीने 35 रुपये मिलने लगे। अपनी इसी कमाई से उसने कानून की पढ़ाई शुरू की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उस बच्चे को आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से जानते हैं, जिन्हें महात्मा गांधी भी अपना गुरु मानते थे।

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

मोदी सरकार ने धैर्य और कौशल का परिचय देते हुए पड़ोसी देश को ज़मीनी हक़ीक़त का अहसास कराया

दुश्मन से फिर दोस्त कैसे बना मालदीव

रंजीत कुमार

केरल के समुद्र तट से करीब 500 किमी दूर स्थित महज पांच लाख आबादी वाले छोटे से द्वीप देश मालदीव से रिश्ते भारत के लिए सामरिक अहमियत रखते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव का दौरा छह साल बाद ही मुमकिन हुआ तो इसलिए कि वहां चीन और पाकिस्तान दूके प्रयासों से जिस तरह का भारत विरोधी माहौल बन गया था, उसे बेअसर करने में थोड़ा वक्त लगा।

पहले जैसे रिश्ते । 24 से 26 जुलाई के बीच हुए इस दौरे में मोदी ने मालदीव के लोगों का दिल जीतने के लिए उन्हें ढेर सारी वित्तीय सौगातें दीं है। माले हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू खुद मौजूद थे। उन्होंने मालदीव की आजादी की 60वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में मोदी को मानद अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर भारत के साथ रिश्तों का पुराना स्तर बहाल करने का भी संकेत दिया।

चीन की नजर । जब से हिंद महासागर के प्रमुख व्यापारिक मार्ग के नजदीक स्थित इस द्वीप देश पर चीन की नजर पड़ी है, तब से भारत और मालदीव के रिश्तों पर आंच पड़ने लगी। हाल के दशकों में चीन और पाकिस्तान की तरफ से मालदीव की राजनीति में दखल देने और वहां अपने अनुकूल सरकार बनवाने की कोशिशें चलती रही हैं। लेकिन जब मालदीव के समुद्री इलाके में अपनी मौजूदगी बनाने के इरादे से चीन ने उसका एक द्वीप लीज पर ले लिया, तब स्वाभाविक ही भारत की चिंता बढ़ गई। इस द्वीप के बहाने चीन न केवल अपने नौसैनिक पोत मालदीव भेजने लगा था बल्कि उनकी स्थायी तैनाती की भी मंशा रखता था। भारत स्वाभाविक ही इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकता था।

भारत विरोधी रुख । मालदीव के समुद्री इलाके की चौकसी के लिए वहां के कोस्ट गार्ड के साथ सहयोग का रिश्ता तो भारत ने बनाया ही था, वहां के एक द्वीप पर अपना रेडार केंद्र भी स्थापित किया था। लेकिन राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने देश की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक को तैनात न करने देने की बात कही। यहां तक कि मालदीव को भेंट में दिए गए टोही हेलिकॉप्टर की देखरेख के लिए तैनात भारतीय तकनीशियनों को भी मालदीव छोड़ने का आदेश सुना दिया।

भारत की सख्ती । मालदीव के इस अपमानजनक कदम के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप जाकर मालदीव जाने वाले पर्यटकों को भारतीय द्वीपों की सैर करने की सलाह दी। मालदीव के भारत विरोधी रवैये के जवाब में भारतीय पर्यटकों ने वहां की यात्रा रद्द करनी शुरू की, तो पर्यटन से होने वाली मालदीव की आमदनी प्रभावित होने लगी। मालदीव के लोगों के भारत आने पर भी कई तरह के अघोषित प्रतिबंध लगा दिए गए।

ऑपरेशन कैक्टस । भारत के साथ सहयोग के रिश्तों के बिना मालदीव चीन और पाकिस्तान के बल पर अधिक वक्त तक नहीं टिक सकता। यही वजह है कि आज से करीब चार दशक पहले 1988 में जब राष्ट्रपति अब्दुल गयूम की सत्ता पलटने के लिए कुछ विद्रोही माले पर उतरे तो तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम ने भारत से ही मदद की गुहार लगाई थी। राजीव गांधी की अगुआई वाली तत्कालीन सरकार ने अब्दुल गयूम की सत्ता को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान से माले फौज भेजी थी।

कूटनीतिक रस्साकशी

- मालदीव में बन गया था भारत विरोधी माहौल
- चीन-पाक की दखलंदाजी का था परिणाम
- मुइज्जू को हुआ अहसास, भारत जैसा कोई नहीं

धार्मिक भावनाएं । तब से लेकर आज तक भारत-मालदीव रिश्तों में काफी उतार-चढ़ाव आए। ये उतार-चढ़ाव अनायास नहीं थे। भारत के साथ रिश्तों को प्रभावित करने के लिए ही मालदीव की पांच लाख सुन्नी मुस्लिम आबादी की धार्मिक भावनाएं भड़काकर उन्हें भारत विरोधी कोशिशों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की रही है।

चीनी कर्ज । बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी के मालदीव दौरे में ढांचागत विकास के लिए जो समझौते किए गए हैं, उसके तहत उसे करीब 4850 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देने का ऐलान हुआ है। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। सबसे अहम यह है कि भारतीय वित्तीय मदद से मालदीव पर चीन के कर्ज बोझ को हलका करने में भी मदद मिलेगी। चीन का मालदीव पर एक अरब डॉलर से अधिक का कर्ज है। चीन और अन्य देशों को मालदीव सालाना 5.1 करोड़ डॉलर का भुगतान करता था। भारत की मदद के कारण अब यह राशि घटकर केवल 2.9 करोड़ डॉलर रह जाएगी। इस तरह मालदीव को चीन पर अपनी निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी।

रिश्तों में नई उम्मीद । प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के बाद अब यह उम्मीद बनी है कि मालदीव की राजनीति को प्रभावित करने की चीन की चालों को मालदीव के नेता समझेंगे। वास्तव में मुइज्जू को चीन के प्रभाव से दूर कर पड़ोसी देश से पुराना रिश्ता बहाल करने के लिए भारत ने अभूतपूर्व धैर्य और कूटनीतिक कौशल का परिचय दिया है। तभी चीन समर्थक माने जानेवाले राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत के साथ न केवल रक्षा सहयोग के रिश्तों को बहाल करने का संकेत दिया बल्कि यह भरोसा भी दिया है कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत के सुरक्षा हितों पर किसी तरह की आंच आने का खतरा हो।

(लेखक सामरिक मामलों के जानकार हैं)

हमारे सफ़र को पूरा करने में क़ुर्बान हो जाते हैं जूते

AI image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

एक द्वीप पर दो कंपनियों के सेल्समैन पहुंचे। एक ने देखा कि द्वीप पर लोग नंगे पैर रहते हैं। उसे निराशा हुई। तुरंत कंपनी में फोन कर दिया, 'यहां सब नंगे पैर हैं। कोई उम्मीद नहीं, वापस आ रहा।' दूसरे की नजर जब उन्हीं स्थानीय लोगों पर पड़ी तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने कंपनी में फोन कर कहा, 'बड़े जहाज से माल भेजो। यहां सब नंगे पैर हैं। खूब बिक्री होगी।' दोनों कंपनियां जूते की थीं। यह कहानी है सिक्के के उस पहलू को देखने की, जो उम्मीद और सकारात्मकता से भरा है। साथ ही, यह कहानी है जूतों की भी। पहनावे में सबसे आखिर में आते हैं जूते, पर इनके बिना पहनावा पूरा नहीं होता। ड्रेस कितनी भी अच्छी हो और पर्सनैलिटी कितनी भी शानदार, उसे पूर्णता जूता ही देता है। कहते भी हैं कि किसी इंसान के बारे में उसके जूतों को देखकर बहुत कुछ जाना जा सकता है।

जूतों ने सभ्यता के हर कदम पर इंसानों का साथ निभाया। जानवरों के चमड़े और पेड़ों के रेशों से लेकर सोने-चांदी के नुमाइशी मॉडल तक - बहुत कुछ बदला, पर इनकी जगह नहीं। ओप्रा विन्फ्रे का कहना है कि उनके पैर अभी तक जमीन पर हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छे जूते पहनती हैं। बिल्कुल यही बात है जूतों के साथ भी। उन्होंने सिखाया है कि सफलता कभी सिर चढ़कर नहीं बोलनी चाहिए। जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ज्यादा जल्दी रास्ते पर गिरा सकती है।

जूते बताते हैं कि जब मौका हो तब सही चुनाव कितना जरूरी है। कितना भी महंगा हो और कितना भी अच्छा, पर अगर खरीदते समय चूक हुई, तो जूता चाल बिगाड़ देता है। हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वह अपनी तरफ से अडजस्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ बातें अगर शुरू से गलत हो जाएं तो हमेशा गलत ही रहती हैं, जब तक कि उनकी फिर से शुरुआत न की जाए।

जूतों से प्यार जताया जाता है और ये विरोध व्यक्त करने का तरीका भी हैं। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने जिन जूतों को पहना था, वे आज भी करोड़ों में बिकते हैं। उनके नाम से जुड़कर एक नया ब्रैंड ही बन गया - एयर जॉर्डन और इसने Nike को स्नीकर्स मार्केट में टॉप पर पहुंचा दिया। भारत में शादी अधूरी मानी जाती है 'जूता चुराई' की रस्म बिना।

हालांकि जूते जब तक पैरों के साथ चलें, तभी तक बेहतर - इनका अकेला चलना यानी भारी मुसीबत। दिसंबर 2008 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर एक जर्नलिस्ट ने जूता ही तो फेंका था, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। न्यू यॉर्क म्यूजियम ने जूते की रॉल्फला के रूप में उस नफरत को अभी तक सहेज रखा है। पिछले साल ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने वहीं की जनता के बीच फेमस ब्रैंड के जूते क्या पहन लिया, निशाने पर आ गए। लोग खफा थे सुनक से। हां, जूतों ने बिल्कुल बुरा नहीं माना!

जूतों की जगह होती है घर के बाहर, एक कोने में। लेकिन, इन्हें चर्चाओं में जगह बनाना भी आता है। हमसे ज्यादा हमारे रास्तों को जानते हैं ये। चलते हम हैं और घिसते ये हैं, मंजिलें हमें मिलती हैं और सफर इनका खत्म होता है। फिर भी इनको शिकायत नहीं - ये उदाहरण हैं कि आनंद दूसरों के लिए जीने में भी है।

शेयर करें अपना अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, भेजिए इस मेल आईडी पर **nbtreader@timesofindia .com** और सब्जेक्ट में लिखें **'जीवन आनंद'**

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

शिव से लय साध लें तो मन बन जाएगा शिवालय

ब्रह्मा कुमारी शुक्ला

शिव उपासना के लिए विशेष माना गया है, लेकिन श्रावण मास के सोमवारों का आध्यात्मिक महत्व और भी अधिक होता है। वास्तव में जीवन का प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, और हमारी हर श्वास ईश्वर की अनमोल देन है। इस अमूल्य जीवन को सार्थक बनाना या व्यर्थ करना हमारी सोच, समझ, शिक्षा और संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे मानव जीवन को दुर्लभ कहा गया है, वैसे ही हमारे पास उपलब्ध प्रत्येक वस्तु भी ईश्वर की अमानत है।

सोमवार का दिन भगवान शिव के अनेक दिव्य कार्यों की स्मृति का प्रतीक है। 'सोम' शब्द का संबंध चंद्रदेव से है। यह भगवान शिव के 'वैद्यनाथ' स्वरूप से भी जुड़ा है, जो रोगों के नाशक हैं। साथ ही यह 'अमरनाथ' महादेव की उस अमर कथा की भी याद दिलाता है, जिसमें यह देवी पार्वती को ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं। यही ईश्वरीय ज्ञान आत्मा को विकारों से मुक्त कर देवतुल्य बनने की शक्ति प्रदान करता है।

श्रावण के सोमवार स्मरण कराते हैं कि हमें अपने दोष, दुर्गुण और विकारों का परमात्मा को दान करना है। ये ही हमारे जीवन में दुख और पतन का कारण हैं। ईश्वर की स्मृति में रहकर हमें अपने अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और वासनात्मक भावनाओं को सदा के लिए समर्पित करना है। यही आत्मिक शुद्धिकरण का मार्ग है, जिससे हम देहाभिमान और सांसारिक मोह से ऊपर उठ सकते हैं।

उपलब्धियों का गर्व ही समस्त विकारों और व्यसनों की जड़ है। इसे समाप्त करने की शक्ति केवल शिव में है, जिनका शाश्वत स्वरूप परम ज्योतिर्लिंग, यानी दिव्य प्रकाश बिंदु है। वही शिव, निराकार परमात्मा, सृष्टि कल्याण के लिए कल्पांत पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से अवतरित होते हैं। वह आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा के माध्यम से नई, सुखद और पवित्र सतयुगी दुनिया का मार्ग दिखाते हैं।

राजयोग और आत्म-चिंतन का नियमित अभ्यास हमें परमात्मा शिव से जोड़ता है, जिससे हम उनके दिव्य गुणों शांति, पवित्रता, करुणा, तप, त्याग और सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं। जब हम शिव की स्मृति में स्थित होकर जीते हैं, तो हमारी सोच, दृष्टि, और कर्म सकारात्मक और सात्त्विक हो जाते हैं। धीरे-धीरे हमारे पुराने दुर्गुण विलीन हो जाते हैं और हम एक श्रेष्ठ, शांत, और आनंदमय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। यही शिव के साथ लय बैठाना है।

यह साधना, आत्मविकास और शिव की लय में जीने की एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई एक दिन या एक महीने का कर्मकांड नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा है, जिसमें हम अपनी बुराइयों को त्यागकर शुभ चिंतन, शिव संकल्प और आत्मिक शक्ति द्वारा परमात्मा के समान बन जाते हैं।

NEP के कामयाब पांच साल

डॉ. विनीत जोशी

29 जुलाई, 2020 को भारत ने न केवल एक नई नीति की शुरुआत की, बल्कि एक नए भारत की कल्पना करने का साहस भी दिखाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 एक सामान्य सुधार नहीं, बल्कि ऐतिहासिक क्षण था। यह नीति हमारे आत्मबोध, हमारी आकांक्षाओं और उस शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना की अभिव्यक्ति है जो हमें भविष्य की ओर ले जाएगी।

अंकों से अर्थ की ओर । NEP 2020 भारत में अब तक की सबसे व्यापक परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें देशभर से दो लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य पुरानी चीजों को केवल संवारना नहीं था, बल्कि सोच में परिवर्तन लाकर शिक्षा को रटंत से समझ की ओर, अंकों से अर्थ की ओर ले जाना था। और, सबसे जरूरी बात, इसे परीक्षा-आधारित दौड़ से हटकर उद्देश्य-आधारित यात्रा का रूप देना था।

जीवन के अनुरूप । सिर्फ पांच वर्षों में यह दूरदर्शी दस्तावेज एक जीवंत आंदोलन बन चुका है। यह केवल सरकार द्वारा संचालित नहीं, बल्कि शिक्षक, संस्थान, अभिभावक, छात्र और समुदाय - सभी की भागीदारी से संचालित हो रहा है। हमने स्कूली शिक्षा के ढांचे को 5+3+3+4 में दोबारा परिकल्पित किया है, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, खेल-आधारित शिक्षा और मूलभूत साक्षरता पर विशेष बल दिया गया है।

सीधी छाप । NEP की सबसे प्रभावशाली उपलब्धि इसकी आम जनजीवन में पड़ने वाली सीधी छाप है। हमारा सकल नामांकन अनुपात (GER) 26.3% से बढ़कर 30% से अधिक हो गया है। पिछले छह वर्षों से महिलाओं का GER पुरुषों से अधिक रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों में

AI image

कॉमन रूम

नामांकन निरंतर बढ़ रहा है।

बुनियादी संरचना । हमारा शोध भी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पीएचडी नामांकन दोगुना हो चुका है, शोध प्रकाशनों में 142% की वृद्धि हुई है और आज भारत वैश्विक शोध में तीसरे स्थान पर है।

भाषा का उत्सव । NCRF, NHEQF और CCFUP जैसे तंत्र छात्रों को शैक्षणिक, व्यावसायिक और कौशल के क्षेत्रों में निर्बाध रूप से आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। दोहरी डिग्री और 45 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी ने स्टूडेंट्स के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। पहली बार, CUET, NEET और JEE जैसी परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। यही नहीं, अनुवादिनी, ई-कुंभ और अस्मिता जैसी पहलें बहुभाषावाद का उत्सव मना रही हैं।

परंपरा बनी ताकत । पांच वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है कि NEP 2020 एक पीढ़ीगत बदलाव है। यह दुनिया को यह दिखाता है कि हमारे दिलों में बसी परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अपने साथ केवल उपलब्धियों का गौरव नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य को बेहतर बनाने का संकल्प भी लेकर चल रहे हैं।

(लेखक उच्च शिक्षा के सचिव हैं)

इनकार नहीं, सुधार

प्रणव प्रियदर्शी

आज की पढ़ी-लिखी ऐंबिशस और वर्किंग गर्ल्स में शादी को लेकर वैसा क्रेज नहीं दिखता जैसा एकाध दशक पहले तक था। शादी से सीधे-सीधे इनकार न करने वाली लड़कियां भी इसे अधिक से अधिक टालने की कोशिश करती दिखती हैं। आंकड़े भी इस प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। 2022 में नैशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की ओर से आई 'यूथ इन इंडिया' रिपोर्ट के मुताबिक देश की युवा आबादी का 23% हिस्सा ऐसा था, जिसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मॉर्गन स्टेनली के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 2030 तक 25 से 44 साल की महिलाओं का 45% हिस्सा चाइल्डलेस और सिंगल होगा। यह ट्रेंड भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी दिख रहा है। ब्रिटेन में 2023 में अविवाहितों की संख्या 58 लाख पाई गई, जो 1991 के मुकाबले दोगुना थी। साउथ कोरिया में तो 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 30 से 39 साल की उम्र की आबादी का 51% हिस्सा अविवाहित था। हालांकि अलग-अलग देशों में इसके पीछे अलग-अलग कारकों की भूमिका हो सकती है। जहां तक अपने देश की बात है, तो एजुकेटेड, वर्किंग लड़कियों में शादी से बेरुखी के पीछे एक बड़ी भूमिका अपनी आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता खोने के डर की दिखती है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद परिवार में रिश्तों का समीकरण जेंडर जस्टिस और बराबरी की भावना पर आधारित नहीं होता। हालांकि लाइफस्टाइल कोच और अन्य एक्सपर्ट्स ही नहीं डेटिंग ऐप्स से जुड़े आंकड़े भी बताते हैं कि युवाओं की शादी से बेरुखी का मतलब रिश्तों या कंपैनियनशिप से बेरुखी नहीं है। डेटिंग, रिलेशनशिप और लिव-इन जैसे विकल्पों को आजमाने का चलन बढ़ रहा है। जाहिर है, ऐसे में यह निष्कर्ष जल्दबाजी भरा हो सकता है कि देश की युवा पीढ़ी शादी से मुंह फेर रही है। यह कहना ज्यादा सटीक होगा कि वह शादी के बाद बनने वाले रिश्तों को ज्यादा समतामूलक, ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने की कोशिश कर रही है।

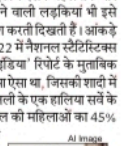

AI image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ **चिट्ठी में भावनाएं**

यह पत्र जीवन आनंद कॉलम में 21 जुलाई के लेख 'चिट्ठी आज भी लाती है खुशियों का संदेश' से संबंधित है। आज के डिजिटल युग में मात्र एक क्लिक से

जीवन आनंद

दूसरे के पास संदेश भले ही भेज दिया जाता हो, लेकिन भावनाएं आज भी हाथ से लिखे पत्रों में ही नजर आती हैं। पत्र में लिखे शब्दों की बनावट से लिखने वाले की भावना भी मिली रहती है। यही कारण है कि आज भी डाक व्यवस्था का महत्व है। कई लोग आज भी पत्रों के माध्यम से अपनी भावनाएं अपनों तक पहुंचा रहे हैं। आज भी डाकिए का घर आकर पत्र देना, खुशी देता है। आज भी रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी डाक के माध्यम से ही भेजती हैं।

पैथर तोमर, किशन गंज

■ **भारत की अहमियत**

26 जुलाई का संपादकीय 'इसमें US का घाटा' पढ़ा। डॉनल्ड ट्रंप का 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' अभियान अगर प्रतिभा और वैश्विक सहयोग के खिलाफ जाता है, तो वह उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा। अमेरिकी टेक इंडस्ट्री की सफलता में भारतीयों समेत प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। किसी देश में समृद्धि केवल संरक्षणवाद से नहीं आती, उसके लिए कुशल प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी भी जरूरी है। भारत जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। यहां सस्ता मानव संसाधन उपलब्ध है, जो अमेरिकी कंपनियों के लिए लाभकारी है। ट्रंप की सोच अमेरिका को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे कर सकती है। यदि वह भारत जैसे साझेदारों को दूर करता है, तो न केवल उसकी आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी, उसकी बढ़त भी खतरे में पड़ सकती है।

सुधा श्रीवास्तव, नोएडा

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बिहार में कानून व्यवस्था पर भिड़े केंद्र के दो मंत्री - एक खबर

- यह भिड़ंत तो चुनावी लगती है।

रोहित सैनी

[illegible]

चिंतन

इजरायल का फैसला मानवता के हित में

आखिरकार संयुक्त राष्ट्र के दबाव में इजरायल ने गाजा पट्टी के तीन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए लड़ाई रोकने का ऐलान किया है। मानवीय सहायता की दिशा में यह अहम कदम है। इजरायल ने यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ती भुखमरी की चिंताओं को देखते हुए उठाया है। भारत, यूएन, अमेरिका, चीन आदि देश इजरायल से शांति की अपील लगातार कर रहे हैं। लेकिन इजरायल का प्रण वैश्विक आतंकी गुट हमास के खात्मे तक सैन्य एक्शन जारी रखने का है। पिछले 21 महीने से इजरायल की सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है। इस दौरान गाजा के हालात बद से बदतर होते गए हैं। हमास के आतंकी कुकृत्य के अंजाम गाजापट्टी के निर्दोष नागरिक व बच्चे भुगत रहे हैं। इजरायल की एक ही मांग है कि यदि हमास आत्मसमर्पण कर दे और क्षेत्र को छोड़ दे, तो वह युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। हमास ने हजारयल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साफ है कि जंग रुकने के आसार निकट भविष्य में नहीं हैं। ऐसे में गाजापट्टी में आमलोगों के हालात खराब ही होते जा रहे हैं। जंग जारी रखने के चलते इजरायल को अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है, हालांकि इजरायली सेना का तर्क है कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ग्लोबल आतंकी गुट हमास ने इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को पैफानिक मना रहे निहत्थे व बेकसूर नागरिकों पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 1200 लोग शिकार हुए थे। उसके बाद से इजरायल व हमास के बीच लड़ाई जारी है, जिसमें करीब 15 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। खाद्य विशेषज्ञ महीनों से गाजा में भुखमरी के खतरे की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि इजरायल ने सहायता पर रोक लगा दी थी। हाल के दिनों में गाजा से कमजोर बच्चों की तस्वीरें सामने आई थीं, जिसके बाद इजरायल की वैश्विक आलोचना तेज हो गई। अब इजरायल की सेना के मुताबिक, वह गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित मार्ग बनाएगी जिसमें आटा, चीनी और डिब्बाबंद खाद्य सामग्री शामिल है। गाजा युद्ध से उत्पन्न मानवीय त्रासदी को झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने सहायता प्रतिबंधों में ढील देने के इजरायली कदमों का स्वागत किया है, लेकिन कहा कि गाजा में जरूरतमंद सभी लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए व्यापक युद्धविराम की आवश्यकता है। इजराइल ने स्पष्ट किया है कि वह इन तीन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में हमास के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 9 लाख बच्चे भूखे हैं और 70 हजार से ज्यादा बच्चे पहले से ही कुपोषण के लक्षण दिखा रहे हैं। गाजा में 127 लोग भुखमरी और कुपोषण के कारण मर चुके हैं। बहुत से बच्चे भूख से बिलखा रहे हैं, महिलाएं अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते देखने के लिए मजबूर हैं, तो आतंकी गुट हमास के आकाओं से पूछा जाना चाहिए कि गाजा के लोगों को इस हालात में किसलिए और क्यों पहुंचाया? इजरायल के बेकसूरों को मौत के घाट क्यों उतारा? क्या सांस्कृतिक विचारधारा और कट्टर धार्मिकता का युद्ध आम आदमी की हत्या कर लड़ा जाएगा? इजरायल की लड़ाई हमास से है, इसलिए उसे गाजा के आम नागरिकों को जरा भी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। हमास, हिज्बुल्ला, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, आल शबाब, हूती, लश्कर, जैश, टीटीपी, तालिबान जैसे आतंकी गुटों को कट्टरता, रसद, धन और हथियार देने वाले मानवता के इनसे बड़े दुश्मन हैं। भारत गाजा में शांति का पक्षधर है।

थाईलैंड-कंबोडिया के संघर्ष खत्म हों

युद्ध
राजेश जैन

कंबोडिया और थाईलैंड खतरनाक सीमा संघर्ष में उलझ गए हैं। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इस बार भी विवाद की जड़ वही पुरानी है, प्रीह विहेयर मंदिर। हजारों साल पुराना यह मंदिर खमेर साम्राज्य की धरोहर है, लेकिन इस पर मालिकाना दावा थाईलैंड और कंबोडिया दोनों करते हैं। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसे कंबोडिया का हिस्सा माना था, पर थाईलैंड ने यह फैसला पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। इसलिए सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका अहम हो सकती है। अगर चीन इस संघर्ष में 'शांति-निर्माता' बनकर उभरता है, तो वह दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका की साख को और कमजोर करेगा और भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी असर डालेगा।

दक्षिण-पूर्व एशिया एक बार फिर अशांत है। कंबोडिया और थाईलैंड खतरनाक सीमा संघर्ष में उलझ गए हैं। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इस बार भी विवाद की जड़ वही पुरानी है, प्रीह विहेयर मंदिर। हजारों साल पुराना यह मंदिर खमेर साम्राज्य की धरोहर है, लेकिन इस पर मालिकाना दावा थाईलैंड और कंबोडिया दोनों करते हैं। 1962 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने इसे कंबोडिया का हिस्सा माना था, पर थाईलैंड ने यह फैसला पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वैसे भी 817 किलोमीटर लंबी थाई-कंबोडिया सीमा पर दशकों से विवाद चला आ रहा है। इसकी जड़ें फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल के नक्शों में हैं। 1907 में बने नक्शों को थाईलैंड अब भी विवादित मानता है। कंबोडिया का कहना है कि प्रीह विहेयर और ता मुएन थोम जैसे ऐतिहासिक मंदिर उसके क्षेत्र में आते हैं, वहीं थाईलैंड इन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत मानता है। 2008 से 2011 के बीच इसी विवाद पर हुई झड़पों में 34 लोगों की मौत हो गई थी। 2025 की चिंगारी तब भड़की जब एक कंबोडियाई सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 24 जुलाई को हालात और बिगड़ गए जब ता मुएन थोम मंदिर के पास भारी गोलीबारी और हवाई हमले हुए। अब, जब व्यक्तिगत कटुता, राजनीतिक अस्थिरता और ऐतिहासिक विवाद आपस में गुत्थमगुत्था हो चुके हैं, दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक और गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

यह सैन्य लड़ाई दो राजवंशों के बीच की अदावत का विस्तार भी है। यह सीमा विवाद से लेकर दो राजवंशों के बीच की रंजिश की लड़ाई है। जुलाई की पहली तारीख को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतौंगतार्न शिनावात्रा को कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन को टेलीफोन किया था। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पैतौंगतार्न ने कंबोडियाई नेता को 'अंकल' कहकर संबोधित किया था। उस टेलीफोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग को हुन सेन ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, जिसमें पैतौंगतार्न उन्हें अंकल कहकर संबोधित कर रहीं थी और उनके बातचीत के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बातचीत को भावनात्मक बनाकर विवाद सुलझाना चाहती थीं। इस दौरान उन्होंने थाईलैंड सेना को भी नजरअंदाज किया, लेकिन ऑडियो फेसबुक पर आते ही बवाल मच गया। प्रधानमंत्री पैतौंगतार्न को इस्तीफा देना पड़ा और उनके पिता थाकसिन शिनवात्रा ने सार्वजनिक तौर पर कंबोडियाई नेता हुन सेन से संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया। थाकसिन और हुन सेन, अपने-अपने देश के दिग्गज नेता रहे हैं और उनके बच्चे भी एक ही साल के अंतराल में देश की सत्ता में पहुंच गये। एक वक्त था जब थाईलैंड के थाकसिन और कंबोडिया के हुन सेन की दोस्ती काफी मशहूर थी। माना जाता था कि दोनों देशों के बीच विवाद के बावजूद दोनों की दोस्ती की वजह से लड़ाई नहीं होगी और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहेगी।लेकिन ऑडियो लीक होने के बाद सबकुछ बदल गया। दोनों नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगले। थाकसिन ने कहा कि वो थाईलैंड सेना को हुन सेन को सबक सिखाने का मौका देना चाहते हैं। जिसपर हुन सेन ने उनके बयान को 'युद्ध की आग भड़काने' वाला बताया। हुन सेन, थाईलैंड की राजनीति में चल रही अस्थिरता का लाभ उठाकर अपने बेटे और

वर्तमान प्रधानमंत्री हुन मानेट की राष्ट्रवादी छवि को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं थाकसिन के खिलाफ राजद्रोह का मामला चल रहा है, जिसने उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर दिया है। उनका 2023 में स्वदेश लौटना और मिलिटरी-रॉयल गठजोड़ से समझौता करना भी उनके पारंपरिक समर्थकों में नाराजगी की वजह बना है।थाईलैंड के पूर्व विदेश मंत्री कासित पिरोम्या ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक रिपोर्ट में कहा कि दोनों परिवारों की आकांक्षाएं और धन-संपत्ति का सपना साकार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हुन सेन शायद इसे थाकसिन की नाकामी मानते थे। हुन सेन अपने देश पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे और वे अपने वादे को पूरा कर सकते थे, लेकिन थाकसिन पिछले 20 वर्षों से थाई समाज पर अपनी चमक और नियंत्रण खोते जा रहे हैं। इसके अलावा थाकसिन ने हाल ही में कंबोडिया की सीमा से सटे इलाकों में कैसीनो और ऑनलाइन स्कैम हब्स के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी और खुद एक ऐसे इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स की योजना की बात की, जो कंबोडियाई कैसीनो उद्योग को चुनौती दे सकता था। यह कदम हुन सेन के लिए सीधा आर्थिक और रणनीतिक खतरा बन गया, जिससे तनाव और गहरा गया। फिलहाल थाईलैंड ने सीमाएं सील कर दी हैं और कंबोडिया ने भी थाईलैंड से आने वाले आयात जैसे फल, सब्जियां, गैस और फिल्मों पर रोक लगा दी है। कंबोडिया पहले से ही चीन के प्रभाव में है। पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन और वर्तमान प्रधानमंत्री हुन मानेट दोनों को चीन का भरोसेमंद साथी माना जाता है। यही वजह है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम में शांत तो है, पर उसकी मौजूदगी हर स्तर पर महसूस की जा सकती है। दक्षिण कंबोडिया में चीन द्वारा विकसित किया गया रीम नौसैनिक अड्डा अमेरिका और भारत जैसे देशों के लिए चिंता का विषय है। माना जाता है कि ऐसे ठिकाने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन की सामरिक पहुंच बढ़ा सकते हैं। थाईलैंड लंबे समय से अमेरिका का रणनीतिक साझेदार रहा है और कोबरा गोल्ड जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में अमेरिका के साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लेता है। लेकिन बीते वर्षों में चीन से उसके आर्थिक और सैन्य रिश्ते भी गहरे हुए हैं। अगर चीन इस टकराव में मध्यस्थ बनता है, तो वह अमेरिका के प्रभाव को तो काफी हद तक कम कर ही सकता है, साथ ही दोनों देशों के साथ व्यापार और निवेश को भी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ा सकता है। भारत के लिए यह संघर्ष कई वजहों से चिंता का कारण है। थाईलैंड 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का मुख्य प्रवेश द्वार है, जबकि कंबोडिया 'मेकोंग-गंगा सहयोग' में एक अहम साझेदार। भारत ने दोनों देशों में डिजिटल कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक परियोजनाओं और रणनीतिक संवादों पर काम किया है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच यह तनाव लंबा चलता है, तो भारत की कूटनीतिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। भारत को संतुलन साधना होगा और दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखते हुए अपने हितों की रक्षा करनी होगी। भारत को चाहिए कि वह आसियान के साथ संवाद और सहयोग को और मजबूत करे। क्षेत्रीय मंचों का उपयोग करके सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर संवाद बढ़ाना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। कंबोडिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक की मांग की है और मामला फिर से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन थाईलैंड ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार को नकारते हुए सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत पर जोर दिया है। इसके लिए उसने पहले युद्धविराम की शर्त रखी है। इस तनाव को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका अहम हो सकती है। अगर चीन इस संघर्ष में 'शांति-निर्माता' बनकर उभरता है, तो वह दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका की साख को और कमजोर करेगा और भारत की रणनीतिक स्थिति पर भी असर डालेगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

शिक्षा प्रणाली

सुनील कुमार महला

भारत के लिए फिनलैंड जैसा शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी

हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिरने से सात मासूम बच्चों की मौत हो गई, यह बहुत ही दुखद और हृदयविदारक घटना है। वास्तव में झालावाड़ में हुई यह घटना हमारे देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली के साथ ही हमारे एजुकेशनल सिस्टम पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है। सच तो यह है कि इस हादसे के बाद स्कूल और प्रशासन की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हादसे के बाद जब बच्चों की मौत हो गई तब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कह रहे हैं कि 2000 स्कूलों को ठीक किया जा रहा है और हादसे के दोषी वे खुद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मात्र स्वयं को दोषी ठहराने से इस हृदयविदारक हादसे की भरपाई संभव हो सकती है ? ऐसा भी नहीं है कि जर्जर व खराब हालात वाले स्कूल भवनों के बारे में किसी को जानकारी या सूचनाएं नहीं होती हैं, लेकिन दुखद यह है कि जानकारी होने के बावजूद समय रहते एक्शन नहीं लिया जाता और हादसे हो जाते हैं। आज राजस्थान ही नहीं हमारे देश में हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहां स्कूल बिल्डिंग्स को लेकर डर का साया है और बहुत से स्कूल आज भी मरम्मत, रख-रखाव के इंतजार में हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की इमारतें जर्जर हैं, शिक्षकों की कमी है और स्वच्छ पेयजल, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक का अभाव है। यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे देश की नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में स्कूलों के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। इसमें सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। आज नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस संदर्भ में हमें फीनलैंड से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बता दें कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्कूली शिक्षा प्रणाली फिनलैंड की मानी जाती है। दरअसल, फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली में बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) आधुनिक, सुसज्जित और छात्रों की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। इसमें आधुनिक क्लासरूम, खेल के मैदान, पुस्तकालय, और तकनीकी उपकरण जैसे कंप्यूटर, टैबलेट आदि, आधुनिक लैब, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सुविधाएं आदि शामिल हैं। फिनलैंड में शिक्षा प्रणाली में बुनियादी ढांचे के लिए सरकार और स्थानीय प्राधिकरण दोनों मिलकर काम करते हैं, और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार निवेश करते हैं। कुल मिलाकर यह बात कही जा सकती है कि फीनलैंड में यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी स्कूलों में छात्रों को सीखने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। कहना ग़लत नहीं होगा कि जब स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होता है तो छात्र सक्रिय, रचनात्मक और आत्मविश्वास से सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। बहरहाल, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फिनलैंड के अलावा, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, और कनाडा जैसे देशों की शिक्षा प्रणालियों को भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि दुनिया बदलने के लिए शिक्षा ही सबसे ताकतवर हथियार है और अच्छी शिक्षा प्रणाली वाले देश अपने छात्रों को उस जरूरी ज्ञान और कौशल से लैस करते हैं, जिनके जरिए वे ना सिर्फ समाज में योगदान दे पाएं, बल्कि आर्थिक तरक्की भी कर पाएं। बहरहाल, भारत एक विकासशील देश है और हम अपने देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का सपना देख रहे हैं। यह तभी संभव है जब हमारे यहां अपनी शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की ओर कदम उठायेंगे। इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर उतर कर पूरी ईमानदारी, इच्छाशक्ति व संकल्प के साथ काम करना होगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम हमारे देश के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना ध्यान केंद्रित करें। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि सभी स्कूलों की इमारतों की नियमित व पारदर्शी जांच हो और इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक समिति गठित हो जो स्कूल भवनों के स्ट्रक्चर और सिक्योरटी का समय-समय पर आकलन करती रहे। वैसे भी हाल फिलहाल पूरे देश में मानसून का समय चल रहा है, ऐसे समय में हमारे अधिकारियों और प्रशासन को यह चाहिए कि वे देश के तमाम स्कूलों और जर्जर सरकारी इमारतों का हाल जानें कि वे किस हालात में हैं और यदि वे ठीक नहीं हैं तो उनके रख-रखाव के लिए कार्रवाई को समय रहते जवाबदेही के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और अगर कोई स्कूल असुरक्षित स्थिति में पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार व कहिरतकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अच्छा काम आलस छोड़कर तुरंत करें

संकलित
दर्शन

शिव का अर्थ है- भोलापन। दुनिया में भोलापन उदय हो जाए, इसका उपाय है- 'शिव सूत्र'। शिव सूत्र छोटे-छोटे सुंदर सूत्र हैं। जीवन के लिए एक सूत्र ही काफी है। आपका जीवन इन सूत्रों के आनंदमय प्रकाश से भर जाएगा। जीवन में भोलापन उदय हो जाएगा। हमारा शरीर और मन दोनों अलग-अलग नियमों पर चलते हैं; जैसे- आप जितना व्यायाम करेंगे, शरीर उतना हृष्ट-पुष्ट होने लगता है, लेकिन मन के लिए एक अलग ही ढंग है। आप जितना विश्राम करेंगे, मन उतना ही तेज होने लगेगा। सबने सुना है, सब भगवान की इच्छा से होता है। 'तेन बिना तृणमपि न चलति' उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी होता है, सब भगवान ही करते हैं। जब हमें अपना पुरुषार्थ या उद्यम नहीं करना होता है, तो हम कह देते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा। जब हमारा संकल्प मजबूत नहीं होता है, तब कह देते हैं कि भगवान की इच्छा। लेकिन, ये बात और जगहों पर लागू नहीं होती है। जब भगवान भोजन कराएंगे, तब करेंगे। जब भगवान सिनेमा दिखाएंगे, तब देखेंगे। हम अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा को अलग-अलग मानते हैं। ऐसे लोगों को 'अनुकूल सिंधु' कहते हैं। जो अपने अनुकूल हुआ, वह मैंने किया है और जो प्रतिकूल हुआ, वह भगवान ने किया। कहीं जीत हो जाए तो मैंने जीता और कहीं हार गए तो भगवान की इच्छा। हम यह नहीं कहते हैं कि हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, इसलिए हम हार गए।

भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए

संकलित
प्रेरणा

एक बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उस महिला की बुद्ध के लिए गहरी आस्था थी। दरअसल, उस महिला के बेटे की मृत्यु हो गई थी। महिला बहुत दुखी थी और उसने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। महिला को लग रहा था कि बुद्ध उसके बेटे का जीवन बचा सकते हैं। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आना है, जहां कभी किसी की मौत न हुई हो। जिस परिवार ने किसी की मृत्यु का दुख नहीं देखा है, वहां से सरसों ले आओ। महिला ने सोचा कि ये तो छोटा सा काम है। बूढ़ी महिला गांव की ओर चल दी और एक-एक घर में जाकर पूछने लगी। महिला जिस घर में जाती, वहां कहती कि अगर आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। गांव के सभी लोगों का यही जवाब रहता था कि हमारे घर में मृत्यु तो हुई है। कुछ लोगों की बढ़ी उम्र में हुई है तो किसी की असमय हुई। जब सभी घरों से ऐसे ही उत्तर मिल रहे थे तो महिला समझ गई कि बुद्ध ने मुझे जरूर कुछ सोचकर ही भेजा है। जब वह लौटकर बुद्ध के पास पहुंची, तब तक वह जान चुकी थी कि एक दिन मौत सबको आनी है। उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए।

अंतर्मन

आज की पाती

बेईमानी का धन

आज भौतिकवादी और आधुनिक युग में कुछ लोगों को धन की इतनी भूख बढ़ रही है कि वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि, धन एक वस्तु है जो ईमानदारी और न्याय से कमाई जाती है, और इसका विपरीत है अधर्म का खजाना। लेकिन आज बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में बेईमानी, हेराफेरी, अनैतिकता की राह पर चल पड़ते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि गलत तरीकों से कमाई धन-दौलत ज्यादा दिन सुख नहीं दे सकती। कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा ही मन। अगर हम बेईमानी कि कमाई से अन्न खरीद कर खाएंगे या अपने परिवार को खिलाएंगे तो क्या वो अन्न हमारे या हमारे परिवार के लिए उचित भोजन होगा? शायद नहीं। पाप की कमाई से अगर बच्चों का पालन-पोषण किया जाए तो इससे बड़ा पापघाट ही होगे। - प्रखर जैन, राजनांदगांव

ट्रेंड

पुण्यतिथि पर नमन

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न, 'मिसाइल मैन' डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। भारत को परमाणु सम्पन्न बनाने में उनका अतुलनीय योगदान अविस्मरणीय है।
-जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

जनहानि अत्यंत दुखद

हरिद्वार स्थित श्री मनसा देवी मंदिर मार्ग में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मां मनसा देवी से प्रार्थना है कि शिवजल आत्माओं को सद्गति, शोकसंतप्त परिजनों को कष्ट अथवा दुःख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। ॐ शांति।
- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

हार्दिक बधाई

पेरिस, फ्रांस में आयोजित 55वें अंतरराष्ट्रीय मोटरसाइकिल प्रोफिवाड 2025 में इंदौर के रिद्धेश बेडसे एवं जबलपुर के स्नेहिल झा को स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। दोनों वीर युवा साधकों मध्यप्रदेश को गौरवान्वित करने वाले हैं।
- डा. मोहन यादव, सीएम, मप्र

हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे

दिल्ली की सुनियोजित से हटने वाले सैकड़ों गरीब परिवार के छोटे-छोटे घरों को नाजायज करार दे बेदखली से उजाड़ दिया। हम इन उजाड़े गए परिवारों के साथ मजबूती से खड़े है और हम हर मोर्चे पर लड़ेंगे।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

करंट अफेयर

इजरायल ने जहाज से गाजा जा रही राहत सामग्री रोकी

इजराइली सेना ने फलस्तीनी क्षेत्र की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर गाजा जाने वाले एक राहत सहायता जहाज को रोक लिया तथा 21 अंतरराष्ट्रीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को हिरासत में ले लिया।
फलस्तीन समर्थक समूह 'फ्रीडम फ्लोटिला कोलेशन' ने रविवार को यह जानकारी दी। समूह ने बताया कि इसके अलावा, इजराइली सेना ने जहाज पर लदे शिशु उपयोग के लिए दूध, खाद्य सामग्री और दवा सहित सभी माल जब्त कर लिए। जहाज 'हंडाला' का संचालन करने वाले समूह ने कहा कि इजराइली सेना ने शनिवार आधी रात से ठीक पहले गाजा से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज को बल प्रयोग कर रोका' और इसके संचार नेटवर्क को काट दिया। समूह ने एक बयान में कहा, 'जहाज पर लदा पूरा माल गैर-सैन्य उपयोग के लिए था तथा यह इजराइल की अवैध नाकेबंदी के कारण भुखमरी और विकिस्सा संकट से जूझ रही आबादी को सीधे वितरित करने के लिए था।' इस सिलसिले में इजराइली सेना ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है इजराइल के विदेश मंत्रालय ने रविवार तड़के 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि नौसेना ने जहाज को रोक लिया और उसे तट पर ला रही है।

ऑफ बीट

क्या वजन से स्वास्थ्य का आकलन हो सकता है

हमें पढ़ाया गया है कि दुबलेपन का सेहत से और अधिक वजन का बीमारी से संबंध होता है। लेकिन विज्ञान एक ज्यादा बारीक कहानी कहता है—जहां वजन एक कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर में सिर्फ एक आंकड़ा भर है। तो अगर अकेले वजन ही यह नहीं दर्शाता कि हम कितने स्वस्थ हैं, तो और क्या दर्शाता है? शरीर का वजन स्वास्थ्य के सबसे ज्यादा मापे जाने वाले पैमानों में से एक है। समाज इस पर बहुत जोर देता है और किसी व्यक्ति के वजन की आलोचना को अक्सर स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में देखा जाता है। तो वजन असल में कितनी सार्थक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करता है? सीधे शब्दों में कहें तो, व्यक्ति का वजन शरीर द्वारा ग्रहण की जा रही कैलोरी पर निर्भर करता है। समय के साथ वजन में बदलाव कैलोरी की खपत की ओर इशारा कर सकता है। अगर उनका वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे जितनी कैलोरी जला रहे हैं, उससे ज्यादा सेवन कर रहे हैं। वहीं, अगर उनका वजन घट रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वे जितनी कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज्यादा जला रहे हैं। शायद यह समझना ज्यादा उपयोगी होगा कि वजन हमें स्वास्थ्य संबंधी कौन-सी जानकारी नहीं देता।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोन: 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

अमर उजाला
प्रवाह
77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा
नई दिल्ली ■ सोमवार, 28 जुलाई 2025

वह नुकसान सबसे अधिक दर्दनाक होता है, जो लापरवाही के कारण होता है। -सेनेका द यंगर

मनसा देवी मंदिर में करंट की अफवाह के चलते मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौतें एक बार फिर भीड़-प्रबंधन नीतियों की विफलता की ओर इशारा करती हैं। यह सुनिश्चित करना प्रशासन और मंदिर प्रबंधन का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था के प्रति भी श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे।

आस्था और व्यवस्था

उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में दर्शन के दौरान करंट फैलने की अफवाह से मची भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मौतें और कई का घायल होना महज एक अफवाहजनित दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की विफलता का आईना भी है। पहाड़ के ऊपर बने इस मंदिर में पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि लोग तार पकड़कर ऊपर चढ़ रहे थे, जिसके दौरान तार छिल गए, जिससे उनमें करंट आ गया और अफरातफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने करंट फैलने की बात को अफवाह बताया। पुलिस का कहना है कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन मनसा देवी मंदिर, जो हरिद्वार के पंच तीर्थों में से एक है और श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, हमेशा ही भीड़ का केंद्र बना रहता है। इस बार, भारी भीड़ के बीच एक बिजली के खंभे से चिंगारी और करंट की अफवाह ने स्थिति को भयावह बना दिया। सावन के महीने में ज्यादा भीड़ के नियंत्रण के लिए आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था और अफवाहों से निपटने के लिए ठोस रणनीति होनी चाहिए थी, जिसका ताजा हादसे में अभाव दिखा। यह पहली बार नहीं है, जब किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह की दुर्घटना हुई हो। हर साल तीर्थ स्थलों पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं। किसी भी धार्मिक स्थल या आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। यह हादसा हमें एक गंभीर चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया और मौखिक संचार के इस युग में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। भविष्य में इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण हादसे न हों, इसके लिए जरूरी है कि भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की जाए, अफवाहों से निपटने

के लिए प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए, अफवाह की स्थिति में तत्काल श्रद्धालुओं को सही सूचना देने की व्यवस्था हो और आपातकालीन निकासी मार्ग के साथ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए कि वह सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा ऑडिट और आपदा प्रबंधन की योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन कराए। यह समय मृतकों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना का तो है ही, इसका भी है कि प्रशासन एवं मंदिर प्रबंधन यह सुनिश्चित करे कि धार्मिक स्थलों पर व्यवस्था के प्रति भी श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे।

आतंकवाद, ममदानी और मोदी

पहलगाम में जो हुआ, उसकी शैली इस्राइल में हुए हमास के हमले की तरह मजहब से प्रेरित थी। एक तरफ ममदानी जैसे नेता और इंतिफादा के वैश्वीकरण पर उनके बदलते विचार हैं, तो दूसरी तरफ मोदी हैं, जो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कह रहे हैं कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है।

अमेरिकी राजनीतिज्ञ जोरान ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने की दौड़ में हैं, ने एक छोटी-सी दया की है कि वह इंतिफादा (विद्रोह) का वैश्वीकरण कर इस युद्धघोष को लोकप्रिय नहीं बनाएंगे। वह इसके पीछे के विचार को भी नहीं नकारेंगे- विचार यह है कि गाजा में इस्राइल की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश है। उनके पक्ष को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। न्यूयॉर्क के विभिन्न सीईओ के साथ बातचीत के दौरान ममदानी ने संकोच सोच रखने वालों को जो रियायत दी, वह शायद उनके अतिवादी विचारों के बावजूद समावेशी दिखने की उत्सुकता से प्रेरित थी।

एस प्रसन्नराजन
संपादक, ओपन मैगजीन

वामपंथी राजनीतिक भाषा में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की दिशा से किसी को विचलित करने के लिए भाषाई विराम अब भी पर्याप्त नहीं है। ममदानी, जो न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में अग्रणी उम्मीदवार से बढ़कर हैं, ने तथाकथित शहरी विशिष्टों (स्नोफ्लेक्स) को क्रांति बेचकर प्रगतिशील कट्टरपंथ के युवराज का खिताब पहले ही जीत लिया है। ममदानी के इस तीखे हमले के कारण वैचारिक विद्रोह के डर से दक्षिणपंथी लामबंद हो सकते हैं, और यह रिपब्लिकन के लिए उतना बुरा नहीं है, जो न्यूयॉर्क में लगातार हारते रहे हैं।

क्या राष्ट्र का विचार या उस पर आधारित राजनीति, नए कट्टरपंथियों की साझा पीड़ित होने की भावना को और बढ़ाती है? क्या ऐसा है कि प्रगतिशील कहानी में राष्ट्रीय महानता की पुनर्स्थापना पर दक्षिणपंथी परियोजना, एक बनावटी अतीत से अपना कच्चा माल प्राप्त करती है, तथा वह जिस भविष्य का वादा करती है, वह एक कल्पना है, जिसका उद्देश्य दुखी लोगों को नशे में डालना है?

पीड़ित होने का दिखावा करने वाले एक ईसाई वामपंथ के लिए पीड़ित को सहानुभूति के चौराहे पर लाने की खातिर वर्जनाएं जरूरी शर्त हैं। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध मानवता के खिलाफ युद्ध है, भोजन की कतारों में खड़े गाजा के बच्चे इसकी गवाही देंगे। और सात

अक्तूबर, 2023 को दक्षिणी इस्राइल में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। यह एक अन्यायपूर्ण इतिहास की शुरुआत की यात्रा है और इस तरह से नैतिकता का उलटा प्रभाव सड़क पर लड़ने वाले लोगों और उनके वैचारिक सहयोगियों द्वारा हासिल किया जाता है।

इस्राइल वह राष्ट्र है, जो नारों की लड़ाई के बीच सबसे अधिक अलगाव महसूस करता है और अपने जीने के अधिकार के लिए अविचल रूप से कार्य करता है। जब इस्राइल के खिलाफ आतंक का अभियान ममदानी जैसे प्रशिक्षु क्रांतिकारियों को इंतिफादा का वैश्वीकरण करने जैसा यहूदी विरोधी नारा देने के लिए प्रेरित करता है, तो यह दर्शाता है कि किस तरह से तुच्छ बयानबाजी राष्ट्रों के अस्तित्व के संघर्ष को मानवता के विरुद्ध आतंक में बदल सकती है। जो लोग इस्राइल को अस्तित्व का अधिकार देने से इन्कार करते हैं, उनके खिलाफ इस्राइल का स्थायी बचाव, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता के लोकप्रिय संस्करण की अस्वीकृति है। किसी भी अन्य राष्ट्र ने, चाहे उसे जिहादियों और आतंकवाद के समर्थकों द्वारा आतंकवादी राज्य के रूप में चित्रित किया गया हो, युद्ध के मैदान में राष्ट्र के विचार को एकमात्र कारण नहीं बनाया है। बचाव की तीव्रता और इसके कार्यक्षेत्र के लगातार बढ़ते विस्तार ने निश्चित रूप से गाजा में गंभीर मानवीय संकट पैदा कर दिया है। आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में इस्राइल जो कहानी कहता है, वह यहूदी-विरोधी अभियान की कथात्मक चौड़ाई और फलस्तीनी संघर्ष के अमर रोमांस से कहीं अधिक बड़ी है। इस्राइल की दृढ़ता ने इंतिफादा को आसानी से सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी है।

आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में तर्क भी मददगार साबित हो सकते हैं। भारत आतंकवादी हमले के शिकार राष्ट्रों के लिए पीड़ित राष्ट्र की विश्वसनीयता के साथ तर्क प्रस्तुत कर रहा है। आतंक के साथ जीने की हमारी कहानी स्वतंत्र भारत जितनी पुरानी हो सकती है, लेकिन 2014 के बाद से, जब मोदी राष्ट्रीय मुक्ति के नारे के साथ सत्ता में आए, तो संदेश की तात्कालिकता के साथ-साथ त्वरित जवाब का सिद्धांत भी सामने आया है। इस संदेश को कभी भी पूर्ण स्वीकृति नहीं मिली, इसका एक कारण यह भी है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में कश्मीर के बारे में गलत धारणा व्याप्त है, तथा भारत-पाकिस्तान तनाव को ऐतिहासिक अपरिहार्यता के रूप में देखा जाता है।

वामपंथियों द्वारा इस्लामोफोबिया की दीवार भी खड़ी की गई है, जो इस्लाम और वैश्विक आतंकवाद पर एक ईमानदार बहस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहलगाम में जो हुआ, उसकी शैली और बर्बरता, दो साल पहले इस्राइल में हुए हमास के हमले की तरह ही मजहब से प्रेरित थी। इस संकट की घड़ी में दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। दुनिया ने भारत के सटीक जवाबी कार्रवाई करने के राष्ट्रीय संकल्प और सजा मिलने के बाद उसके संयम का समर्थन करने में उतनी तत्परता नहीं दिखाई। भारत को अपनी कहानी को आगे बढ़ाना था और इस बात पर जोर देना था कि विश्व को इसे अपना मानना चाहिए।

यही वह संदेश है, जो मोदी दुनिया को देना चाहते हैं, और यह संदेश एक ऐसे नेता की ओर से है, जो जानता है कि इस्लामवादी वैधता के साथ आतंकवाद के विरुद्ध बहस जीतने के लिए क्या करना होगा। चूंकि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध एक बार फिर एकजुट वैश्विक प्रतिक्रिया के बजाय पृथक राष्ट्रीय कार्रवाई बन गया है, इसलिए इस संदेश को विश्वसनीय और तात्कालिक बनाने के लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता है, जिसके पास उतना ही ठोस और स्थायी लोकतांत्रिक जनादेश हो, जितना कि आज दुनिया में अकेले मोदी के पास है।

इंतिफादा (विद्रोह) का वैश्वीकरण एक भयावह कल्पना है, लेकिन जाने या अनजाने में, भारत के प्रधानमंत्री अपने पास उपलब्ध हर अंतरराष्ट्रीय मंच से यह कहकर एक प्रतिवाद प्रस्तुत करते हैं कि दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जग्गी वासुदेव

एक बार आपने क्षमा मांग ली, तो इल्जाम लगाने वाला ही अपराध-बोध को ढोएगा। यह न तो जलील होना है, न हार जाना। यह तो इस बात की निशानी है कि आपका मन परिपक्व हो गया है।

गलती को मानने से सम्मान ही बढ़ता है

छुटपन में आप कितने सरल-तरल थे। मार खाने के बाद भी बिना किसी द्वेषभाव के मारने वाले व्यक्ति के पास भी बार-बार जाते थे। कहां गया खुशी का वह आलम? बड़े होते-होते शारीरिक और मानसिक रूप से ठोस बन गए। आपने समाज में अपने लिए एक महान पहचान बना ली। अब उस पहचान और प्रतिष्ठा को बनाए रखने की कोशिश में अपनी ईमानदारी का भी बलिदान करने को तैयार हो गए। इसलिए गलती मानने की अपनी बुनियादी प्रकृति को भी गंवा बैठे हैं। मानव रूप में जन्मा हुआ कोई भी गलती से परे नहीं है। यह कोई समस्या नहीं है कि जो काम किया, वह सही था या गलत। गलती मानना अपमानजनक है, यही अहंकारपूर्ण सोच कई लोगों को झकझोरती है। 'क्षमा कर दो भई, भूल हो गई। मैंने अनजाने में गलती कर दी। अगली बार सावधान रहूंगा' यों विनीत भाव से कह देंगे, तो क्या आपके सिर से ताज उतर जाएगा? अंदर गलती का एहसास होने पर भी प्रकट रूप से स्वीकार करने के साहस के बिना उसे उचित ठहराते जाना ही सबसे बड़ी भूल है। एक बार शंकरन पिल्लै ने किसी दूसरे के बाग में डालों से लटक रहे पके-पके फलों को देखा। जल्दी से एक बोरी ले आए। बाड़ को फांदा। बड़ी फुर्ती के साथ पेड़ से फल तोड़ डाले। उन्हें बोरी में भरके कंधे पर डाल लिया। फिर से बाड़ फांदकर बाहर निकले ही थे कि बाग के मालिक ने पकड़ लिया। 'बोलो किसकी इजाजत से इन्हें तोड़ा था?' 'मैंने कहां तोड़े? बड़ी जोर की हवा चली। आंधी में ये फल नीचे झड़ गए।' शंकरन पिल्लै ने कहा। 'तो यह बोरी काहे को उठा लाए?' 'ओह.. बोरी ? यह भी कहीं से हवा में उड़ते हुए आ गिरी थी।' 'माना कि जोर की हवा में फल झड़ गए। और बोरी हवा में उड़कर आ गिरी, मगर फलों को भरने वाला कौन था, बताओ।' बाग का मालिक दहाड़ पड़ा। शंकरन पिल्लै घबराए नहीं, बड़े भोले बनकर बोले, 'वही मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है।' गलती करने वालों में से अनेक लोग शंकरन पिल्लै की तरह रंगे हाथ पकड़े जाने पर भी अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उसे उचित ठहराने के लिए नई-नई दलीलें रखते हैं। गलती को माने बगैर यों तर्क करना खतरनाक है। अपनी गलती को मान लीजिए। ऐसा करने से आपका सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अनजाने में एक बार गलती हो सकती है। लेकिन गलती की ओर ध्यान दिए बिना और सैकड़ों लोगों को वही दर्द पहुंचाना अपनी प्रगति और विकास को अवरुद्ध करना है। कुछ लोग आपकी गलती को सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। उन्हें देखने दें, कोई बात नहीं। अगर आप क्षमा मांगते, तो लड़ाई वहीं समाप्त हो गई होती न? फिर इल्जाम लगाने वाला ही तो अपराध-बोध को ढोएगा। अच्छी तरह से समझ लीजिए, यह न तो जलील होना है, न हार जाना। यह तो इस बात की निशानी है कि आपका मन परिपक्व हो गया है। आप व्यापारी हो सकते हैं या खिलाड़ी, अपनी गलतियों को मानने के आधार पर ही जीवन में आपकी सफलता निर्भर करती है। गलतियों को मानना एक ऐसी शक्ति है, जो दुश्मनों को आपका दिली दोस्त बना दे। यह अद्वैत शक्ति आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगी।

प्रेम भाव से रहें

सूत्र

अधिकांश लोग बड़ी चतुराई से झूठ बोलकर आगे निकल जाते हैं और खुद को बुद्धिमान मानते हैं। वे तरह-तरह की डींगें हांकते हैं। यह सब एक क्षण में धराशायी होकर बिखर जाएगा और अंत में उसे उसकी गलती की सजा मिलनी तो तय है। इसलिए जब-तक जीवन है, तब तक ईमानदारीपूर्वक प्रेम भाव से रहें।

दूसरा पहलू

लगभग 150 साल तक स्कॉटलैंड की एक तिजोरी में बंद रहीं सीताराम की पेंटिंग्स उस दौर का सटीक विवरण पेश करती हैं।

गुमनाम ही रह जाता ब्रिटिश काल का विलक्षण चितेरा

अगर भारत से मीलों दूर स्कॉटलैंड में मौजूद वह तिजोरी नहीं खुलती, तो दुनिया सीताराम नामक उस विलक्षण चितेरे के बारे में कभी नहीं जान पाती, जिसने कैनवास पर मानो इतिहास को उकेर दिया था। सीताराम के बारे में हम अब भी बस इतना ही जानते हैं कि वह बंगाली हिंदू थे। सीताराम की पेंटिंग्स जैसे ही दिगंज ब्रिटिश कला समीक्षकों ने देखीं, वे हैरान रह गए। उनकी तस्वीरें उस दौर की इमारतों और पूरे माहौल का सटीक विवरण पेश करती हैं।

भूपेंद्र कुमार

वर्ष 1814-23 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में गवर्नर जनरल रहे फ्रांसिस राडसन हेस्टिंग्स को कोई ऐसा चित्रकार चाहिए था, जो महत्वपूर्ण शहरों में उनके दौरे को दर्ज कर सके। यहीं से सीताराम और हेस्टिंग्स का साथ बना। बंगाल के बैरकपुर से पटना, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली और हिमालय तक सीताराम ने ऐतिहासिक इमारतों और घटनाओं के चित्र बनाए। सीताराम जून, 1814 से अक्तूबर, 1815 तक उत्तर भारत के शहरों में घूमे। हेस्टिंग्स ने सीताराम के बारे में अपने संस्मरणों में बस यही लिखा है कि एक बंगाली ड्राफ्ट्समैन भी हमारे साथ था। ब्रिटिश कला इतिहासकार गाइल्स टिलोत्सन के अनुसार, हेस्टिंग्स के इस दौरे का मकसद नेपाल युद्ध के लिए भारतीय राजाओं का समर्थन जुटाना और ब्रिटिश हुकूमत के प्रसार के उपाय तलाशना था। ऐसी तीन यात्राओं के दौरान सीताराम ने 229 बड़े चित्र बनाए। 40 गुणा 60 सेंटीमीटर की इन तस्वीरों को दस एलबमों में रखकर हेस्टिंग्स 1823 ई. में ब्रिटेन ले गए। इसके बाद वे हेस्टिंग्स की खानदानी हवेली में 1970 तक रोके ही पड़ी रहीं। 1974 में उनके परिवार ने दो एलबम (46 पेंटिंग) बेचने का फैसला किया। एलबम के कवर पर सीताराम का नाम था, जिससे दुनिया को पता चला कि कितना दुर्लभ काम उन्होंने किया था। तब तक किसी को सीताराम और हेस्टिंग्स के संबंधों का पता नहीं चल सका था। इसकी वजह थी कि पेंटिंग्स निजी संग्रहकर्ताओं ने खरीदी थीं। 20 साल बाद उनके परिजनों ने बाकी आठ एलबम ब्रिटिश लाइब्रेरी को चार लाख पूरी (लगभग चार करोड़ रुपये) में बेच दीं। जब यह पूरा संग्रह सार्वजनिक हुआ, तो इन चित्रों की अहमियत लोगों ने जानी। खोजकर्ताओं को यह भी पता चला कि सीताराम हेस्टिंग्स के जाने के बाद भी तस्वीरें बनाते रहे। कला समीक्षक मानते हैं कि सीताराम ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में कला की बारीकियां सीखीं। 18वीं सदी में मुर्शिदाबाद मिनिएचर आर्ट का बड़ा केंद्र था। सीताराम की बाद की पेंटिंग्स कहां और किसके पास हैं, यह किसी को पता नहीं। मुमकिन है किसी जर्जर इमारत के तलघर में उन्हें भी किसी कद्रदान का इंतजार हो।

सीताराम की तस्वीरें ब्रिटिश काल की इमारतों और पूरे माहौल का सटीक विवरण पेश करती हैं, जिन्हें देखकर ब्रिटिश कला समीक्षक हैरान रह गए।

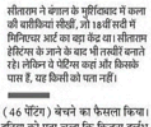

सीताराम ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में कला की बारीकियां सीखीं, जो 18वीं सदी में मिनिएचर आर्ट का बड़ा केंद्र था। सीताराम हेस्टिंग्स के जाने के बाद भी तस्वीरें बनाते रहे। लेकिन वे पेंटिंग्स कहां और किसके पास हैं, यह किसी को पता नहीं।

आंकड़े

तैराकी के शौकीन

दुनिया भर में लाखों लोग डूबने से मर जाते हैं। तैराकी स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। ऑस्ट्रिया के लोग सबसे ज्यादा तैराकी के शौकीन हैं।

आंकड़े प्रतिशत में हैं। स्रोत : statista

एक सिपाही ने भगवानदास जी को पांच दिनों तक अवध से बाहर जाने से रोका, छठे दिन उन्हें भगवान की कृपा समझ में आई।

सब भगवान की कृपा है

श्री भगवानदास जी मधुकरिया जब से अवध आए, तो उन्हें अवध से गहरा प्रेम हो गया था, और वह किसी को वहां से जाने की आज्ञा भी नहीं देते थे। एक बार वह बीमार पड़ गए। छह महीने तक उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उनके शुभचिंतकों ने आग्रह किया कि वह कुछ दिनों के लिए कहीं और जाकर जल परिवर्तन करें, परंतु वह कहीं नहीं गए।

कुछ दिनों बाद उनके मन में विचार आया कि शायद बाहर जाना उचित होगा। लेकिन यह बात किसी से साझा करना ठीक नहीं समझकर वह चुपके से निकल पड़े। रास्ते में मणिपर्वत के समीप एक सिपाही मिला। उसने पूछा, 'कहां जा रहे हो?' श्री भगवानदास जी संकोच में पड़ गए और कोई उत्तर नहीं दे सके। सिपाही ने कहा, 'हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, लौट जाओ।' वह दूसरा रास्ता अपनाकर गए, पर सिपाही वहां भी पहुंच गया। जिधर जाते, वह उधर ही आ जाता। बहुत सोचने के बाद वह घर लौट आए। अगले दिन सुबह फिर निकले, पर सिपाही ने पुनः रास्ता रोक लिया। चार-पांच दिन तक अलग-अलग रास्तों से जाने की कोशिश की, पर हर बार वह सिपाही मिल जाता। छठे दिन उन्हें एहसास हुआ कि वह पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं और ऊर्जा से भरे हैं। अगले दिन वह फिर गए, पर इस बार कोई सिपाही नहीं मिला। तब उन्हें समझ आया कि यह सब भगवान की कृपा है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 28 जुलाई, 1952

मिस्र के पांच बड़े फौजी अफसर गिरफ्तार किए गए

मिस्र के पांच उच्चपदों के अफसर गिरफ्तार किये गये
भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के १ लाख का अनाजापराधिकरा

काहिरा के जनरल नगीब के आदेश पर मिस्र के पांच बड़े फौजी अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। इन लोगों में तीन जनरल व दो कर्नल शामिल हैं। इन लोगों पर शांति भंग करने के आरोप लगाए गए हैं।

जीएसटी कैसी है पहेली, हाय

जीएसटी के नियम इतने सरल हों कि छोटे कारोबारियों को भी ये आसानी से समझ में आएं। इसे सिर्फ राजस्व उगाही का माध्यम नहीं होना चाहिए।

मधुरेंद्र सिन्हा — आर्थिकी

भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की परिकल्पना की गई। इसे टैक्स वसूली तथा कारोबारियों को राहत देने की दिशा में एक गेम चेंजर माना गया। लेकिन इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कई तरह की समस्याएं आती रही हैं। कारोबारियों को बताया गया कि उनके लिए टैक्स भरना पहले से भी आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीएसटी को सुचारु ढंग से लागू करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि थे। अब भी जीएसटी काउंसिल ही इसका काम देखती है। यह भारत सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत नहीं है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता भर करती हैं। उन्हें अपने बूते कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। वहां जो भी फैसले होते हैं, वे बहुमत से होते हैं।

इसी कारण कई बार कुछ बड़े फैसले अटक जाते हैं। जनता की तरह वित्तमंत्री की भी इच्छा रही है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ताकि पूरे देश में इसका मूल्य एक समान हो, पर बहुत से सदस्य इसका विरोध करते हैं। वे अपने राज्य के हित में ऐसा नहीं होने देते। जब भी किसी राज्य को अपना राजस्व बढ़ाना होता है, वह तुरंत ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कर्नाटक, जहां इनकी कीमतें सबसे ज्यादा हैं। अगर यह जीएसटी के दायरे में होता, तो ऐसा संभव नहीं था।

कारोबारी और व्यापारी भी अब तक जीएसटी भुगतान में सहज नहीं हो पाए हैं। जीएसटी में कई विसंगतियां हैं। मसलन, दो तरह के सामान, जो मिलकर एक उत्पाद बनते हैं, उन पर अलग-अलग टैक्स दरें हैं। यह कारोबारियों के लिए एक परेशानी है। अगर हम भारत के पॉपुलर स्नैक बन मस्का को देखें, तो पाएंगे कि बन पर टैक्स की दर अलग है और मस्का यानी मक्खन पर अलग। अब व्यापारी किस दर से टैक्स लेगा? रेस्तरां में रोटी पर कम टैक्स है, तो पराठे पर ज्यादा। बिना एसी वाले रेस्तरां के लिए अलग दर है, तो एसी वाले के लिए अलग। खुले सामान पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन पैकेट में आते ही उस पर टैक्स लगेगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जो जीएसटी की विसंगतियां बताते हैं। इसके अलावा कई सेवाओं पर 18 फीसदी का भारी-भरकम टैक्स भी है। एक ओर सरकार जनस्वास्थ्य को लेकर चिंता जताती है, तो दूसरी ओर जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटी लगाई है। कारोबारियों की मांग है कि टैक्स दरों में विसंगति न हो और उन्हें तार्किक बनाया जाए।

इस समय टैक्स के चार स्लैब हैं-5,12,18 और 28 फीसदी। इन्हें घटाकर तीन स्लैब करना चाहिए। इन दरों को तर्कसंगत बनाने से वैधानिक मामले कम हो जाएंगे। साथ ही, जीएसटी की रिटर्न प्रणाली और इनपुट टैक्स क्रेडिट नीति में भी बदलाव की जरूरत है। जीएसटी लागू हुए आठ वर्ष हो गए, लेकिन इसके नियमों में हर महीने बदलाव होते रहते हैं, जिससे व्यापारियों में भ्रम पैदा होता है। दूसरी तरफ, सरकार की शिकायत है कि अब भी जीएसटी की बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। कई राज्यों में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चोरी हो रही है। वर्ष 2022-23 में देश में दो लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई। पिछले पांच वर्षों में केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने टैक्स चोरी के 86,717 मामलों का पता लगाया, जिससे 6.79 लाख करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता लगा।

जीएसटी नियम निर्माण से लंबे समय जुड़े रहे सुमित दत्त मजूमदार कहते हैं कि जीएसटी के नियमों को इतना सरल कर दिया जाना चाहिए कि छोटे से छोटे कारोबारी को भी यह आसानी से समझ में आ जाए। टैक्सेशन सिर्फ राजस्व उगाही का माध्यम नहीं होना चाहिए, यह जनता के हित में भी होना चाहिए।

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के संस्थापक और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, जो अब सांसद हैं, कहते हैं कि जीएसटी को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के वित्तमंत्री सम्राट चौधरी अभी इसकी कमान संभाल रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्रियों के समूह में इस पर काफी चर्चा की है। इसे और सरल बनाने, स्लैब कम करने एवं व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बातचीत हुई है। अगले महीने जीएसटी कांउसिल की बैठक में इन पर विचार होगा। कुछ चीजों और सेवाओं पर जीएसटी की दर घटाने की भी बात चल रही है।

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल इसमें आमूल-चूल बदलाव करेगी। टैक्स के स्लैब घटाए जाएंगे, सरलीकरण की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा और कुछ सेवाओं एवं वस्तुओं पर टैक्स घटाए जाने की भी उम्मीद है। बस संसद के मानसून सत्र के बाद काउंसिल की बैठक का इंतजार है।

राष्ट्रीय सहारा
पटना • सोमवार • 28 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

सौ बार सोचेगा पाकिस्तान

थल सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के कथन से पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब संयम बरत कर सारे षड्यंत्र झेलना भारत की नियति नहीं है। भारत अब बदल गया है और अपने खिलाफ किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देता है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक संदेश था और साथ ही यह पूरे देश को गहरा जख्म देने वाले पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब भी था। इस बार भारत केवल शोक में नहीं डूबा,

बल्कि उसने दिखाया कि दिल दुखाने वालों को निर्णायक जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात तो साबित कर दी है कि जरूरत पड़ने पर अब इस सोच-विचार में समय खराब नहीं किया जाता कि सेना को सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ही सीमित रहना है। अब भारत जरूरत होने पर पाकिस्तान में अंदर तक घुस कर भी आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा सकता है और आतंकवाद की पोषक पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की भी चूलें हिला सकता है। दुश्मन को कड़ा जवाब देना भारत के लिए अब सामान्य बात है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने या लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने पर ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने निर्देशों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पाकिस्तान में नौ महत्वपूर्ण आतंकवादी ढांचों को नष्ट किया। आतंकियों के बचाव में भारत की कार्रवाई रोकने के लिए पाकिस्तान के आक्रामक प्रयासों को सेना ने विफल किया। भारत ने शांति का मौका दिया लेकिन पाकिस्तान ने कायरता दिखाई। आठ-नौ मई को पाकिस्तानी कार्रवाई का ऐसा जवाब दिया गया जिसे पाक कभी भूल नहीं पाएगा। हमारी सेना की वायु रक्षा एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी रही जिसे पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल या ड्रोन भेद नहीं सका। अब भारत रुद्र ब्रिगेड की स्थापना करने जा रहा है, इसके तहत एक ही स्थान पर पैदल सेना, मशीनीकृत पैदल सेना, बख्तरबंद इकाइयां, तोपखाना, विशेष बल और मानवरहित हवाई इकाइयां होंगी जो साजोसामान और युद्ध संबंधी सहायता प्रदान करेंगी। सेना ने विशेष बल भैरव लाइट कमांडो इकाई का भी गठन किया है जो दुश्मन से निपटने को हमेशा तैयार रहेगी। अब पाकिस्तान की परमाणु शक्ति होने की धौंस नहीं चलने वाली।

बंद होना सही कदम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील, अभद्र व पोर्नोग्राफिक सामग्री उपलब्ध कराने वाले तकरीबन पच्चीस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइटों व ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। यह कदम गृह मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि-मामलों के विभाग, सिब्बी व सीआईआई जैसे उद्योग निकायों समेत महिला व बाल अधिकार क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श के बाद उठाया गया है। बताया जा रहा है कि छब्बीस वेबसाइट्स के साथ गूगल प्लेस्टोर में पर नौ व एपल प्लेस्टोर पर पांच यानी चौदह ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न मध्यस्थों को अधिसूचना जारी की गई है ताकि इसे सुनिश्चित किया जा सके। आरोप है कि इसमें नग्नता, यौन इशारे, अश्लील दृश्यों के लंबे अंश शामिल थे। अनुचित संदर्भों में नग्नता, यौन संबंधों का चित्रण, अश्लील सामग्री भारतीय न्याय संहिता व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जिनकी शिकायतें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ओयाग को प्राप्त हो रही थीं। इनमें उल्लू व अल्ट के चिन्हित संदर्भ भी प्राप्त किए गए। इसी साल मार्च में ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए सरकार द्वारा अश्लीलता से संबंधित कानूनों के तहत निर्धारित आचार संहिता भी जारी की जा चुकी है। बीते साल इन्हें न केवल चेताया गया था, बल्कि पांच प्लेटफार्मों को प्रतिबंधित भी किया गया था परंतु उन सबने नये वेबसाइट डोमन पर पुनःप्रसारण चालू कर लिया। यह भी पाया गया कि आपत्तिजनक दृश्य या वेब-सीरीज अल्पकाल के लिए हटा लिए जाते हैं पर उन्हें चेतावनी के साथ पुनः प्रकाशित किया जाता है। बीते साल देश में अकेले एक ऐप के गूगल प्लेस्टोर से एक करोड़ से ज्यादा व दो ऐप पचास-पचास लाख डाउनलोड मिलने के बाद से इस चिंता का इजाफा हुआ है कि इंटरनेट का प्रयोग करने वालों में अश्लील सामग्री के प्रति लोलुपता बढ़ती जा रही है। बेशक, पोर्नोग्राफी देखने वाले भारतीयों की संख्या में साल्नों-साल इजाफा होता जा रहा है मगर एडल्ट कंटेंट दिखाने वालों को यौन सामग्री प्रदर्शित करने की खुली छूट नहीं दी जा सकती। हमारी संस्कृति अनुपयुक्त खुलेपन की आदी नहीं है। इसलिए स्व-नियामक आवश्यक हैं।

महाश्वेता देवी/प्रो. आर.के. जैन

शब्दों में जंग, जीवन में आंदोलन

जब शब्द तलवार की धार बन जाएं और कलम क्रांति का हथियार, तब रचनाएं केवल स्याही और कागज नहीं रहतीं, बल्कि वे समय की सीमाओं को तोड़ कर सदियों तक दिलों में गूंजती हैं। ऐसी ही थीं महाश्वेता देवी- एक लेखिका, एक योद्धा, जिनकी लेखनी में जंगलों की सांस थी, आदिवासियों का दर्द था, और समाज के अंधेरे को चीरती एक प्रखर रोशनी थी। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें केवल याद करना नहीं, बल्कि उनके विचारों को जीवित रखना, उनके संघर्षों को आत्मसात करना और उनकी लड़ाई को आगे ले जाना हमारा सच्चा कर्त्तव्य है।

28 जुलाई, 2016 को जब वे इस दुनिया से रुखसत हुईं, भारत ने न केवल एक साहित्यकार खोया, बल्कि ऐसी शख्सियत को अलविदा कहा जिसने अपनी कलम से शोषित के लोगों की आवाज दी। अन्याय के खिलाफ विद्रोह की मशाल जलाई। उनकी लेखनी में वह आग थी, जो हर उस जुल्म को भस्म करना चाहती थी जो इंसानियत को लज्जित करता था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर करने वाली महाश्वेता की असली शिक्षा उन जंगलों, गांवों और आदिवासी बस्तियों में हुई जहां उन्होंने वंचितों के दर्द को करीब से देखा। उनकी रचनाएं उस मिट्टी की गंध, उस पीड़ा और उस संघर्ष की गवाही देती हैं, जो भारत के आदिवासी और शोषित पर जी रहे समुदायों की जिंदगी का सच है। उनकी लेखनी न केवल साहित्य, बल्कि एक आंदोलन थी-जो अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती थी। महाश्वेता देवी का साहित्य केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इतिहास के उन दबे-छिपे पन्नों का जीवंत दस्तावेज भी है, जिन्हें सत्ता ने मिटाने की साजिश रची। महाश्वेता देवी की पुण्यतिथि हमें न केवल उनकी स्मृति में झुकने को प्रेरित करती है, बल्कि एक अटल संकल्प की भी मांग करती है कि हम उनके साहित्य को न सिर्फ पढ़ें, बल्कि उसे अपने जीवन की मशाल बनाएं और समाज के दबे-कुचले वर्गों के लिए लड़ें। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी हथियार है जो अन्याय की नींव को हिला सकता है। महाश्वेता देवी की तरह जीना कोई साधारण पथ नहीं। उनकी तरह निर्भीक होना, सत्ता के तख्तों से टकराना, और हर उस इंसान के लिए लड़ना, जो अपने हक से वंचित है-एक तपस्या है, एक संपूर्ण समर्पण है।

बढ़ रही है लोकप्रियता

भारतीय पासपोर्ट

विनीत नारायण

हाल में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स-2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष के 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़ कर भारत अब 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इसका सीधा लाभ पासपोर्टधारकों को मिल रहा है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक संबंधों के लिए भी शुभ संकेत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है, जो दुनिया के पासपोर्ट को उनकी यात्रा स्वतंत्रता के आधार पर रैंक करता है यानी कोई पासपोर्टधारक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में यह सुधार सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों के लिए अधिक वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल देशों तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्टधारक 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या 57 थी। यह बढ़ी हुई पहुंच भारतीय यात्रियों के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। वीजा प्रक्रिया अक्सर लंबी, जटिल और खर्चीली होती है। वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा यात्रा योजना को सरल बनाती है, समय बचाती है, और अचानक यात्राओं को संभव बनाती है। यह व्यापार, पर्यटन और व्यक्तिगत यात्राओं को बढ़ावा देती है। व्यापारिक पेशेवरों के लिए आसान अंतरराष्ट्रीय यात्रा व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने में मदद करती है। इससे विदेशी निवेश आकर्षित होता है, और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचने में आसानी होती है। भारतीय पर्यटकों के लिए अधिक गंतव्यों तक आसान पहुंच अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित करती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आसान यात्रा विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन या शोध के लिए नये अवसर खोलती है, जिससे ज्ञान और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ता है।

मजबूत पासपोर्ट किसी देश की वैश्विक प्रतिष्ठा और उसके नागरिकों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। यह भारत की बढ़ती 'सॉफ्ट पावर' का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में उछाल के पीछे कई कारक हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वीजा समझौतों को उदार बनाने पर विशेष जोर दिया है। विदेश मंत्रालय की सक्रिय कूटनीति ने कई देशों को भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नीतियों में ढील देने के लिए प्रेरित किया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और वैश्विक भू-राजनीति में इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत का आर्थिक उदय और रणनीतिक महत्त्व अन्य देशों को भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और भारतीय

नागरिकों को अधिक सुगम यात्रा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी भी देश की पासपोर्ट रैंकिंग में उसकी आंतरिक सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और बेहतर बनाने के प्रयासों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस सुधार में योगदान दिया है। सुगम और पारदर्शी पासपोर्ट सेवाएं नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को और अधिक व्यवहार्य बनाती हैं। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंधों के कारण दुनिया भर के पासपोर्टों की रैंकिंग प्रभावित हुई थी। अब जब वैश्विक यात्रा धीरे-धीरे सामान्य हो रही है, तो देशों के बीच समझौते और यात्रा की बहाली रैंकिंग में सुधार का कारण है। भारतीय पासपोर्ट की इस क्रमबद्ध बढ़ती ताकत को बनाए रखना और उसे मजबूत करना सतत प्रक्रिया है। इसके लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। विदेश मंत्रालय को दुनिया के उन देशों के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए जो अभी भी भारतीय नागरिकों के लिए सख्त वीजा आवश्यकताएं रखते हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां भारतीय व्यापार, पर्यटन या छात्र समुदाय की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है। भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना चाहिए और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों का सम्मान करना और उनका प्रभावी ढंग से पालन करना किसी भी देश की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे अन्य देश उसके नागरिकों को अधिक वीजा स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मजबूत ढांचा किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्यटकों और व्यापारिक आगंतुकों के लिए सुरक्षित वातावरण का आश्वासन देता है। भारत को उन देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए जो ई-वीजा या वीजा-ऑन-अराइवल की पेशकश नहीं करते। सरकार को भारतीय पासपोर्टधारकों के लिए उपलब्ध वीजा-मुक्त/वीजा-ऑन-अराइवल देशों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित अपडेट और सार्वजनिक जागरूकता अभियान इसमें मदद कर सकते हैं। भारत को 'अतिथि देवो भव' की अपनी परंपरा के अनुरूप विदेशी पर्यटकों का स्वागत करना जारी रखना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आदान-प्रदान से भारत की 'सॉफ्ट पावर' बढ़ती है, जिसके बदले में अन्य देशों से वीजा उदारता प्राप्त होती है। भारत की विदेश नीति को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। इस नीति के आलोचकों का कहना है कि हाल में हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ जबकि चीन, टर्की आदि ने पाकिस्तान को खुला समर्थन देने की घोषणा की थी। उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों बार दोहराया कि भारत पाकिस्तान के बीच उन्होंने ही सीज-फायर करवाई है जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे का बार-बार खंडन किया।

दरअसल, किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसकी आर्थिक प्राथमिकताएं व भू-राजनैतिक (जियो पॉलिटिकल) बाध्यताओं से निर्धारित होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में जहां एक तरफ अमेरिका और रूस की नजर हमेशा भारत के बड़े बाजार पर रहती है वहीं चीन से संतुलन बनाए रखने के लिए इन्हें पाकिस्तान को भी साधना पड़ता है क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। इन सब दबावों के बीच भारत अपनी विदेश नीति तय करता है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> भारत को 'अतिथि देवो भव' की अपनी परंपरा के अनुरूप विदेशी पर्यटकों का स्वागत करना जारी रखना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और आदान-प्रदान से भारत की 'सॉफ्ट पावर' बढ़ती है, जिसके बदले में अन्य देशों से वीजा उदारता प्राप्त होती है। किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसकी आर्थिक प्राथमिकताएं व भू-राजनैतिक वाध्यताओं से निर्धारित होती है। हालांकि भारत की विदेश नीति को लेकर विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं

परिस्थितियां

श्रीराम शर्मा आचार्य

जीवन वृक्ष की जड़ मन के अंदर है। अक्सर बाहर की परिस्थितियां जीवन से मेल नहीं खातीं तब बड़ा दुख होता है। घर में अकेला कमाने वाला हूं, मेरी मृत्यु हो गई तो? पशुओं को कोई चुरा ले गया तो? कोई झूठा मुकदमा लग गया तो? इस प्रकार की आशंकाएं कल्पित होती हैं। जितना भय होता है, वास्तव उसका चौथाई भी नहीं आता। हम देखते हैं कि कई धनवान और बलवान अपने घर में ढाका पड़ा जाने, अपना कत्ल हो जाने की आशंका से रात भर चैन की नींद नहीं लेते। यद्यपि जैसा वे सोचते हैं, वैसी घटना जीवन भर नहीं होती और अपनी इंद्रियों का तो कहना ही क्या? वे यदि काबू में न हों तो हिरन की तरह चौकड़ी मारती हैं। अपने भोगों के लिए उनकी सदा 'और लाओ और लाओ' की रट लगी रहती है। दैनिक जीवन की ये अवस्थाएं मनुष्य को उलझन में डाल देती हैं। दुख, शोक, तृष्णा, चिंता, भय, क्रोध, लोभ, द्वेष की भावनाएं उसके मस्तिष्क पर अधिकार जमा कर उसे बड़ी दयनीय दशा में असहाय छोड़ देती हैं। वह शांति के लिए प्यासे मृग की तरह चारों ओर दौड़ता है परंतु दृष्टिदोष के कारण सफेद भूमि ही जल दिखाई पड़ती है, दौड़ कर वहां पहुंचता है, परंतु वहां धरा ही क्या था? दौड़ने के श्रम से पहले की अपेक्षा भी अधिक अशांति हो जाती है। धन कमाने के लिए अथर्म करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप करते हैं, सुख के लिए मायाचार करते हैं परंतु हाथ कुछ नहीं आता। जितना चाहते हैं, जितनी तृष्णा होती है, उसका शतांश भी प्राप्त नहीं हुआ तो ओस चाटने पर तृप्ति कैसे हो सकती है। एक कामी पुरुष रात-दिन सैकड़ों सुंदरियों का चिंतन करता रहता है, कितना ही प्रयत्न करने पर भी उसे उतनी स्त्रियां भोग के लिए नहीं मिल सकतीं। यदि नहीं मिलीं तो शांति कहां? संसार के निर्बाधित क्रम के अनुसार जो घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनसे हम बच नहीं सकते। वेशक, मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, प्रयत्न करने पर परिस्थितियों को बहुत कुछ अपने अनुकूल कर सकता है, परंतु यह न भूलना चाहिए कि मनुष्य-मनुष्य भी है। घटनाएं संसार के क्रम के साथ हैं, वे होती हैं, और होंगी। उनके प्रवाह से भगवान राम और योगिराज कृष्ण तक नहीं बच सके। परिस्थितियों से कोई नहीं बच सकता।

रीडर्स मेल

नजीरी फैसले की दरकार

खबर है कि राजस्थान में एक स्कूल की बिल्डिंग किन्हीं कारणों से टूट गई, यह हमारत एक शिक्षालय की थी और उसमें पढ़ने वाले बच्चों में से पांच काल के क्रूर गाल में समा गए, क्या यह विचार का विषय है, या फिर इसमें भी कोई गुंजाइश है सोचने-समझने की, क्या यह तंत्र का खोखलापन है, या फिर मोटी रकम जिम्मेदारी के नाम पर लेने वाले लोगों की विफलता है। आखिर, क्यों हमारत की जर्जरता के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होना चाहिए जबकि सरकार शिक्षा के लिए अच्छी खासी रकम खर्च करती है। इन पांच नौनिहालों की जान क्या इतनी सस्ती है कि वो किसी अधिकारी, कर्मचारी या सरकारी संस्था के अनदेखे रवैये या भ्रष्टाचार की वजह से आहूत हो जाएं। व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है, जो अभी दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है, अधिकारी कर्मचारी और तंत्र जब तक एक सूत्र और उद्देश्य से काम नहीं करेंगे और गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकेंगे तब तक ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना संभव नहीं, इस बार फैसला निर्णायक होगा तभी भविष्य के लिए नजीर बन पाएगी।

मनोज पुरुषार्थी, ई मेल से

डिजिटल माध्यमों में अश्लीलता

केंद्र सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए मनोरंजन के नाम पर अश्लील सामग्री दिखाने वाले 25 ओटीटी चैनल और ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। ये सभी बहुत समय से अश्लीलता फैला रहे थे। हालांकि इसे आधी-अधूरी और देर से हुई कार्रवाई कह सकते हैं। सवाल है कि प्रतिबंध के अलावा क्या इन ओटीटी चैनल और ऐप्स के मालिक और कर्तधर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? अगर नहीं तो, मतलब असली अपराधी बच गए, ऐसे में पूरी संभावना है कि ये ओटीटी चैनल और ऐप्स नाम बदल कर दोबारा बाजार में आएंगे और जब तक सरकार कार्रवाई करेगी अपना उल्लू सीधा कर चुके होंगे। यही नहीं, इनके अतिरिक्त अभी भी अश्लील सामग्री दिखाने वाले बहुत से ओटीटी चैनल और ऐप्स उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि उनके खिलाफ भी सरकार जल्द ही कार्रवाई करेगी। सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसी नीति बनाए जिससे डिजिटल माध्यम से अश्लीलता फैलाने वालों पर बंद दिनों में ही त्वरित सख्त कार्रवाई हो सके और ऐसे लोगों को फलने-फूलने का कोई मौका न मिले।

बृजेश माथुर, गाजियाबाद

भारत-मालदीव के सशक्त संबंध

वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत और मालदीव के संबंध रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के चलते भारत के लिए मालदीव एक प्रमुख साझेदार बन गया है। भारत ने हाल के वर्षों में मालदीव को बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सहायता प्रदान की है। वहीं मालदीव ने भी 'इंडिया फर्स्ट' नीति के तहत भारत के साथ गहरे संबंध बनाए रखे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु दोनों देशों ने आपसी समझ और सहयोग के जरिए रिश्तों को संतुलित रखा है। आज इन संबंधों के मायने केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये क्षेत्रीय शांति, विकास और आपसी सम्मान की दिशा में भी एक सशक्त साझेदारी को दर्शाते हैं।

महेन्द्र तिवारी, दिल्ली

letter.editorsahara@gmail.com

दिल-दिमाग की सेहत में मददगार चिया सीड

- चिया सीड...इन छोटे-छोटे बीजों के अनगिनत फायदे हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चिया बीज का वैज्ञानिक नाम 'सालिया हिस्पैनिका' है
- इसके बीज बहुत छोटे, सफेद या काले रंग के होते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर 'सुपर फूड' होते हैं, जो हमारे शरीर की कई जरूरतों को पूरा करते हैं
- अमेरिकी हाइपरी गाइडलाइंस के अनुसार, रोजाना 48 ग्राम से ज्यादा चिया सीड का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि इसे संतुलित तरीके से अपने रोज के खाने में शामिल करें तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित हो सकता है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

भारत में पत्रकारों के खिलाफ उत्पादतर मामले सरकारी अधिकारियों, धार्मिक मामलों और विरोध प्रदर्शनों की बाबत रिपोर्टिंग करने पर दर्ज किए जाते हैं। छोटे शहरों और नगरों के पत्रकार इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं, जिनका जीना मुहाल हो गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), दिल्ली के सहयोग से किए गए एक हालिया अध्ययन में यह बात कही गई है।

विजयेता सिंह, पत्रकार
@vijaita

मानव अस्तित्व के लिए रामबाण

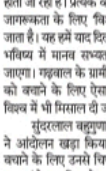

प्रकृति संरक्षण | शिव मोहन यादव

प्रकृति, मानव जीवन का मूल-स्रोत और आधार-बिंदु है। जल, वायु, पेड़-पौधे, जीव-जंतु-सब मानव जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हैं। वर्तमान अंधी दौड़ में हम निरंतर प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव-विविधता का विनाश होता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम शीघ्र नहीं संभले तो भविष्य में मानव सभ्यता के लिए गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। गढ़वाल के ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण और पेड़ों को बचाने के लिए ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी विश्व में भी मिसाल दी जाती है।

सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन खड़ा किया जिसमें आंदोलनकारी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे। 1973 में शुरू हुआ यह आंदोलन 'चिपको आंदोलन' नाम से जाना जाने लगा। केरल सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 'हरित क्रांति मिशन' शुरू किया जिसके अंतर्गत 'चूक्षमित्र' योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत सरकार ने नागरिकों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल में स्वीडन की युवा कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध आवाज उठाई। दुनिया को जागरूक किया कि जलवायु परिवर्तन के लिए कदम उठाना सरकार का ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्त्तव्य है। प्रकृति में सभी जीव और तत्व एक-दूसरे से जुड़े हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर ऑक्सीजन देते हैं। इससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, नदियां जल संचय करती हैं, और जीव-जंतु पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं। अगर यह संतुलन टूटा तो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो जलवायु परिवर्तन का संकट भी खड़ा हो जाएगा।

हम देख ही रहे हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और मौसम चक्र अस्त-व्यस्त हो गया है। यदि हमने अब भी प्रकृति संरक्षण को गंभीरता से नहीं

लिया तो भावी पीढ़ियों को भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। हम निरंतर जैव-विविधता को समाप्त होते देख रहे हैं। हर साल हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। शेर, बाघ, हाथी और गैंडे जैसे जानवर संकटग्रस्त हैं। यदि जैव-विविधता नष्ट हुई तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और इससे मानव जीवन प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। विगत वर्षों से हम देख ही रहे हैं कि पूंजीवादी दौर में मनुष्य समझ ही नहीं रहा है कि वह धरती को कहां लिए जा रहा है। प्रकृति हमें जीवन देती है, और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। छोटे-छोटे कदम उठाए जाने चाहिए जैसे पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग, ये सब बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि 'धरती हमारी मां है, और हम उसके संरक्षक हैं।' 'विश्व प्रकृति संरक्षण' दिवस (28 जुलाई) पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ सहअस्तित्व बनाए रखेंगे और भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और सुरक्षित धरती छोड़ेंगे। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।

शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप गार्डनिंग और वर्टिकल गार्डनिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संरक्षण के प्रति भी सजग रहना होगा। वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया जाना चाहिए। नदियों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं तो बेहतर। पानी की बर्बादी रोकने के लिए 'ड्रिप इरिगेशन' जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाए। प्लास्टिकरहित जीवनशैली अपनानी चाहिए जिससे सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। ऊर्जा संरक्षण के लिए भी हमें कदम उठाने चाहिए। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाया जाना बेहतर होगा। वनों से लेकर बड़ों तक को बिजली की बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एलईडी बल्ब जैसे एनर्जी-सेविंग उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।

एक और पहलू है, वन्य जीव संरक्षण। हम कई वर्षों से देखते आए हैं कि कई वन्य जीव तेंदुआ, चीता आदि शहरों में दिखाई दिए और कई गांवों में भी उनका आतंक देखने को मिला है। हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो न केवल वन्य जीव संरक्षित रहेंगे, बल्कि मानव जीवन भी संरक्षित हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकार शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार पर सख्त कार्रवाई करे। और हां, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विस्तार किया जाना भी हितकर होगा। कहना न होगा कि इससे मानव जीवन भी सुरक्षित और सुखमय बन पाएगा।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-परिसपुर, पुलिस स्टेशन-बाकीपुर, थानापुर, पटना से मुद्रित तथा न्यूज़ भवन, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। : स्वामीय संपादक - संजय तिवारी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2539935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6729
आर.एन.आई. नं. बीआईएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

53 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खोले जा चुके हैं अब तक देश भर की बैंक शाखाओं में, जिन्हें आधार और मोबाइल नंबर से जोड़े जाने के कारण बिना किसी लीकेज के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ है।

आजकल

समानता कायम करने की दिशा में उपलब्धि

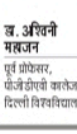

ब्र. अश्विनी महाजन
पूर्व प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

विश्व बैंक द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उपभोग में असमानताएं कम हुई हैं। यानी विश्व बैंक से लेकर तमाम संबंधित संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट में इस बात पर सहमति है कि भारत में उपभोग असमानताएं कम हुई हैं। लेकिन कई आलोचक इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वस्तुतः कोई भी सर्वेक्षण सभी पहलुओं में परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए इन तर्कों के आधार पर हम इसे नकार नहीं सकते कि तमाम रिपोर्ट गरीबी में कमी का संकेत दे रही हैं। यह भी समझना होगा कि सरकार की समावेशी नीतियों के कारण ही अत्यधिक गरीबी में कमी आई है

प्रतीकात्मक

हाल ही में जारी विश्व बैंक की 'स्प्रिंग 2025 पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' ने दुनिया में एक बहस शुरू की है। बहस का मुद्दा यह है कि क्या भारत वास्तव में दुनिया का चौथा सबसे समान देश बन गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है? वास्तव में देश और दुनिया में प्रचलित विमर्शों का यह रिपोर्ट खंडन करती है। देश में बड़ी तादाद में बुद्धिजीवी जो इससे पूर्व की रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए यह तर्क देते रहे हैं कि देश में आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ असमानताएं भी बढ़ी हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ी है, वंचित वर्ग के हालात पहले से अधिक बिगड़े हैं और यह असमानता आय और संपत्ति दोनों में दिखाई देती है। ऐसे में यदि कोई रिपोर्ट यह कहे कि देश में असमानता कम हुई है तो असमंजस स्वाभाविक ही है।

समझने की कोशिश करते हैं कि क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जैसे उसके आलोचक दावा करते हैं या उसमें कुछ सच्चाई है। और यदि यह सच है तो यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में समानताएं घटने के पीछे कारण क्या हैं।

असमानताओं को मापने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका गिनी चटांक माना जाता है। गिनी चटांक शून्य से एक तक होता है, जहां शून्य गिनी सह गुणांक पूर्णतः समानता की और एक पूर्णतः असमानता को दर्शाता है। नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनमिक रिसर्च और अन्य गृहस्थ आय सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार, 2023 में आय गिनी सह गुणांक 0.410 था जो 1955 में 0.371 से भी अधिक था। यदि संपत्ति के वितरण के बारे में विचार करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2023 में यह सह गुणांक 0.405 था जो 1955 में 0.341 से कहीं अधिक था, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 1955 में 0.392 से घटकर 2023 में 0.382 ही रह गया, लेकिन काफी ऊंचे स्तर पर बना हुआ है।

भारत में आय और संपत्ति में बढ़ती असमानताओं के बीच, अच्छी खबर यह है कि उपभोग में असमानताएं कम हो रही हैं। इसे अलग-अलग शब्दों में पहले यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में भारी कमी और बाद में विश्व बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में अत्यधिक गरीबी में बड़ी कमी दर्ज की गई है। हालांकि अत्यधिक गरीबी की परिभाषा 2.15 डालर प्रतिदिन से बदलकर तीन डालर प्रतिदिन कर दी गई है, फिर भी 2022-23 में केवल 5.3 प्रतिशत लोग ही अत्यधिक गरीबी से पीड़ित थे। वर्ष 2011-12 में यह आंकड़ा 27.1 प्रतिशत था। यदि इस परिभाषा को पहले की तरह 2.15 डालर ही रखा जाए, तो 2022-23 में गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत केवल 2.3 प्रतिशत ही रह गया है।

एक अधिक समतापूर्ण समाज की ओर भारत की यात्रा पिछले कुछ वर्षों में उसके गिनी सूचकांक में परिलक्षित होती है। 2011 में यह सूचकांक 28.8 था, जो 2022 में 25.5 तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि इस अवधि में विश्व बैंक के रिपोर्ट गृहस्थ उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है और इसमें आय और संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। उपभोग आधारित गिनी सहगुणांक असमानताओं को कम करके आंकता है, क्योंकि अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं। उसके मुकाबले आय आधारित समानताएं अधिक विस्तृत अवधारणा है और उस संदर्भ में भारत में आय और संपत्ति की असमानताएं वास्तव में बढ़ी है। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया गया सर्वेक्षण उपभोग को ठीक प्रकार से आकलन नहीं कर पाया। ऊपर के पांच प्रतिशत अमीर सामान्य सर्वेक्षण में अपने उपभोग को कम कर बताते हैं और उसे आधार पर निष्कर्ष सही नहीं होगा।

सभी पहलुओं पर विचार : भारत में वर्तमान सरकार की समावेशी नीतियों के कारण पहली बार इतने कम समय में ग्रामीण क्षेत्रों में तीन करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ घरों के निर्माण से अभावग्रस्त लोगों का जीवन बदला है। इसके साथ ही सभी घरों में बिजली, अधिकांश आबादी को पाइप से जल कनेक्शन और स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन की उपलब्धता, स्वथ ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक सीमा से कम आय वाले प्रत्येक पात्र परिवार को पांच लाख रुपये तक की मुफ्त द्वितीयक स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को गरीब करनेवाले कारकों को समाप्त कर रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि पहले भी सरकारें समाज के गरीब तबके के उपभोग में सुधार के नाम पर भारी धनराशि खर्च करती थीं, लेकिन खामियों के कारण भारी भ्रष्टाचार और लीकेज होता था। लेकिन जन धन बैंक खाते खोलने और इन सभी खातों को आधार व मोबाइल नंबर से जोड़ने से, बिना किसी लीकेज के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ।

यह भी समझना चाहिए कि हालांकि असमानताएं कम हुई हैं, लेकिन असमानताओं में कमी का श्रेय सरकारी सहायता और कुछ हद तक मुफ्त सुविधाओं को जाता है, फिर भी हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार अनंत काल तक गरीबों का समर्थन करती रहेगी। दीर्घकाल में हमें लोगों को इतना सक्षम बनाना होगा कि वे अपने परिवारों की जरूरतें पूरी कर सकें, जैसे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, पानी आदि। लोगों को आजीविका कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना होगा।

कृषि में प्रगति से विकसित भारत का लक्ष्य संभव

ब्र. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

विकसित कृषि के लिए विज्ञान एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। समय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर घटने एवं जलवायु परिवर्तन से फसलों के पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। इसलिए आज कृषि क्षेत्र के लिए शोध और नवाचार अनिवार्य है। वर्तमान सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में कृषि उत्पादन में पिछड़े जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिला सम्मिलित होगा। इसमें छोटे किसानों को आधुनिक एवं लाभकारी खेती की ओर बढ़ने पर बल दिया जाएगा। यह अनन्दाता के सम्मान और कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है।

ध्यातव्य है कि भारत कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 47 प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका पर निर्भर है। आज भी देश के विभिन्न राज्यों में कृषि के लिए पुरानी तकनीक और पुराने उपकरणों पर ही निर्भरता है। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास से वे अभी भी बहुत दूर हैं। दिसंबर 2024 की नेशनल बैंक आफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार किसानों की कमाई में खेती का योगदान 33 प्रतिशत है। किसान परिवारों की खेती से औसत मासिक आय केवल 4476 रुपये है। इसके अतिरिक्त खेती, पशुपालन, अन्य उद्यम, मजदूरी एवं सेवा आदि को मिलाकर किसान परिवार की औसत मासिक आय 13,661 रुपये है। देश के लगभग 55.4 प्रतिशत किसन परिवारों पर कर्ज है। क्या यह चिंताजनक नहीं है?

विगत दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक आमसभा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान में आए सुझावों के आधार पर कृषि विकास की रणनीति बनेगी। उन्होंने जन औषधि केंद्र की तरह फसल औषधि केंद्र खोलने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने किसानों की उपयोगिता और मांग आधारित शोध की जरूरत पर भी जोर दिया। आज हमें गंभीरता से यह समझने की जरूरत है कि भारत की वैश्विक कृषि उत्पादन में 7.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है तो वहीं राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि उत्पादों का 18 प्रतिशत योगदान है। ऐसे में कृषि क्षेत्र पर समग्रता और व्यापकता से विचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि विश्व बाजार में भारत की कृषि का निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा है, तथापि अनेक चुनौतियां हमारे सामने हैं। गेहूं, चावल, दलहन एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्यान्नों का समुचित और सुरक्षित भंडारण एक बड़ी चुनौती है।

आज जब विकसित कृषि एक बड़े संकल्प के रूप में उभर रही है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रदेश की जलवायु, वहां की मिट्टी एवं प्रकृति के अनुसार कृषि के लिए योजनाएं बने। वहां की आवश्यकता के अनुसार बीज, खाद, कीटनाशक एवं भंडारण सुविधा उपलब्ध करवाई जाएं। भिन्न-भिन्न प्रकार की जानकारियों एवं जागरूकता हेतु समय-समय पर किसानों से संवाद हों। स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जाए। विकसित कृषि के संकल्प के लिए यह आवश्यक है कि यथाशीघ्र बीज, उर्वरक और कीटनाशक एवट बने और उसे टेंट के प्रविधानों के साथ तत्काल लागू किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा भी है कि अमानक बीज, खाद एवं कीटनाशक गंभीर विषय है जिसे लेकर सरकार कड़ा कानूनी प्रविधान करेगी। राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए विकल्पहीन प्रतिबद्धता से योजनाएं बनाकर उन्हें शीघ्रता से लागू करना होगा। क्योंकि विकसित कृषि से ही विकसित राष्ट्र का संकल्प साकार होगा।

खरी-खरी

नौकरी और ईश्वर

प्रेमोद कुमार प्रेमकी

सरकारी नौकरी का मिलना ईश्वर के साक्षात्कार के समान है। वस्तुतः सरकारी संस्थान मंदिर की तरह होता है। जिस प्रकार सनातन धर्म में कोटि-कोटि के देवता हैं, उसी तरह सरकारी संस्थानों में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष साक्षात देव स्वरूप विद्यमान होते हैं। सरकारी संस्थानों में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर, वित्त आदि के प्रबंधन एवं नियमन के लिए विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं, जिनके शीर्ष पद पर आसीन सचिव/ प्रधान सचिव कहलाते हैं।

सनातन धर्म में भी विभाग वार ईश्वरों का वर्गीकरण किया गया है यथा, विद्या के लिए माता सरस्वती, धन के लिए मां लक्ष्मी, स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरि, दीर्घायु के लिए भोलेनाथ, ब्रश्रिश के लिए इंद्रदेव आदि विभागाध्यक्ष होते हैं जिन्हें भगवान कहा जाता हैं।

मृत्युलोक में प्रखंड, जिला प्रत्येक स्तर पर पद एवं कद के अनुसार कार्यालय प्रधान देवी-देवता विभिन्न पदाधिकारियों के रूप में मौजूद होते हैं, जो अन्य कर्मचारियों से स्वयं को श्रेष्ठ मानता है।

सरकारी संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मियों और पदाधिकारी के बीच वही संबंध होता है जो पुजारी और भगवान के बीच। स्थानांतरण, प्रोन्नति, अवकाश आदि के लिए निम्न वर्गीय एवं मध्यमवर्गीय कर्मचारी स्वरूप भक्तों को संपूर्ण सेवा काल में उच्च वर्गीय पदाधिकारी स्वरूप भगवान के कोप भाजन रहित कृपा और अनुकंपा पर आश्रित रहना पड़ता है। दूसरी ओर प्राइवेट संस्थानों में 'सबका मालिक एक है' ऐसी संकल्पना के तौर पर एक ही बास व प्रधान होता है।

ईश्वरीय आशीर्वाद मिलने पर इंसान को मानवीय जीवन से मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि नौकरी हासिल करने पर बेरोजगारी, गरीबी, पारिवारिक एवं सामाजिक तानों से मोक्ष मिल जाता है। धार्मिक स्थलों पर दैवीय लाभ प्राप्ति हेतु पुष्प, प्रसाद आदि चढ़ाने का रिवाज है, तो वहीं सरकारी स्थलों पर योजना लाभ की प्राप्ति हेतु चाय-पानी के रूप में चढ़ावा चढ़ाने का एवं प्राइवेट संस्थानों अथवा प्राइवेट एजेंसी के कार्यस्थल पर कंट्रैक्ट एवं प्रमोशन पाने के लिए मौद्रिक एवं मौखिक मक्खन मसाज किए जाने का प्रविधान देखने को मिल जाता है।

पोस्ट

क्या हम पाकिस्तान के साथ हमेशा के लिए क्रिकेट खेलना बंद कर सकते हैं? क्रिकेट का खेल कोई युद्ध का मैदान नहीं है। असली लड़ाई वह है जो हमारे सैनिक रोज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारा दुश्मन, आतंक का आका और एक नितांत नाकाम देश है।

शेफाली पैद्य@ShefVaidya

मनसा देवी हादसे के बारे में कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण हालात बिगड़े। जब भीड़ बढ़ रही थी तब शासन-प्रशासन क्या कर रहा था? बड़े अधिकारी क्या इस हादसे की जिम्मेदारी लेंगे? या फिर वही जांच कमेटी, जिसकी रिपोर्ट कभी नहीं आएगी और लोग चार दिन बाद सब भूल जाएंगे।

गगन प्रताप@GaganPratapMath

राजस्थान में स्कूल की छत गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं। यूपी में विद्यार्थियों के अभाव में स्कूलों का मर्जर हो रहा है। हमारा देश इन्हीं विरोधाभासी विडंबनाओं से बना देश है। इसमें अपने आप को जिंदा क्या लेना ही आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अतुल कुमार राय@AuthorAtul

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या भारतीय टीम को एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

अजय कुमार सक्सेना
क्या मनसा देवी हादसा प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के छठवें का महार्ह।

जनपथ

सीधी आखिर हो गई मालवीय की ऐंठ,
जो इतराता था कभी गोद वीन की बैठ।
गोद वीन की बैठ सबक जब उसने पाया,
त्राहि माम कह लौट पुनः भरत संग आया।
दुष्ट वीन के साथ मुहब्बत की नाबीती,
बीलका की भांति हुई है तब दुम सीधी!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तर प्रदेश डायरी

अपनों के 'विपक्षी स्वर' बढ़ा रहे चुनौती

अजय जायसवाल
रुग्ण बूढ़े ध्रुव, उत्तर प्रदेश

सिर पर विधानमंडल का मानसून सत्र। आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में हैट-ट्रिक लगाने का लक्ष्य। इन सब की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था तक के मुद्दों पर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर वार पर वार कर रहा है। इनमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सबसे आगे हैं। उनके प्रहार पर तो सरकार के मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक पलटवार कर रहे हैं, लेकिन हाल-फिलहाल में 'अपनों' के सवालों की नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है। सहयोगी दलों से लेकर विधायक-मंत्रियों की कई मामलों में असहमति तो सामान्य बात है, लेकिन इधर असहमति की धार से सरकार की नीति, योजनाओं, कानून व्यवस्था और सबका साथ-सबका विकास के दावों पर भी घाव लग रहा है। पहले निषाद पार्टी और फिर अपना दल (एस) से गठबंधन में तनाव की बात सामने आई और अब तो गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा की मंत्री और नेता भी खुलकर कानून-व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर रही हैं।

कानपुर देहात की अकबरपुर-रनियां विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं बाल विकास, पुष्टाहार एवं महिला कल्याण राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पिछले दिनों न केवल अपनी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया, बल्कि ब्राह्मणों की उपेक्षा का आरोप भी मढ़ा। मंत्री ने एक मामले में अकबरपुर के कोतवाल व लालपुर चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग को लेकर 24 जुलाई को साढ़े छह घंटे धरना दिया। आश्वासन पर भी कार्रवाई न होने पर 25 जुलाई को उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा, 'ऐसा लगता है कि हम विपक्ष में हैं और सरकार अफसरों की है। मेरी पार्टी के एक बड़े क्षेत्रीय नेता और कोतवाल सतीश सिंह एक ही जाति के हैं। दूसरी पार्टी की सरकार होती तो मंत्री को थाने नहीं जाना पड़ता। प्रदेश में ब्राह्मणों को सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी बात मनवानी है तो एकजुट होकर नेतृत्वकर्ता तय करना होगा।' भाजपा संगठन को भी यह कहकर एक तरह से चुनौती दी कि पार्टी कोई एकराज लेती है तो ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए प्रदेशभर में यात्रा निकालेंगे। इससे भी ज्यादा मुश्किल उन्होंने बसपा की प्रशंसा करके कर दी। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2004 में बसपा सरकार के दौरान बहन जी (मायावती) ने मुझे थाने जाने से मना किया, लेकिन काम तुरंत हो गया था।

कानपुर में समर्थकों के साथ गुरुवार को धरने पर बैठी राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला। फाइल

मंत्री के 'विपक्षी स्वर' पर विरोधी दलों को कानून-व्यवस्था के सवाल ही ब्राह्मणों की उपेक्षा को लेकर सरकार को घेरने का नए सिरे से बहाना मिल गया है। अखिलेश लगातार भाजपा नेताओं के ऐसे बयानों को पोस्ट कर अपने आरोपों को सही ठहराते रहे हैं। सरकार के अंदर गुटबाजी का मुद्दा भी उठाते हैं। सवाल उठाने वाली प्रतिभा शुक्ला अकेली नहीं हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने भी बिजली व्यवस्था की तमाम खामियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर योगी सरकार के दावों पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। कुशीनगर की भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष नूतन दुबे ने भी जीडियो जारी कर हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। पूर्व में भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की सरकार से सीधी तनातनी का मामला भी सुर्खियों में रहा है। दूसरी तरफ सहयोगी दल भी सरकार-संगठन पर दबे-छिपे अंदाज में निशाना साधते रहे हैं। अपना दल (एस) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल बिना नाम लिए योगी पर हमला बोल पार्टी को तोड़ने की साजिश रचने के सवाल खड़े करते हैं। निषाद पार्टी के मुखिया व मंत्री संजय निषाद भी अपने बयानों से जब-तब आगी तेवर दिखते रहे हैं।

भाजपा और सरकार, अपने नेताओं-मंत्रियों के 'विपक्षी स्वर' से होने वाले नुकसान को अच्छे से समझती है। यही कारण है कि अपनों की शिकायतें दूर करने के लिए नए सिरे से मुख्यमंत्री मंडलाकर एनडीए के विधायक-सांसदों के साथ बैठकें कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की समस्याएं, शिकायतें सुनकर उन्हें तवज्जो देने की हिदायत अफसरों को दी जा रही है, ताकि बाद में असहमति के सुर न सुनाई दें। मुख्यमंत्री बताते हैं कि संवाद और समीक्षा केवल एक बैठक नहीं, बल्कि शासन की नई कार्यसंस्कृति का संदेश है, जहां योजनाएं सिर्फ फाइलों में नहीं, जनता के जीवन में बदलाव लाने वाली साबित हों। अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि संवाद के इस माडल को प्रदेशभर में लागू करें, ताकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र हर योजना, हर कार्य में परिलक्षित हो। अब यह रणनीति कितना कारगर होगी और जनता तक सरकार कितना संदेश पहुंचा पाएगी, यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे।

छत्तीसगढ़ डायरी

मतांतरण के विरुद्ध ठोस कानून

सतीश चंद्र श्रीवास्तव
संपादकीय प्रभारी, रायपुर

बांटो और विस्तार करो। मतांतरण के मामले में यह नारा शत प्रतिशत प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। माओवादी हिंसा प्रभावित नारायणपुर की लौ जाए जाने के प्रयास में शुक्रवार को भिलाई स्टेशन पर कोरबा के आधार कार्ड वाली नन के साथ पकड़ा जाना मिशनरियों के नेटवर्क का प्रमाण है। मिशनरियों के लिए कमजोर कानून हथियार है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी इनका सवाल है। प्रदेश सरकार की मानें तो फरवरी 2024 से नए विधेयक की पांडुलिपि (ड्राफ्ट) तैयार है। डेढ़ वर्ष बाद भी कानून बनने का इंतजार है। यद्यपि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुले मंचों से घोषणा कर चुके हैं कि सख्त कानून से मतांतरण की नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी गृहमंत्री विजय शर्मा को सौंप रखी है।

उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में यदि छांगुर द्वारा मुस्लिम मतांतरण का मुद्दा छाया हुआ है तो छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत में मिशनरियों की गतिविधियां लगातार चर्चा में हैं। मतांतरण बस्तर और जशपुर के आदिवासी बहुल इलाकों तक सीमित नहीं है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग-भिलाई में भी विस्तार हो चुका है। एससी-एसटी वर्ग के साथ प्रदेश के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) में साहू समाज मतांतरण से सर्वाधिक प्रभावित हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू कड़वे अंदाज में कहते हैं कि सत्ताधारी बिलबिला उठेंगे अगर पूछा जाए कि 'पालिटिकल बिल' के अभाव में बिल (विधेयक) किस बिल (छिद्र) में घुस गया? मतांतरण के विरुद्ध कड़े कानून का चुनावी वादा कहां गया?

मतांतरण का विरोध करने वाले संगठनों के लोग कठोर कानून के अभाव में स्वयं को असहाय स्थिति में बता रहे हैं। उनके अनुसार यह कड़वा सच है कि माओवादियों, मिशनरियों और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अपने-अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को ही दांव पर लगा दिया है। अंतिम संस्कार की जमीन तक के लिए गांवों में झगड़े हो रहे हैं। सामान्य रूप से शैव परंपरा को मानने वाले, देवी के उपासक व प्रकृति पूजक आदिवासियों की पूजन और जीवन पद्धति बदल रही है। देव स्थान के समानांतर प्रार्थना घर स्थापित हो रहे हैं। जल-जंगल-जमीन के लिए संघर्ष की सीख देने वालों ने विदेशी धन के लोभ से जीवन पद्धति पर ही प्रहार कर दिया है।

हिंसा प्रभावित नारायणपुर की पीड़ित बेटियें भिलाई स्थित 'सखी केंद्र' भेजी गई हैं। वे उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं जिनके सदन कन में माओवादियों की पकड़ के कारण अभी भी सुरक्षा बलों के केंद्र नहीं स्थापित हो सके हैं। लड़कियों को पता नहीं था कि वह कहां और क्या करने जा रही हैं। इनकी मानव तस्करी के आरोप में आगरा की वंदना फ्रांसिस के साथ गिरफ्तार प्रीति मेरी के पास कोरबा का आधार कार्ड है। पहले वह जिले के एक सुदूर गांव में केरल की संस्था द्वारा संचालित मिशनरी अस्पताल में काम करती थीं। उस गांव में सरकारी अस्पताल खुलने के बाद मिशनरी अस्पताल बंद हुआ तो वह मध्य प्रदेश के डिंडौरी में सक्रिय रही और अब आगरा पहुंच चुकी है। इस मानव तस्करी में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला आदिवासी युवक सुखमन मंडावी तीसरी बार यह काम कर रहा था।

पूर्व विधायक और आदिवासी नेता राजाराम तोमड़े के अनुसार आदिवासियों के कई समुदायों में 50 प्रतिशत तक ईसाई बन चुके हैं। मिशनरियों का बांटो और बिस्तार करो का सूत्र भी स्पष्ट है। समाज को जातीय आधार पर बांटो, लड़ाओ और स्वार्थ पैदा करो। यह गठजोड़ इसलिए भी चिंताजनक है कि वामपंथी बुद्धिजीवियों ने आदिवासियों को पहले भड़काया कि वह हिंदू या सनातनी नहीं हैं। पूरे समाज से काटने के बाद गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए जीवन में संघर्ष करने वाले लोगों का मतांतरण कराना आसान हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गैर सनातनी वोट बैंक की इच्छा रखने वालों ने राजनीतिक संरक्षण दिया। दूसरा पक्ष तरफ सत्ता परिवर्तन के बाद मतांतरण के विरुद्ध ठोस कानून के चुनावी वादे का इंतजार कर रहा है।

प्रीति मेरी : मतांतरण की आरोपित। फाइल

सुखमन मंडावी : मतांतरण का आरोपित। फाइल

विधानसभा के अंदर फरवरी 2024 में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने मतांतरण के विरुद्ध विधेयक की यह कहते हुए हवा निकाल दी थी कि विपक्ष से विचार-विमर्श किए बिना ही मसौदा तैयार कर लिया गया। इससे पहले तत्कालीन मंत्री (वर्तमान सांसद) बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया था कि कांग्रेस के शासन काल में 3400 से अधिक शिकायतें पहुंचीं, परंतु सिर्फ 34 में ही केस दर्ज हुए। यह भी सच है कि स्थिति बदली है। वर्ष 2023-24 में पुलिस तक 16 शिकायतें पहुंचीं और नौ में केस दर्ज हुए तो वर्ष 2024-25 में 50 शिकायतें पहुंचीं और 23 केस दर्ज हुए।

आंकड़े बता रहे हैं कि समाज बेचैन है। संघर्ष बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है कि मंजगा का दौर समाप्त हो और ठोस कानून पर कार्रवाई शुरू हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा तथा कठोर कानूनी प्रविधान लागू होने के साथ मतांतरण पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

****

दैनिक जागरण
आदतें ही हमारे स्वभाव का निर्माण करती हैं

भारत और भगदड़

यह बड़े शर्म और दुख की बात है कि भगदड़ की एक और जानलेवा घटना घट गई। इस बार यह घटना हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह भगदड़ यही बता रही है कि इस तरह की पहले की घटनाओं से कहीं कोई सबक नहीं सीखा गया। हाल के समय में भगदड़ की कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं। कुंभ में भगदड़ मचने से अनेक लोग मारे गए थे। इसके बाद बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में आयोजित समारोह में भगदड़ मचने से कई क्रिकेट प्रशंसकों की मौत हो गई। हाल ही में पुरी में भगदड़ जानलेवा साबित हुई। भगदड़ की घटनाओं के सिलसिले में हाथरस के एक आश्रम में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की घटना को भी नहीं भूला जा सकता। आखिर ऐसी कितनी घटनाओं के बाद शासन और प्रशासन चेतेगा। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भगदड़ की घटनाएं लगभग वैसे ही कारणों से रह रहकर होती रहती हैं, जैसे पहले हो चुकी होती हैं। हर बार जांच, कठोर कार्रवाई करने, सबक सीखने की बातें की जाती हैं, लेकिन नतीजा के ढाक के तीन पात वाला है। न तो शासन-प्रशासन कोई सबक सीख रहा है और न ही आम जनता संयम एवं अनुशासन का परिचय देने की आवश्यकता समझ रही है। भगदड़ की घटनाओं का सिलसिला जारी रहने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी भी होती है, क्योंकि इन घटनाओं से यही संदेश जाता है कि भारत का शासन-प्रशासन भगदड़ रोकने में पूरी तरह नाकाम है। सार्वजनिक स्थलों पर भगदड़ की घटनाएं दुनिया के अन्य देशों में भी होती हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी अपने देश में होती ही रहती हैं।

मनसा देवी मंदिर में भगदड़ का कारण करंट फैलने की अफवाह को बताया जा रहा है। क्या इस तरह की अफवाह को रोका नहीं जा सकता था? हमारा प्रशासन कोई अनुमान लगाने में इतना अक्षम क्यों है? क्या इसका कारण उसकी संवेदनहीनता है अथवा यह कि संबंधित अधिकारी यह जानते हैं कि कैसी भी घटना हो जाए, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आखिर हम दुनिया के अन्य देशों से कोई सबक सीखने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो सकता कि सार्वजनिक स्थलों और विशेष रूप से धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों में लोग कुचलकर मारे जाएं। अच्छा यह होगा कि सरकारें भगदड़ की घटनाओं को लेकर प्रशासन को सच में जवाबदेह बनाना सीखें। इसके साथ ही आम लोगों को भी जापान जैसे देशों के लोगों से अनुशासन सीख लेनी होगी। शासन-प्रशासन और आम जनता को अपने हिस्से की जिम्मेदारी इसलिए निभानी होगी, क्योंकि आने वाले समय में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ का दबाव और अधिक बढ़ेगा।

पीड़ितों को राहत

साइबर ठगी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं, साइबर अपराधी उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। यद्यपि बिहार में साइबर सेल इस पर नियंत्रण को लेकर काफी सक्रिय है और समय रहते कार्रवाई भी की जाती है, पर पीड़ितों की ठगी गई राशि की वापसी में विलंब उनके लिए परेशानी का कारण भी है। ईओयू ने इसके निदान की पहल की है, जिससे यह आशा की जा सकती है कि पीड़ितों की परेशानी कम हो सकेगी। हालांकि, इस पर स्वीकृति के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह मुद्दा लगातार उठ भी रहा था कि पीड़ितों को आखिर अपनी ही राशि की वापसी के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी इसमें काफी समय लग जाता है। जब किसी के साथ आनलाइन धोखाधड़ी होती है तो तुरंत शिकायत के बाद संबंधित बैंक खाते में स्थानांतरित की गई राशि साइबर सेल की पहल पर रोक दी जाती है। इससे पीड़ित पक्ष की रकम बहुत हद तक बच तो जाती है, पर इसकी वापसी की प्रक्रिया में काफी विलंब होता है। आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई (ईओयू) के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो साइबर ठगी की रकम वापसी के लिए पीड़ितों को प्राथमिकी की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। आनलाइन शिकायत और कार्रवाई रिपोर्ट ही इसके लिए पर्याप्त होगी। इसके साथ ही आइटी एक्ट से जुड़े मामलों में जांच भी अवर निरीक्षक रैंक के पदाधिकारी से कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इससे मामलों की जांच में तेजी आ सकेगी, क्योंकि जांच अधिकारी अधिक संख्या में होंगे। इस पर तीव्रता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ितों की समस्या का हल हो सके।

यह प्रयास जरूरी है कि साइबर अपराध के पीड़ितों को रकम की वापसी जल्द से जल्द हो

मताधिकार का स्पष्ट आधार है नागरिकता

ए. सूर्यप्रकाश

संविधान से लेकर जनप्रतिनिधि कानून में स्पष्ट है कि केवल भारतीय नागरिक ही देश के मतदाता हो सकते हैं। इसलिए नागरिकता और मतदान के अधिकार को अलग करके नहीं देखा जा सकता

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक मोर्चे पर तकरार जारी है। तकरार में एक मुद्दा नागरिकता और मताधिकार का भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। राजनीतिक कोलाहल से इतर देखा जाए तो यह संवैदनशील एवं महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके गहरे निहितार्थ हैं, क्योंकि संविधान यह प्रविधान करता है कि 25 साल से अधिक का कोई मतदाता देश के किसी भी हिस्से से विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसलिए यह चुनाव आयोग का दायित्व बन जाता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मतदाता न बनने पाए जो भारत का नागरिक न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को संविधान ने पर्याप्त अधिकार भी दिए हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावली के रखरखाव तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचनों के संचालन की शक्ति देता है और उसके कार्यों को परिभाषित करता है। वहीं, अनुच्छेद 326 में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु इस संबंध में विधि द्वारा यथानिर्धारित तिथि को 18 वर्ष से कम न हो और जो अन्यथा अयोग्य घोषित न किया गया हो, ऐसे किसी भी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

नागरिकता का यही संदर्भ जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1950 की धारा 16 में है। इसके अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का भी पात्र नहीं। इस तरह संविधान और संसद द्वारा पारित निर्वाचन संबंधी कानून दोनों स्पष्ट रूप से यह प्रविधान करते हैं कि केवल भारतीय नागरिक को ही मतदान का अधिकार मिल सकता है। जनप्रतिनिधि कानून की धारा 14 यह भी निर्धारित करती है कि जहां तक मतदाता सूची को तैयार करने का सवाल है तो यह कवायद संबंधित वर्ष की जनवरी, अप्रैल, जुलाई या अक्टूबर से शुरू की जा सकती है। धारा 21 चुनाव आयोग को लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव से पहले उपयुक्त तिथि के संदर्भ में अपेक्षाओं के अनुरूप मतदाता सूची तैयार करने या उसे संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है। इसे देखते हुए मतदाता सूची से जुड़ी चुनाव आयोग की कवायद पर सवाल उठाना बेतुका ही कहा जाएगा। इसका विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के तर्क गले नहीं उतरते।

अधोक्षर हाफ़ाज़

इस संदर्भ में एक बहुत दिलचस्प मामला है। यह मामला किसी और से नहीं, बल्कि खुद नेहरू-गांधी परिवार से जुड़ा है। इसमें गैर-भारतीय नागरिक के मतदाता बनने और फिर एक जागरूक नागरिक द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उस नाम को मतदाता सूची से हटाना पड़ा था। यह जनवरी 1980 की बात है। दिल्ली में मतदाता सूची संशोधित की जा रही थी। उस संशोधन में सोनिया गांधी का नाम शामिल किया गया था, जबकि उस समय वे इटली की नागरिक थीं। उस समय जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 लागू था। उसके अंतर्गत सूची में शामिल होने के लिए मतदाता को अपना नाम, पता, जन्मतिथि की जानकारी के साथ यह उद्घोषणा भी करनी थी कि वह भारत का/की नागरिक है। इन दावों के सत्यापन के बाद ही चुनाव प्राधिकारी संस्था संबंधित व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करती थी। उस कानून में यह प्रविधान भी था कि किसी गलत दावे या गलत प्रतिनिधित्व के मामले में ऐसा करने वाले व्यक्ति को छह महीनों की कारावास तक हो सकती थी।

सोनिया गांधी का मूल नाम एंटोनिया माइनो था। उनका विवाह 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी से हुआ था। नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने पर पांच साल बाद 1973 में वे भारत की नागरिक बन सकती थीं, पर उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। अपनी इतालवी नागरिकता के बावजूद नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी के साथ उनका नाम भी जोड़ दिया गया था। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को राजनीति में उतारा। चूंकि राजीव औपचारिक राजनीति में उतर गए थे और उस स्थिति में सोनिया के लिए अपनी इतालवी नागरिकता को कायम रखना विरोधियों के हाथों में एक मुद्दा थमा देता, इसलिए सोनिया गांधी ने अंततः 2 अप्रैल, 1983 को नागरिकता के लिए आवेदन किया और 30 अप्रैल, 1983 को उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। हालांकि इससे पहले ही बिना भारतीय नागरिकता के उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। इसे लेकर एक प्रबुद्ध नागरिक ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाना पड़ा था। नागरिकता और मताधिकार के जिस विवाद के केंद्र में स्वयं सोनिया गांधी रहीं, उसे देखते हुए कांग्रेसियों का यह राग अलापना समझ नहीं आता कि नागरिकता के पहलू का मतदान अधिकार से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।

समझ नहीं आता कि विपक्षी दलों के नेता बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन की कवायद को लेकर क्यों आसमान सिर पर उठाए हुए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो यहां तक कहने में लगे हैं कि चुनाव आयोग को भाजपा के निर्देश पर काम न करते हुए कानून के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। चुनाव आयोग को बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए कि वह प्रत्येक कानूनी कसौटी के अनुसार आगे बढ़े। इस संदर्भ में उसे अपेक्षित अधिकार भी मिल हुए हैं। अनुच्छेद 326 से लेकर निर्वाचन संबंधी कानून यह स्पष्ट करते हैं कि केवल भारतीय नागरिक ही देश के मतदाता हो सकते हैं। चुनाव आयोग अपने इस कर्तव्य से बंधा हुआ है। वह ऐसी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता कि कोई गैर-भारतीय नागरिक मतदाता सूची का हिस्सा बन जाए।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

बाजार संभावनाओं को भुनाने का मौका

डा. जयंतीलाल भंडारी

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है

देश में लोगों की बढ़ती आमदनी, शहरीकरण के कारण बदलती जीवनशैली और खानपान की आदतों में परिवर्तन के कारण भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाजार आकार तेजी से बढ़ रहा है। हाल में डेलाइट और फिक्की द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक देश में परिवारों के खाद्य बजट का वित्त वर्ष 2000-01 में अनाज और दालों पर 40 प्रतिशत खर्च किया जाता था, वह वित्त वर्ष 2023-24 में यह खर्च घटकर महज 14 प्रतिशत पर पहुंच गया। देश में खानपान तो लगभग हर आय वर्ग का बदला है, लेकिन शहरी संपन्न वर्ग अब अपने मासिक खाद्य बजट का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा पैकेज्ड फूड, बाहर खाने और डिलीवरी पर खर्च कर रहा है। ग्रामीण भारत में भी इसी तरह का बदलाव दिख रहा है। ग्रामीण खपत अनाज से ऐसे पदार्थों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार कृषि उत्पाद जब तैयार भोजन का रूप लेता है तो उसके मूल्य में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होती है। पीएचडी चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक भारत के खाद्य प्रसंस्करण बाजार का आकार वर्ष 2023 में करीब 307 अरब डालर था, इसके वर्ष 2030 तक करीब 700 अरब डालर पर पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से निर्यात बढ़कर वर्ष 2030 तक 125 अरब डालर होने की उम्मीद है।

इसे देखते हुए भारत ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए व्यापक सुधार शुरू किए हैं। भारत खाद्य प्रसंस्करण में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ), प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण, पृष्ठतल आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) जैसी बहुआयामी पहलों के माध्यम से पौष्टिक दुनिया के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले दस वर्षों में भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का एफडीआइ प्राप्त हुआ है। इस दौरान हमारी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 15 गुना बढ़कर दो सौ लाख टन से अधिक हो गई है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कई अन्य पूंजी आधारित उद्योगों की तुलना में ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण के तहत- डेरी, फल एवं सब्जी, अनाज, मांस, मछली एवं पोल्ट्री तथा उपभोक्ता वस्तुएं, पैकेट बंद खाद्य और पेय पदार्थ आते हैं।

बदलती जीवनशैली ने बदली खानपान की आदतें। फाइल

सरकार ने इन क्षेत्रों की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए सुनिश्चित किए गए एक लाख करोड़ रुपये की वित्त पोषण सुविधा से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाभान्वित हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार लाजिस्टिक्स क्षेत्र को बुनियादी ढांचे का दर्जा दे चुकी है। वर्ष 2020 से शुरू की गई किसान ट्रेनें भी खाद्य प्रसंस्करण बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न फलों, खाद्यान्नों और फूलों की खेती के लिए निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) का गठन किया गया है। मौजूदा 'कृषि-क्लस्टरों' को मजबूत करने और अधिक उत्पाद-विशेष वाले क्लस्टर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। छोटे फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को वित्त, तकनीक और अन्य तरह की मदद पहुंचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 'केंद्रीय प्रायोजित पीएम फार्मलाइजेशन आफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना' चला रही है। इस योजना के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे कच्चे माल की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए हर जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान करें। एक जिला-एक उत्पाद के आधार पर चुने गए उत्पादों का प्रोत्ढक्षन करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर मदद दी जा रही है। वस्तुतः खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि और विनिर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। यह कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसमें भारत अभी बहुत पीछे है। भारत में कुल खाद्य उत्पादन का 10 प्रतिशत से भी कम हिस्सा प्रसंस्कृत होता है। सब्जियों के लिए प्रसंस्करण स्तर 2.7 प्रतिशत, फलों के लिए 4.5 प्रतिशत, मत्स्य पालन के लिए 15.4 प्रतिशत और दूध के लिए 21.1 प्रतिशत है।

भारत के खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में पीछे रहने का एक बड़ा कारण खाद्यान्न भंडारण का अभाव है। अनाज के भंडारण की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से 12 से 14 प्रतिशत तक खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। कृषि उपज हासिल करने के तुरंत बाद किसानों को उसे बेच देना पड़ता है। देश में खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में भंडारण की क्षमता आधी से भी कम करीब 1450 लाख टन ही है। उम्मीद है कि सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत धन-धान्य और समृद्धि योजना से इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में बढ़ती हुई आर्थिक, निर्यात और रोजगार संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार को इस सेक्टर के समक्ष आ रही बाधाओं का निराकरण करना चाहिए। खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। कटाई के बाद फसलों की बर्बादी रोकने, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था, तकनीकी उन्नयन और लाजिस्टिक सुधार से देश का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तेजी से बढ़ेगा।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

चिंता और चिंतन

चिंता और चिता में केवल बिंदु मात्र का अंतर है। यह दो मानसिक अवस्थाएं हैं, जो विचारों और भावनाओं को अभिव्यंजित करती हैं। जीवित मनुष्य चिंता करने से अवसाग्रस्त होकर अपने शरीर को नष्ट कर देता है तथा चितामि प्राणशून्य शरीर को भस्मीभूत कर देती है। चिंताग्रस्त व्यक्ति अत्यधिक नकारात्मक भावजगत में जीवन जीता है, जिसके कारण लोक में विकास की मुख्यधारा से अलग पड़ जाता है। चिंता भविष्य की अनिश्चितताओं और संभावित भय के संदर्भ में होती है, जिससे व्यक्ति निरुत्साही और तनावग्रस्त होकर अपनी सृजनात्मक क्षमता से वंचित हो जाता है। चिंता से प्रभावित व्यक्ति की सोचने-समझने की शक्ति का ह्रास हो जाता है। जबकि चिंतन एक सकारात्मक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी समस्या के निदान के संदर्भ में गहनता से विचार मंथन और तर्क-वितर्क से रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर जीवन को समुचित गति-मति प्रदान करता है।

जीवन में आने वाली बाधाएं और अनुकूलताएं वस्तुतः मनुष्य को बहुत अनुभव और ज्ञान प्रदान करती हैं। चिंता नकारात्मक और तनावग्रस्त होती है, जबकि चिंतन सकारात्मक और रचनात्मक होता है। चिंता में प्रायः व्यक्ति समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जबकि चिंतन समस्या का समाधान निकालने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। चिंता से विमुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपनी नकारात्मक भावनाओं पर अंकुश लगाकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष व्यक्ति हुए हैं, जिनके जीवन में अत्यंत गंभीर और विषम परिस्थितियां आईं, किंतु उन्होंने पलायनवाद को नहीं अपनाया, अपितु आत्मबल और विवेक से समस्या का समाधान निकाला। आत्मबल का मुख्य आधार है-सत्य और प्रेम। चिंता जीवन की विकासधारा के लिए व्यवधान है और चिंतन उसका समाधान है।

आचार्य नारायण दास

व्यवस्था की विफलता

सोनम लववंशी

देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं

राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से सात मासूम बच्चों की जान चली गई। राजस्थान विद्यालय शिक्षा विभाग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 82 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में से 8,308 स्कूल भवनों को जर्जर और खतरनाक घोषित किया गया है। इन स्कूलों में बच्चे लकड़ी की बल्लियों या लोहे की चादरों से टिकी दीवारों के नीचे पढ़ने को विवश हैं। न पानी की निकासी है, न रोशनी की व्यवस्था, और न ही कोई संरचनात्मक सुरक्षा। झालावाड़ की यह घटना न पहली है, न आखिरी। हर बार की तरह इस बार भी सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता मुआवजे या एक जांच समिति के दायरे में ही सिमट कर रह जाएगी। देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ने जाते हैं। क्या यही है 'शिक्षा का अधिकार'? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआइएसई) 2021-22 की रिपोर्ट बताती हैं कि भारत में 1.45 लाख से अधिक सरकारी स्कूल भवन जर्जर या खतरनाक स्थिति में हैं।

शिक्षा के नाम पर 'डिजिटल क्लासरूम', 'स्मार्ट स्कूल', और 'मिशन समग्र शिक्षा' जैसी बड़ी योजनाएं तो बनाई गई हैं, लेकिन बुनियादी सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं बजट के अंतिम पायदान पर रह जाती हैं। यह केवल राजस्थान की बात नहीं है। बिहार के सासाराम में 2023 में स्कूल की छत गिरने से दो बच्चों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं बार-बार सामने आती रही हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश के लगभग 35 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में आज भी शौचालय नहीं हैं, और करीब 20 प्रतिशत स्कूलों की छतों में लीकेज है।

देश में शिक्षा के दो चेहरे हैं। एक वह जो स्मार्ट बोर्ड, सीसीटीवी और वातानुकूलित कक्षाओं से सजा है, और दूसरा वह जो उखड़ते प्लास्टर, टपकती छतों और टूटी खिड़कियों से जूझता है। यह फर्क केवल संसाधनों का नहीं, लोकतंत्र के आत्मा पर पड़े गहरे धब्बे का है। संविधान ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, पर क्या यह अधिकार सिर्फ सुविधा-संपन्नों के लिए है? झालावाड़ में गिरी स्कूल की छत ने केवल मासूम बच्चों को नहीं कुचला, सरकारी मशीनरी की संवेदनहीनता को भी बेनकाब कर दिया। झालावाड़ की त्रासदी केवल चेतावनी नहीं, सिस्टम की विफलता की खुली किताब है। अगर अब भी सरकारें नहीं चेतीं, तो अगली बार गिरने वाली दीवारें केवल ईंट-पत्थर की नहीं होंगी, ये देश की उम्मीदों और नागरिक जिम्मेदारियों की भी होंगी। और तब कोई मुआवजा न तो किसी मासूम की जान सहेज पाएगा, न ही इस देश का भविष्य।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जनभावना समझे कांग्रेस

'खुद को क्षति पहुंचाती कांग्रेस' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने कांग्रेस के आत्मघाती आचरण को संदर्भित किया है। दरअसल कांग्रेस अपनी नींव मजबूत करने के बजाय भाजपा के बनाए महल को गिराने में अपना समय और श्रम व्यर्थ करने में लगी हुई है। इसमें उसे इस बात से भी मतलब नहीं है कि देश की चुनाव व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ वही लोग शामिल हों, जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं। और उन लोगों का नाम भी मतदाता सूची से हटाया जाए, जो मृत हो चुके हैं अथवा स्थायी रूप से कहीं अन्यत्र बस गए हैं। प्रश्न उठाने का यह कोई वाजिब कारण नहीं हो सकता कि यह काम विधानसभा चुनाव के समय क्यों हो रहा है, लोकसभा चुनाव के वक्त क्यों नहीं? अच्छा विचार और अच्छे कार्य हमेशा सराहनीय होते हैं समय चाहे कोई भी हो। इस समय देश घुसपैठ की त्रासदी से गुजर रहा है। क्या ही अच्छा होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इस समस्या से निपटने की भरसक कोशिश करते। देश की जनता अच्छे और बुरे का फर्क अच्छी तरह जानती है। मोदी का तीन बार प्रधानमंत्री बनना उसकी समझ का ही परिचायक है। अतः कांग्रेस यदि खुद को वाकइ में मजबूत कर सत्ता में वापसी चाहती है तो उसे अहंतावाजी के पैंतरे छोड़कर जनता के दिलों को जीतने का प्रयास करना चाहिए।

वेद्प्रकाश पाण्डेय, अंबेडकर नगर, यूपी

बढ़ रहा है कार्बन का खतरा

हर साल दुनियाभर में बिजली गिरने से लगभग 32 करोड़ पेड़ नष्ट हो जाते हैं। यह बात ग्लोबल चेंज बायोलाजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार, जंगलों में आग लगने से हर साल लगभग 1.26 अरब टन कार्बन डाइआक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होती है। बरसात के मौसम में बिजली गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिजली गिरने से पेड़ों की हानि सबसे अधिक होती है। कई जंगलों में पेड़ों के नष्ट होने का एक प्रमुख कारण बिजली गिरना है। वनस्पतियों के जलने से प्रतिवर्ष भारी मात्रा में कार्बन डाइआक्साइड उत्सर्जित होती है। अब तक बिजली गिरने से हर साल कितने पेड़ नष्ट होते हैं, इसका स्पष्ट अनुमान नहीं था, लेकिन इस नए शोध ने उस संख्या का आकलन करने में मदद की है। इस अध्ययन में पहली बार वैश्विक स्तर पर बिजली गिरने से पेड़ों के नष्ट होने और उससे जुड़ी कार्बन हानि का अनुमान प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि जंगलों में बिजली गिरने के पर्यावरणीय प्रभावों को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। भले ही प्राकृतिक पर्यावरणीय हानि को मानव हस्तक्षेप के बिना रोक न जा सके, लेकिन यह एक गंभीर और वैश्विक स्तर पर चिंताजनक विषय है।

दत्तात्रय शिरोडकर, मुंबई

प्रतिक्रिया

मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी चिंताजनक

आज की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरी जीवनशैली ने हमें भौतिक रूप से तो सफल बनाया है, परंतु मानसिक स्वास्थ्य के मामले में हम कहीं खोते जा रहे हैं। बढ़ती चिंता, तनाव, अकेलापन, अवसाद और आत्महत्या की घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए दवाएं, डाक्टर और जांच की सुविधाएं विकसित कर ली हैं, पर जब मानसिक स्वास्थ्य का विषय उठता है, तो समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। इसे शर्म और कमजोरी से जोड़ा जाता है। इसी कारण लाखों लोग सामाजिक डर या इलाज न मिलने की वजह से अपनी परेशानियों को अकेले ही सहन करते हैं। युवा वर्ग परीक्षा, करियर और मीडिया के बोझ के चलते मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। कामकाजी लोग नौकरी के तनाव, रिश्तों में असंतुलन और अकेलेपन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। हमें स्कूल-कालेजों, कार्यालयों और घरों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए। लोगों को बताया जाए कि मानसिक बीमारियां भी अन्य बीमारियों की तरह सामान्य हैं, जिनका उपचार संभव है।

ऋतिक, छात्र, चितकारा यूनिवर्सिटी, पंजाब

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 138

दृष्टिकोण में बदलाव

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया और उस पर हस्ताक्षर किए। इसे हाल के वर्षों में भारत द्वारा किया गया सबसे व्यापक व्यापार करार माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर पिछले कुछ वर्षों से चर्चा चल रही थी। इस बारे में जनवरी 2022 में औपचारिक वार्ता शुरू हुई थी और ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उम्मीद जताई थी कि यह समझौता उसी साल दीपावली तक हो जाएगा। मगर तथ्य यह है कि समझौते पर अनौपचारिक चर्चा 2016 में ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए हुए मतदान से पहले से ही चल रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस दौरान जो कुछ भी बातचीत हुई थी, उसकी रूपरेखा बदल गई थी। 6 या 7 साल पहले स्थिति यह थी कि जब तक किसी भी समझौते में बीजा या प्रवासियों का बड़ा मुद्दा शामिल न हो, भारत शुल्क कटौती पर चर्चा से इनकार करना चतुराई समझता था।

ऐसी मांगों के कारण 10 डाउनिंग स्ट्रीट में डेविड कैमरन की उत्तराधिकारी टरीसा मे के साथ बातचीत में बाधा आई थी। मगर इस दरमियान ब्रिटेन का राजनीतिक माहौल प्रवासन के खिलाफ हो चुका है। समझौते में महज 1,800 अतिरिक्त पेशेवर वीजा का वादा किया गया है। इस संयम की बुद्धिमत्ता तब स्पष्ट हो गई जब बचत योजनाओं में दोहरे योगदान संबंधी एक अहानिकर प्रावधान भी ब्रिटेन में बड़ा विवाद का कारण बना गया जबकि इस समझौते में अन्य कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए निवेश पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है। हालांकि यह कहना उचित होगा कि यह एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के साथ सबसे व्यापक समझौता है। और यह व्यापार को लेकर भारत की मानसिकता में महत्त्वपूर्ण बदलाव को प्रतिबिंबित करता है।

सवाल यह है कि मानसिकता में इस बदलाव को अब अन्य व्यापारिक भागीदारों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (ईयू) पर कितना और किस तरह लागू किया जा सकता है। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है और भारत के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि इसे इस साल के अंत तक संपन्न हो जाना चाहिए। भारत ने ब्रिटेन से जो प्रतिबद्धताएं की हैं और रियायतें दी हैं, उनसे देश में बहुत कम या कोई राजनीतिक चिंता नहीं हुई है। इसलिए वार्ताकार यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में शुल्क में अधिक कटौती का जोखिम उठा सकते हैं। यूरोपीय संघ के साथ वार्ता में इनमें से कुछ की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि ईयू को अपने आकार और अफसरशाही ढांचे को देखते हुए अन्य की तुलना में अधिक व्यापक चर्चा और समझौते की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके फायदे भी उतने ही व्यापक होंगे। ब्रिटेन के उलट यूरोपीय संघ अभी भी प्रमुख विनिर्माण ताकत है और कई वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र में है, जिनमें भारतीय उत्पादकों को प्रवेश करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इस दृष्टिकोण से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आने वाले वर्ष में भारत की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाया जाने वाला सबसे बड़ा परिवर्तनकारी कदम हो सकता है।

इसके अलावा भारत को रक्षात्मक कार्रवाई भी करनी होगी ताकि अमेरिका के साथ भारत की बाजार पहुंच और व्यापार अधिशेष की रक्षा हो सके। अमेरिका में आयात पर ऊंचा शुल्क लगाने की राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की दूसरी समय-सीमा नजदीक आ रही है और जापान जैसे कई देशों ने पहले ही उसके साथ समझौतों की घोषणा कर दी है। हालांकि इनमें से कोई भी समझौता उन देशों के पक्ष में ज्यादा अनुकूल नहीं है। ब्रिटेन अमेरिका से आयात की तुलना में कम निर्यात करता है, फिर भी उसे 10 फीसदी बुनियादी शुल्क का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में जापान के उत्पाद पर 15 फीसदी कर चुकाना पड़ रहा है और उसे घटिया अमेरिकी चावल के खिलाफ सुरक्षा छोड़नी पड़ी है। इस विशेषाधिकार के बदले में उसने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया है। भारत को भी इसी तरह की रियायतें देनी पड़ सकती हैं। सवाल यह है कि भारत और अमेरिका किस स्तर का समझौता करेंगे।

इंदिरा का इंडिया और मोदी का भारत

नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर लगातार सबसे लंबी अवधि तक बने रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। यह जानने का प्रयास करते हैं कि चार अहम मामलों में वह इंदिरा गांधी के साथ तुलना में कैसे नजर आते हैं?

जून 2024 में जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तीसरा कार्यकाल हासिल किया, ठीक उसी दिन तय हो चुका था कि इस वर्ष वह लगातार कार्यकालों में दूसरी सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस दौरान वह इंदिरा गांधी से आगे निकल गए जो 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक प्रधानमंत्री रही थीं। उसी दिन यह भी तय हो गया था कि 2025 में लगभग इसी समय मोदी और इंदिरा के बीच तुलनाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। या ऐसा कहने वाले शुरुआती लोगों में मेरा नाम शुमार कर सकते हैं।

सबसे पहले, हमें उन व्यापक राजनीतिक हकीकतों पर नजर डालनी होगी जिनके तहत दोनों सत्ता में आए तथा उनकी सत्ता के समक्ष चुनौतियों पर भी गौर करने की जरूरत है। उसके पश्चात हम विभिन्न आयामों पर उनके प्रदर्शन का आकलन करेंगे: राजनीति, सामरिक और विदेश मामले, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रवाद।

इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने एकदम अलग-अलग हालात में सत्ता संभाली। दोनों की राजनीतिक पूंजी में भी अंतर था। गांधी ने 1966 में कोई चुनाव नहीं जीता था। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद उन्हें एक सहज विकल्प के रूप में चुना गया था। अपने शुरुआती दिनों में वह संसद में ज्यादा कुछ नहीं बोलती थीं और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने उन्हें 'गूंगी गुड़िया' कहकर खारिज कर दिया था। उन्हें विरासत में एक ध्वस्त अर्थव्यवस्था मिली थी। 1965 में देश की वृद्धि दर 2.6 फीसदी ऋणात्मक थी। युद्ध, सूखा, खाद्य संकट तथा राजनीतिक अस्थिरता की तिहरी मार के साथ-साथ महज 19 महीनों के अंदर दो पदासीन प्रधानमंत्रियों के निधन ने भारत को कमजोर कर दिया था।

2014 में मोदी के लिए तस्वीर इसके एकदम उलट थी। उन्हें बहुमत मिला था और देश में 30 साल बाद बहुमत की सरकार आई थी। वह अपनी पार्टी के चुने हुए प्रत्याशी थे। अर्थव्यवस्था पिछले 15 वर्षों में औसतन 6.5 फीसदी की मजबूत वृद्धि दर से चल रही थी। उन्हें सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से, नियोजित ढंग से और चुनाव प्रक्रिया के जरिये मिली थी। सत्ता के आरंभ में उनके लिए कठिनाई इंदिरा गांधी की तुलना में बहुत कम थी क्योंकि उनके पास बहुत अधिक राजनीतिक पूंजी थी।

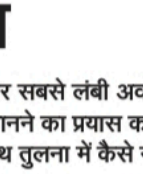

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

इस बात को रेखांकित करना भी आवश्यक है कि इंदिरा गांधी को सत्ता का 11वां साल चुनावी जीत से नहीं हासिल हुआ था बल्कि उन्हें वह अतिरिक्त वर्ष संविधान धज्जियां उड़ा कर मिला था। यह इसलिए संभव हुआ कि कांग्रेस को संसद में भारी बहुमत हासिल था। उसके पास 518 लोक सभा सीटों में से 352 सीटें थीं और विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। इसके विपरीत मोदी का तीसरा कार्यकाल आम चुनाव जीत कर हासिल किया गया। हालांकि इस बार वह पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए। मोदी को 11 साल में कोई चुनौती नहीं मिली। न तो पार्टी के भीतर और न ही पार्टी के बाहर। वैश्विक हालात भी मोटे तौर पर अनुकूल बने रहे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत ने जरूरत हालात को मुश्किल बनाया।

अब बात करते हैं चारों आयामों की। घरेलू राजनीति के मोर्चे पर पहला सवाल है: भारत का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री कौन रहा? नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? बाकियों का उल्लेख करना ठीक नहीं।

गांधी ने अपनी राजनीति एक विचारधारा (समाजवादी रुझान वाली) के बूते चलाई। शुरू में मजबूरी के कारण, और उसके बाद अपनी पसंद से। मोदी का जन्म भगवा राजनीति में हुआ और वे उस रंग में पूरे रंगे रहे। इंदिरा गांधी की ताकत समय के साथ फर्श और अर्श को छूती रही। मोदी की ताकत 2024 में 240 सीटें जीतने के बाद के कुछ महीनों को छोड़ निरंतर स्थिर रही।

240 सीटों के साथ भी उन्हें अपनी पार्टी के भीतर से कोई चुनौती मिलती नहीं दिख रही। उन्होंने सभी को हाशिये पर कर दिया है। राज्यों के क्षत्रपों की जगह अनजान नेताओं को आगे लाया गया है। यह इंदिरा गांधी के व्यवहार से अलग नहीं है यानी निर्ममता के मामले में दोनों को एक साथ रखा जा सकता है। वहीं विपक्ष के साथ व्यवहार और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करें तो आपातकाल जैसे कदम का मुकाबला करना किसी के लिए भी मुश्किल है। जहां तक संस्थानों के आदर की बात है तो तगड़ी प्रतिस्पर्धा है। सहजता के लिए आइए केवल एक संस्थान की बात करते हैं- राष्ट्रपति। वी.वी. गिरि के साथ इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के पद को एक पुतले की तरह बना दिया। कमजोर और दिखावटी जो बस खाली जगहों पर दस्तखत करता था। मोदी युग में भी राष्ट्रपति ऐसे ही रहे।

मोदी '56 इंच का सीना' जैसे बयान के साथ सत्ता में आए, गांधी को भी उनके समय में 'कैबिनेट में इकलौता मर्द' कहकर पुकारा गया। 1977 से 1984 के बीच जब वह सत्ता से बाहर हुईं और फिर वापस आईं, उस समय उन्होंने एक अलग कौशल दिखाया लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वह 11 साल की तुलना से बाहर है।

एक अहम सवाल है कि किसने भारत के ताने-बाने को बेहतर बनाए रखा। गांधी ने मिजोरम और नागालैंड में विद्रोहियों से सख्ती से मोर्चा लिया। इस मोर्च पर उनकी समस्या 1980 के बाद शुरू हुई। मोदी ने कश्मीर घाटी में जबरदस्त सुधार किया और पूर्वोत्तर में हालात सामान्य करने की प्रक्रिया में लगे रहे। परंतु मणिपुर में उन्हें नाकामी हाथ लगी। देश के पूर्वी और मध्य इलाके में माओवाद का विनाश एक बड़ा सकारात्मक कदम रहा।

इंदिरा गांधी के 11 साल के दौरान शीतयुद्ध चरम पर था। उन्होंने सोवियत संघ के साथ संधि की जिसमें बहुत चतुराई से साझा सुरक्षा का प्रावधान रखा गया। उन्होंने निक्सन-किसिंजर के चीन के प्रति झुकाव का सामना किया और भारत के लिए उपलब्ध छोटे-छोटे अवसरों का लाभ लिया।

मोदी ने सबके साथ दोस्ती के साथ शुरुआत की लेकिन पाकिस्तान और चीन की हकीकतों ने जल्दी ही हालात स्पष्ट कर दिए। गांधी ने 1974 में पोकरण-1 के बाद भारत को परमाणु शक्ति बनाया लेकिन 2019 में बालाकोट और 2025 में पहलगाम के बाद पाकिस्तान की परमाणु धमकी का प्रत्युत्तर दिया गया जो मोदी की कामयाबी है।

पड़ोस में माहौल बिगड़ रहे थे और भारत, अमेरिका और पश्चिम के साथ रिश्ते सुधार रहा था कि तभी यूक्रेन में जटिलताएं शुरू हो गईं। ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में हलचल मचा दी। अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान 1971 की तरह खेल रहा है। उस दौर की इंदिरा गांधी की तरह मोदी को विकल्प तलाशने होंगे। सोवियत संघ बहुत पहले जा चुका है। उनके पास 1971 की इंदिरा गांधी की तुलना में कम विकल्प हैं। लेकिन भारत मजबूत हुआ है।

अर्थव्यवस्था में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। इंदिरा गांधी के उलट मोदी यह कहते हुए सत्ता में आए कि कारोबार करना सरकार का काम नहीं है। परंतु वह कई जगह उनका अनुकरण करते नजर आए। उदार और प्रभावी तरीके से लोगों में कुछ वितरित करते रहने की राजनीति इसका उदाहरण है। निजीकरण के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर प्रतिबद्धता नजर आई। इस वर्ष के बजट में भी 5 लाख करोड़ रुपये की राशि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में नए निवेश के लिए रखी गई है, जबकि हमारा रक्षा बजट ही केवल 6.81 लाख करोड़ रुपये का है। मोदी ने डिजिटल भुगतान, जीएसटी और ऋणशोधन संहिता जैसे सुधार अवश्य किए हैं। कई अन्य सुधार प्रक्रिया में हैं।

अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में मोदी ने भूमि अधिग्रहण, कृषि और श्रम सुधार, अफसरशाही में लैटरल एंट्री जैसे सुधारों के प्रयास किए लेकिन अब उन्हें त्याग दिया गया है। ट्रंप के सत्ता में आने तक मोदी 6-6.5 फीसदी की वृद्धि दर से संतुष्ट दिख रहे थे जिसे हम हिंदुत्व वृद्धि दर कह सकते हैं। तर्क यह है कि हिंदू पहचान और ध्रुवीकरण से संचालित राजनीति 6-6.5 फीसदी की वृद्धि दर के साथ चुनाव जिताने में कामयाब रहेगी। परंतु ट्रंप की हरकतों और उसके चलते हो रहे व्यापार समझौतों ने हालात बदल दिए।

राष्ट्रवाद की बात करें तो इंदिरा गांधी के लिए 1962 और 1971 की जंग जैसी पृष्ठभूमि थी। भारत पहले ही जय जवान, जय किसान का देश था। बांग्लादेश की आजादी, हरित क्रांति और गुटनिरपेक्षता ने उनके राष्ट्रवाद को हवा दी। मोदी का राष्ट्रवाद अधिक शक्तिपूर्ण और सैन्य छवि वाला है।

मोदी के अधीन एक नया हिंदू आधारित राष्ट्रवाद उभरा है। इसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर हिंदुओं को एकजुट किया है लेकिन विभाजन भी बढ़ाया है। देश के विरोधी इसका लाभ लेना चाहेंगे। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान केवल मुस्लिमों ही नहीं सिखों के साथ भी ऐसी कोशिश करता है। खासतौर पर वह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसा करता नजर आया।

विवादों के बावजूद आहार में जगह बना रहा वीगन मिल्क

सामान्य दूध की तरह दिखने वाला वनस्पति आधारित अनूठा पेय, जिसे आमतौर पर वीगन मिल्क भी कहा जाता है, आजकल भारत सहित पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन डेरी किसान इसे गाय के दूध की तरह पोषक मानने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि गौवंश के दूध में ऐसे बेजोड़ गुण होते हैं, जो किसी अन्य पदार्थ में हो ही नहीं सकते। सोयाबीन, बादाम, चावल, काजू, जई, नारियल, अखरोट, मूंगफली तथा सन के बीज आदि से तैयार यह कृत्रिम दूध उन लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो सामान्य दूध को पचा नहीं पाते या उन्हें इससे एलर्जी है अथवा हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और कम वसा या कैलोरी वाले उत्पाद चाहने वाले लोग भी इसे अधिक पसंद करते हैं। एक बात और, जहां गौवंश दूध की आपूर्ति कम है, उन क्षेत्रों में कृत्रिम दूध खूब पिया जा रहा है।

भारत में भी वीगन मिल्क अपना खास बाजार बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन डेरी दूध का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के कारण यहां इसकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती है। देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रति दिन है, जो वैश्विक औसत 322 ग्राम से कहीं अधिक है। भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा के मुताबिक आदर्श रूप में दैनिक दूध की खपत 280 ग्राम होनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए अधिकांश वीगन मिल्क निर्माता इसे अधिक पोषक बनाने के लिए इसमें प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड और खनिजों का मिश्रण कर रहे हैं। यहां तक कि कृत्रिम रंग, सुगंध और स्वाद बढ़ाने वाले तत्व भी इसमें मिलाए जाते हैं कि ताकि लोग उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों और गैर-कार्बोनेटेड शीतल पेय में विविधता की तलाश करने वाले उपभोक्ताओं के बीच भी इनकी मांग बढ़े।

बाजार में इस समय सबसे ज्यादा सोया, बादाम, काजू, ओट और नारियल के वीगन मिल्क उपलब्ध हैं। इनमें से प्रत्येक में अलग-अलग पोषण गुण होते हैं। उदाहरण के लिए सोया मिल्क में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। कैलोरी और प्रोटीन सामग्री इसमें लगभग 7 से 9 फीसदी होती है। इन तत्त्वों के कारण सोया दूध को गाय के दूध के समान ही माना जाता है।

खेती बाड़ी
सुरिंदर सूद

बादाम के दूध में संतृप्त वसा की तुलना में असंतृप्त वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो वजन के प्रति बेहद सचेत रहते हैं। नारियल के सफेद गूदे और पानी से बने नारियल दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं। दूसरी ओर, ओट मिल्क में आहार फाइबर होता है, जो पाचन और रक्त कोलेस्ट्रॉल और शर्करा को संतुलित बनाए रखने के लिए अच्छा होता है।

लेकिन तमाम गुणों के बावजूद डेरी वैज्ञानिक वनस्पति आधारित इस पेय को दूध मानने को तैयार नहीं हैं। उनका तर्क है कि जानवरों और मनुष्यों की स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव को ही दूध कहा जा सकता है। खाद्य मानकों के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग द्वारा तैयार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोड भी उस सामान्य स्तन स्राव को ही दूध के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें कोई मिलावट न हो या उससे कुछ भी निकाला नहीं गया हो। पशुपालन विशेषज्ञों का कहना है कि वनस्पतियों से तैयार पेय को वीगन मिल्क कहना गलत है।

अप्रैल 2024 में नैशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज द्वारा 'दूध बनाम वनस्पति आधारित डेरी समतुल्य: मिथक और तथ्य' शीर्षक से प्रकाशित एक नीति पत्र में कहा गया है कि वनस्पतियों पर आधारित पेय पदार्थों को दूध, दूध का विकल्प या दूध के समतुल्य नहीं कहा जाना चाहिए। विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण करने के बाद भी ये शायद ही कभी सामान्य दूध का मुकाबला कर सकते हैं। मवेशियों, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़ी आदि प्रजातियों से प्राप्त दूध 500 से अधिक जैविक रूप से सक्रिय स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों का जटिल मिश्रण होता है, जो विभिन्न चिकित्सीय गुणों के अलावा, मानव पोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूध मानव विकास और शरीर प्रणालियों के रखरखाव के लिए लगभग संपूर्ण भोजन है। मानव जाति युगों से दूध का सेवन करती आ रही है। इस नीति पत्र में बताया गया है, 'वनस्पतियों पर आधारित दूध की मांग आवश्यकता की वजह से नहीं, बल्कि अधिक किफायती और फैंसी खाद्य स्रोत के रूप में उभरने से बढ़ रही है।'

फिर भी, मांग-आपूर्ति गतिशीलता के आधार पर वीगन मिल्क का बाजार घरेलू और वैश्विक स्तर पर लगातार फैलता जा रहा है। दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अमेरिका, यूरोप और महासागरीय क्षेत्रों के विकसित देशों में इसने बहुत तेजी से अपनी जगह बनाई है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार सूचना फर्म ग्लोबल डेटा का अनुमान है कि 2023 और 2027 के बीच भारत में दूध के विकल्पों का बाजार 6 से 8 फीसदी प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। एक अन्य संस्था इंटरनैशनल मार्केट एनालिसिस रिसर्च ऐंड कंसल्टिंग ग्रुप का मानना है कि देश में वीगन मिल्क का वर्तमान बाजार आकार लगभग 85.55 करोड़ डॉलर का है। वर्ष 2033 तक इसके 10 फीसदी से अधिक की वार्षिक वृद्धि के साथ 216.63 करोड़ डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर, इन दुग्ध पदार्थों का वैश्विक बाजार 2018 में 11.16 अरब डॉलर से बढ़कर 2023 में 19.67 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 12 फीसदी की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। सोया, बादाम, ओट्स, नारियल और चावल से बने दूध सबसे अधिक पसंद किए जा रहे हैं।

इस प्रकार अपने गुणों-अवगुणों और दूध कहा जाए अथवा कोई दूसरा नाम दिया जाए, जैसे विवादास्पद मुद्दों के बावजूद वीगन मिल्क वैश्विक एवं घरेलू खाद्य बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं तथा समय के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं।

आपका पक्ष

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर जागरूक हों लोग

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि लोगों को पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी उस विनाश से जो हमने स्वयं अपने लालच और विकास की अंधी दौड़ में जन्म दिया है। आज जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि प्रकृति कराह रही है। घने जंगलों की जगह कंक्रीट के जंगल उग आए हैं, नदियां सूख रही हैं, समुद्र गर्म हो रहे हैं, और वायुमंडल जहरीला होता जा रहा है। जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और कई विलुप्ति के कगार पर हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ती गर्मी और बिगड़ता जलवायु संतुलन ग्लेशियरों को पिघलाकर समुद्र का स्तर बढ़ा रहे हैं। दुखद पहलू यह है कि जहां एक ओर धरती सांस लेने को तरस रही है, वहीं दूसरी ओर मानव परमाणु परीक्षणों, युद्धों और हथियारों की होड़ में उलझा हुआ है। शक्ति प्रदर्शन की यह होड़ उस आग को और भड़का रही है, जो पहले ही पर्यावरण को जला रही है। बड़ी महाशक्तियां अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को विनाश की ओर धकेल रही हैं , जंगल कट रहे हैं, समुद्र में प्लास्टिक का पहाड़ बन चुका है और वनों में आग लगाना मानो विकास का संकेत बन गया है।

जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित बारिश से कई शहरों में जलजमाव की स्थिति बन रही है

प्रकृति हमारे अस्तित्व की जड़ है। यदि यह समाप्त होती है, तो जीवन का अस्तित्व भी समाप्त होगा। ऐसे में हमें तत्काल पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, वृक्षारोपण करना होगा, जल और ऊर्जा का संरक्षण करना होगा, प्रदूषण रोकना होगा।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

प्रकृति के संरक्षण में ही हमारी खुशहाली

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो प्राणि जाति को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहा है। इसकी रक्षा के लिए लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। सरकार भी पौधरोपण को बढ़ावा दे तथा खाली जगहों पर पेड़ लगाए जाएं। प्रकृति से खिलवाड़ का बुरा नतीजा हम मौसम चक्र के बिगड़ने और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख रहे हैं। प्रकृति से खिलवाड़ के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और धरती गर्म होती जा रही है। बढ़ती गर्मी इंसान के अस्तित्व के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्राणि जाति के लिए हानिकारक है। इसी कारण कुछ प्रजातियां विलुप्त भी हो गई हैं। बारिश के मौसम में अगर पौधे लगाएं जाएं तो वह बहुत अच्छे तैयार होते हैं। अतः जिन लोगों के घरों में जगह है वहां एक पौधा जरूर लगाएं। भारत को विश्व में प्राकृतिक सौंदर्य में शीर्ष स्थान पर माना जाता है। प्रकृति की सुंदरता जंगली-जीव जंतुओं से भी होती है। लेकिन आज बहुत से जंगली-जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने के कगार तक पहुंच चुकी है। हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति गंभीर होना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

गाजा में रविवार को इजरायली हमले के बाद उठता धुआं। इजरायल की सेना ने रविवार को गाजा के तीन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रतिदिन 10 घंटे के लिए लड़ाई रोकने की शुरुआत की। यह कदम इस क्षेत्र में बढ़ती भुखमरी की चिंताओं मद्देनजर उठाया गया।

मोदी का मालदीव दौरा

विश्वास बहाली का प्रयास

राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। यही बात अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी लागू होती है, जहां राष्ट्र बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप भू-राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर अपनी स्थिति बदलते हैं। भारत-मालदीव संबंध इसका एक उदाहरण हैं। कभी सौहार्दपूर्ण, फिर तनावपूर्ण रहे ये संबंध अब पुनरुद्धार के लिए तैयार प्रतीत होते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा महज एक कूटनीतिक औपचारिकता से कहीं अधिक का संकेत देती है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति की एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध वापसी का प्रतीक है, जो हाल के वर्षों में स्पष्ट रूप से खराब हो गए थे। प्रतीकात्मक होते हुए भी यह क्षण तुच्छ से कोसों दूर है, मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा भेजवाही किए जाने वाले पहले विदेशी नेता होंगे।

इसके बाद के महीनों में, मुइज्जू का प्रशासन चीन की ओर झुकने लगा, जिससे नई दिल्ली में हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के संभावित क्षरण को लेकर खतरे की घंटी बज गई। आज, परिदृश्य काफी बदल गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक कूटनीतिक नरमी से कहीं अधिक है - यह मालदीव में भारत की स्थायी रणनीतिक हिस्सेदारी की पुष्टि है। मात्र नौ महीने पहले, मुइज्जू ने भारत का दौरा किया था, जहां दोनों पक्षों ने एक व्यापक आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाया था - जो अब भविष्य के सहयोग के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है।

मालदीव भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और व्यापक महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंद महासागर में एक समुद्री चौराहे पर स्थित, यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग और रणनीतिक गहराई में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद, भारत एक दृढ़ साझेदार बना हुआ है। मालदीव के रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों तक, द्विपक्षीय रक्षा संरचना मजबूत बनी हुई है। भारत ने आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों के दौरान भी कदम उठाया है और क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की है। उल्लेखनीय रूप से, भारतीय सहायता ने मालदीव में संभावित ऋण चूक को रोकने में मदद की।

वर्तमान घनिष्ठ संबंध समयोचित हैं क्योंकि यह वह समय है जब हिंद महासागर में चीनी प्रभाव बढ़ रहा है और वह भारत को घेरने की अपनी नीति पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। चीन ने बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं, व्यापार समझौतों और सैन्य सहयोग के माध्यम से मालदीव में अपने प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे इस द्वीपीय राष्ट्र की चीन पर अत्यधिक निर्भरता और क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट मालदीव का स्थान इसे चीन के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है, विशेष रूप से ऊर्जा आपूर्ति और हिंद महासागर तक पहुंच के संबंध में। इस प्रकार, हिंद महासागर पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारत के लिए मालदीव का अपने पक्ष में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

आर्थिक रूप से, भारत मालदीव के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 500 मिलियन डॉलर है। वर्तमान में एक मुक्त व्यापार समझौते और एक व्यापक निवेश संधि, विशेष रूप से मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, के लिए बातचीत चल रही है। इस बीच, भारत द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, विशेष रूप से प्रमुख ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना-चार प्रमुख द्वीपों को जोड़कर देश के परिवहन परिदृश्य को बदलने का वादा करती हैं।

मोदी की विदेश नीति को परिभाषित करने वाली व्यक्तिगत कूटनीति मालदीव में भी अभिव्यक्त होती है—रणनीतिक आश्वासन और राजनीतिक व्यावहारिकता के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए। हालांकि यह नया जुड़ाव 'इंडिया आउट' अभियान की यादों को रातोंरात मिटा नहीं सकता, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय साझेदारियों को पोषित किया जाना चाहिए और उन्हें आपसी सम्मान, साझा हितों और दीर्घकालिक रणनीतिक दूरदर्शिता पर आधारित होना चाहिए ताकि क्षेत्र को बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त रखा जा सके।

लोकतंत्र की पूर्वापेक्षाएं

जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक पहलू, मतदाताओं को लुभाने के लिए क्षेत्रीय और भाषाई अपीलें खुलेआम की जा रही हैं। इस तरह की प्रथाओं का उदय तभी हुआ जब आजादी के लगभग दो दशक बाद, गांधीवादी मूल्यों का क्षरण चारों ओर दिखाई देने लगा।

जेएस राजपूत
लेखक, शिक्षा व सामाजिक समरसता हेतु कार्यरत हैं।

बीसवीं सदी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व प्रगति, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के साथ-साथ, मुक्ति आंदोलनों, सामाजिक सुधारों, लोकतंत्रों की जड़ें जमने और, सबसे महत्वपूर्ण बात, लगभग हर नए स्वतंत्र देश में उच्च आकांक्षाओं, प्रगति और विकास की अज्ञाओं के उदय की भी साक्षी रही। शांति, सद्भाव, सामाजिक समन्वय और धार्मिक सौहार्द से भरे विश्व के निर्माण की बड़ी उम्मीदें थीं। गांधी, मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और राजनीतिक क्षेत्र के कई अन्य लोगों ने, आईंस्टीन, नील्स बोहर जैसे वैज्ञानिकों और विभिन्न मोर्चों पर कई अग्रणी हस्तियों के साथ मिलकर, एक सुंदर, बेहतर और सामंजस्यपूर्ण विश्व की तस्वीर पेश की।

संयुक्त राष्ट्र संघ (अब संयुक्त राष्ट्र) का गठन किया गया और इसे एक वैश्विक निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया जो घृणा, हिंसा और युद्धों को रोकने के लिए नैतिक और नैतिक रूप से पर्याप्त रूप से सुसज्जित होगी। सामाजिक, नैतिक और आचारिक मुक्ति होगी, और रंगभेद, असमृषता, नस्लीय और धार्मिक भेदभाव जैसी अमानवीय प्रथाएं पृथ्वी से मिट जाएंगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी यही आम धारणा थी।

दुर्भाग्य से, स्वतंत्र भारत की शुरुआत रक्तपात, घृणा, हिंसा और मानव जीवन की भीषण क्षति से हुई। विभाजन के दौरान भारत को भारी क्षति हुई। सबसे बुरी बात तो दो प्रमुख समुदायों के बीच उत्पन्न अविश्वास था, जिसके समाप्त होने से निश्चित रूप से भारत की प्रगति की गति प्रभावित हुई। गरीबी, अशिक्षा, संसाधनों की कमी और कई अन्य चुनौतियां थीं। लेकिन उम्मीदें किसी भी स्तर पर कम नहीं हुईं। ये उम्मीदें न केवल भारत में, बल्कि उन सभी शोषित और अपमानित राष्ट्रों के लोगों में भी प्रबल रहीं, जिन्हें सदियों से दुनिया भर में, विशेष रूप से यूरोपीय लोगों द्वारा, अमानवीय औपनिवेशिक शासनों द्वारा दबाया गया था।

भारत में, आम आदमी एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना करता था जो भ्रष्टाचार और सरकारी कार्यालयों में अपमान से मुक्त होगी, और जहाँ पुलिस अब एक भयावह संस्था नहीं होगी। हमारे अपने ही लोग, जो सामान्य सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं, हमारा शोषण कैसे कर सकते हैं, जबकि वे हमारे ही लोगों के नेतृत्व वाली सरकार में काम कर रहे होंगे? लोगों को उनके नेतृत्व की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्ठा पर पूरा भरोसा था। भारत में, अफसोस! बहुत ऊंची थीं: एक बार जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, जाति और पंथ के आधार पर कोई अपमान या भेदभाव नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई छुआछूत नहीं होगी, मंदिरों में प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा या कुछ सड़कों पर आवाजाही से मना नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी के अधिक गहराई से भारत के भविष्य की कल्पना कौन कर सकता था?

1922 में लिखे एक पत्र में, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामने आने वाली यथार्थवादी स्थिति की कल्पना की थी: हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद, हमारे लोगों को सुख प्राप्त नहीं होने वाला। जैसे ही हम स्वतंत्र होंगे, चुनाव प्रणाली के सभी दोष, अन्याय, धार्मिक वर्ग का अत्याचार, और प्रशासन चलाने का भार भी हम पर आना तय है। लोगों को लगने लगेगा कि उन दिनों स्वतंत्रता के बाद के दिनों की तुलना में अधिक न्याय था, बेहतर प्रशासन था, शांति थी, और प्रशासकों में काफी हद तक ईमानदारी थी। हालांकि, स्वतंत्रता का एकमात्र लाभ यह होगा कि हम गुलामी और उससे उत्पन्न अपमान के कलंक से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर शिक्षा पूरे देश में फैल जाए, तो उम्मीद है। इससे लोगों में बचपन से ही शुद्ध आचरण, ईश्वर-भक्ति और प्रेम जैसे गुण विकसित होंगे। स्वराज हमें तभी सुख देगा जब हम इस कार्य में सफल होंगे। अन्यथा, भारत शासकों के घोर अन्याय और अत्याचार का अड्डा बन जाएगा। मैं उपरोक्त चार में से पहले को कभी ठीक से समझ नहीं पाया: चुनावों के दोष! 1922 में वे चुनावों के दोषों की बात कैसे कर सकते थे?

इस मामले में उनकी आशंका सबसे सटीक साबित हुई है, और यह अन्य तीन पर भी उतना ही भयावह प्रभाव डाल रही है। राष्ट्रीय, राज्य और पंचायत स्तर पर हुए अनेक चुनावों से गुजरने के बाद, यह सभी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और उसके परिणामों को विकेन्द्रपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए चुनावों का पूरी तरह से नैतिक और नैतिक वातावरण में, ईमानदारी और निष्ठा के साथ पारदर्शी तरीके से संचालन आवश्यक है। राष्ट्र ने बार-बार देखा है कि कैसे राजनीतिक दल खुलेआम उन सभी बातों के आधार पर लोगों के अपने समूह बनाने की कोशिशें पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी उनसे भारतीय संविधान में अपेक्षा नहीं की गई थी, और वास्तव में, स्पष्ट रूप से निषिद्ध भी थी।

जातिगत समीकरण, सांप्रदायिक पहलू, मतदाताओं को लुभाने के लिए क्षेत्रीय और भाषाई अपीलें खुलेआम की जा रही हैं। इस तरह की प्रथाओं का उदय तभी हुआ जब आजादी के लगभग दो दशक बाद, गांधीवादी मूल्यों का क्षरण चारों ओर दिखाई देने लगा। सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉ. विधान चंद्र रॉय और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे दिग्गज चले गए थे। युवा नेताओं की पीढ़ियों ने देखा था कि चुनाव जीतना सत्ता, अधिकार, सुविधाओं और विशेषाधिकारों की ओर पहला कदम है, और अंततः, संपत्ति और अपने प्रियजनों के उत्थान की ओर। उस ओर बढ़ना मुश्किल नहीं था। धीरे-धीरे, उन्होंने देखा कि सत्ता का मतलब व्यक्तिगत आर्थिक उन्नति है, और कानून, अपवादों को छोड़कर, एक बार सत्ता में आ जाने के बाद आपको छू नहीं सकता।

इस परिवर्तन को समझने की मेरी उत्सुकता और यह कि गांधीजी इसकी भविष्यवाणी कैसे कर सकते थे, ने मुझे कई भाग्यशाली व्यक्तियों से बातचीत करने का सौभाग्य दिलाया, जिन्होंने अपनी युवावस्था में उनके साथ काम किया था। उन्होंने मुझे दो बातें बताईं। पहली, उन्होंने ब्रिटिश चुनाव प्रणाली का बहुत ध्यानपूर्वक और गहन अध्ययन किया था।

दूसरी, वे भारतीयों की मानसिकता को अच्छी तरह समझते थे। अंग्रेजों ने अपनी अलिखित नीति के तहत न्यायपालिका, पुलिस और प्रशासन सहित पिछले प्रशासनिक पदों पर भ्रष्टाचार के सर्वव्यापीकरण की अनुमति दी थी। इन दोनों को मिलाकर, उन्हें भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर मिलती थी। अब यह सर्वविदित है कि वे लगभग हर चुनाव में जो हम आज देख रहे हैं, उसकी कल्पना कैसे कर सकते थे। हर भारतीय जानता है कि चुनावों के दोषर क्या होते हैं।

मुझे 1952 के चुनावों के दौरान हरदोई में ट्रेन से पंडित नेहरू की प्रशंसक जनता की ओर हाथ हिलाते हुए सुनने का सौभाग्य मिला था, जब मैं नौ साल का था। 1962 के तीसरे आम चुनाव तक ही मुझे इसका वास्तविक अर्थ समझ में आया, और यह कैसे संचालित किया जाना चाहिए। इस समय तक, मेरे कुछ विश्वविद्यालय के दोस्तों ने राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं को समझने में काफी समय और ऊर्जा लगा दी थी, और कुछ ने तो कुछ राजनीतिक दलों की सदस्यता भी प्राप्त कर ली थी। व्यक्तिगत नेताओं के प्रति अपार सम्मान था—उन्होंने अपना सब कुछ दिया था, लेकिन जनता से अपने लिए कुछ नहीं छीना था।

चीनी आक्रमण और भारतीय सशस्त्र प्रतिरोध के पराभव के बाद नेहरू सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए आचार्य जे.बी. कृपलानी ने लोकसभा में इसे बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया था—और उसके भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गुटनिरपेक्षता नीति और भारत की चीन नीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था।

कृपलानी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष यू.एन. ढेबर के एक बयान का हवाला दिया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारी योजनाओं ने अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना दिया है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने यह तो स्वीकार किया कि अमीर और अमीर हो गए हैं, लेकिन यह मानने से इनकार कर दिया कि गरीब और गरीब हो गए हैं। आज हम इन मामलों में कहां खड़े हैं? अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है, तो उनके जीवन में निश्चित रूप से आत्मसम्मान की कमी है। इस बहस में भाग लेने वाले एक अन्य पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिन्हें पंडित नेहरू भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनके प्रेम और उनके पालन के कारण कभी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार की भयावह उपस्थिति और उसके उदय पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने खुलकर कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग थे जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी और वे अब करोड़पति बन गए हैं।

अब वह समय आ गया है कि देश की युवा पीढ़ी जो अपनी शिक्षा पूरी कर रही है और शीघ्र ही राष्ट्र की बागडोर संभालने के लिए तैयार है, स्वयं, समाज, समुदाय और राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व को परिभाषित और परिभाषित करे।

अनुकरणीय बनता यूपी मॉडल

किसी भी राज्य की प्रगति के लिए पहला काम कानून व्यवस्था ठीक रखना है। साथ ही सड़कों का जाल, बिजली आदि प्रमुख घटक है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद योगी बाबा दो प्रमुख मामलों में चर्चा में आ गये। पहला कानून व्यवस्था और दूसरा गौ-संरक्षण।

अशोक सिंह
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बहुत समय से हम लोग देश के विकास में गुजरात माडल की बड़ी चर्चा सुनते आये हैं। दुग्ध उत्पादन व विपणन में अमूल ने गुजरात को बहुत ख्याति दिलाई। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन समेत दर्जनों योजनाओं में देश में नम्बर वन बन गया है। कानून व्यवस्था के मामले में तो योगी माडल की देश भर में चर्चा है। कई राज्य तो अपने यहां योगी माडल को फालो भी कर रहे है।

किसी भी राज्य की प्रगति के लिए पहला काम कानून व्यवस्था ठीक रखना है। साथ ही सड़कों का जाल, बिजली आदि प्रमुख घटक है। यूपी में योगी सरकार आने के बाद योगी बाबा दो प्रमुख मामलों में चर्चा में आ गये। पहला कानून व्यवस्था और दूसरा गौ-संरक्षण। योगी बाबा ने इन दोनों मामलों में 'जीरो टालरेंस' की नीति अपनाई। आज इसी का प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश जहां दुग्ध उत्पादन में देश में नम्बर वन है, वहीं गौवंश के मामले में देश में नम्बर वन है। आज उत्तर प्रदेश में 390 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है जो देश में सर्वाधिक है। एक करोड़ 90 लाख गौवंश के साथ यू पी नम्बर वन है। राष्ट्रीय जीडीपी में पशुपालन का योगदान 4.11 फीसदी है, जबकि यूपी में यह प्रतिशत 7.10 है। इस मामले में करोड़ों लोगों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है।

देश में ढेरियां भी खुलीं गोबर आदि से खाद का भारी उत्पादन हुआ। गौआश्रय स्थलों के खुलने से सड़कों, खेतों में घूमते गोवंश को आश्रय मिला। यही नहीं पशु बीमा से बीमा उद्योग को भी लाभ मिला। मतलब योगी बाबा ने परिणाम देकर बता दिया कि सही तरीका से काम किया जाय तो परिणाम निश्चित है। शुरूवात में गो संरक्षण आदि की बड़ी आलोचना हुई लेकिन परिणाम के बाद आलोचकों के मुंह बंद हो गये हैं। वैसे भी काई भी कार्य हो परिणाम आने में समय लगता है। आलोचनाओं की परवाह किये बिना लगन से काम काज का ही परिणाम है कि आज

यूपी दुग्ध उत्पादन में नं० वन है। योगी बाबा की दूसरी वरीयता थी कानून व्यवस्था। माफिया इस कदर सक्रिय थे कि सरकार तक माफिया के सामने नतमस्तक थी। माफिया पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीयों का जिस तरह अपमान करते थे, उससे लगता था कि सरकार माफिया की दासी है। कुछ माफिया तो अपने अपने इलाके में समांतर सरकार चलाते थे। योगी बाबा ने संकल्प लिया कि अपराधियों को मिटाना है। कानून में संशोधन किया फिर चलना शुरू हुआ सरकार का डंटर । इनकाउंटर होने लगे। बाबा के बुलडोजर माफिया की संपत्तियों पर टूट पड़े।

अवैध कमाई से बने महल धराशायी होने लगे। अवैध जमीनें खाली होने लगी और अपराधी जमानत रद कराकर जेल में रहना पसंद करने लगे। शुरू में लगा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा लेकिन योगी बाबा के दृढ़ निश्चय ने अपराधियों की पेंट ढीली कर दी। बड़े-बड़े सूरमा पुलिस की गोलियों के शिकार हो गये। अपराधियों में मौत का भय फैल गया। अब अपराध करने से पहले सोचने लगे धीरे-धीरे स्तिथि काफी नियंत्रित हो गयी। 25 करोड़ आबादी में एक भी अपराध ना हो, ऐसा संभव नहीं। पीड़ितों की सुनवाई होने लगी। कुल मिलाकर अपराधियों का आतंक काफी हद तक समाप्त हो गया।

सिर्फ ये दो मामले ही नहीं, योगी सरकार ने प्रदेश के विकास की दिशा में भी काफी काम किया। गन्ना, चीनी आम आलू, खाद्यान्न, सीरा के उत्पादन में यूपी नम्बर वन बन गया । जाहिर है जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों मजदूरों कुशल व अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश अब दुग्ध उत्पादन, एक्सप्रेस-वे नेशनल हाईवे यानि कि सड़कों के निर्माण में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के क्रियान्वयन, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में, महिला अपराधों में सजा दिलाने में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम है । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन, किसानों को अनुदान, कौशल विकास नीति के क्रियान्वयन, शौचालय निर्माण आदि में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में नम्बर वन है।

ऐसी स्तिथि जब हम दर्जनों योजनाओं में नम्बर वन है तो यूपी माडल सफल माना जायेगा। ऐसे में गुजरात माडल के दिन गये, अब यूपी माडल की चर्चा हो रही है। उद्योग लगने व एयरपोर्ट बनने में यूपी काफी आगे है। जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। माइक्रोचिप की फैक्ट्री लग रही है। मोबाईल फोन की फैक्ट्रीयां भी लग रही है। डिफेन्स कारीडोर बहुत बड़ी उपलब्धी है। ब्रह्मोस मिसाइल की फैक्ट्री लखनऊ में लग गयी है। उत्तर प्रदेश चौतरफा विकास की ओर अग्रसर है। लम्बे समय से लगी जंक टूटने लगी है। इतना सब होने के बाद अब गुजरात माडल की चर्चा ठंडी पड़ने लगी है। अब यूपी माडल की चर्चा हो रही है।

आप की बात

सुरक्षा व्यवस्था में खामियां

गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा सुरक्षा व्यवस्था में व्याप्त गंभीर खामियों की सच्चाई को उजागर करता है। राजधानी दिल्ली के समीप इस स्तर की धोखाधड़ी का संचालन न केवल प्रशासन की चूक है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा माना जा सकता है। आरोपी ने नकली राजनयिक पहचान, कूट दस्तावेज, और राजनयिक पासपोर्ट के सहारे न केवल लोगों से ठगी की बल्कि हवाला और संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से भी उसका संबंध सामने आया है। यह कोई साधारण अपराध नहीं बल्कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। हथियार सौदागरों और विदेशी खुफिया एजेंसियों से आरोपी की कथित निकटता सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। यह मानना कठिन है कि इतना बड़ा जाल एक व्यक्ति अकेले चला रहा था। यह निश्चित रूप से एक संगठित गिरोह की करतूत है। इसलिए आवश्यकता है कि इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जाए, उसके सभी सहयोगियों का पता लगाया जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली को चाक-चौबंद बनाया जाए। यह मामला केवल कानून व्यवस्था नहीं, देश की संप्रभुता से जुड़ा है। अतः त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए।

– **अमृतलाल मारू, 'रवि'** इन्दौर

जर्जर स्कूलों के भवन

मध्यप्रदेश हो या राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो सभी की सरकारी शिक्षा की स्थिति अमूमन एक जैसी ही नजर आती है। शिक्षा व्यवस्था के ढांचे को सुधारने हेतु केंद्र और राज्य सरकारें का शिक्षा सुधार के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाना और दूसरी और पुराने जर्जर होते स्कूल भवन जिनकी छतें और दीवारें कभी भी भरभरा कर गिर जाती है जिससे बच्चे दबकर मर जाते है घायल हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं सरकार की योजनाओं को मुंह चिढ़ाती है । स्कूल भवन गिरने से बच्चो की मौत पर ब्लाक ,जिले, संभाग और राज्य में स्कूलों की व्यवस्था संचाले जिम्मेदार अधिकारी भी उतने ही दोषी है जितना स्कूल प्रधान या शिक्षक को माना जाता है । इसे दुर्भाग्य कहे या फिर विडम्बना कहे कि स्कूलों की स्कूली भवनों की छत गिरने से छात्रों की मौत का मामला हो या दूषित मध्यान्ह भोजन से छात्रों का बीमार होना होना हो विपक्ष द्वारा अक्सर संस्था प्रधान या स्कूली शिक्षको को ही सर्वप्रथम बलि का बकरा बनाया जाता है । जबकि घटना के वास्तविक जिम्मेदारें पर कभी भी कार्यवाही नही की जाती है । हर वर्ष देशभर के सरकारी स्कूलों की खरी जानकारी आनलाइन यू डाइस के माध्यम से शाला प्रधान द्वारा भरी जाती है जिनमे भवन की जीर्णशीर्ण की स्थिति भी अंकित होती है । क्या यू यू डाइस के माध्यम से शाला भवनों की जीर्णशीर्ण की जानकारी का परीक्षण जिला और राज्य स्तर के अधिकारी द्वारा नही किया जाता?

– **अरविंद रावल**, झाबुआ

धर्मस्थलों पर भगदड़

हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में रविवार को हुए भगदड़ हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत और कई के घायल होने की खबर ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों की भीड़-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी बेंगलुरु में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भी ऐसी ही भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। यह साफ संकेत है कि हमारे देश में भीड़ प्रबंधन और जनसुरक्षा के मामले में अब भी गंभीर खामियां मौजूद हैं। हरिद्वार जैसे धार्मिक और भीड़भाड़ वाले शहरों में प्रशासन को यह अंदाजा होना चाहिए कि विशेष पर्वों या अवकाश के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में मंदिर परिसर, प्रवेश मार्ग और निकासी द्वार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, स्वास्थ्यकर्मी और वॉलंटियर तैनात करने चाहिए। साथ ही, सीसीटीवी निगरानी और अनाउंसमेंट सिस्टम की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक विफलता के साथ-साथ आम जनता का भी गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार इस तरह की घटनाओं का एक बड़ा कारण है। एक ही दिन में ब्रह्मअष्टक पुष्पच्छ कमाने की होड़ में हजारों की भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ती है। कोई फॉल में खड़ा नहीं रहना चाहता, कोई इंतजार नहीं करना चाहता, हर कोई सबसे पहले दर्शन करना चाहता है।

– **सुभाष चुहानवाला**, रतलाम

शौर्य और बलिदान का प्रतीक

कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य जीत का पर्व नहीं, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की प्रेरक गाथा है। 1999 में जब पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंचाइयों पर कायरता से कब्जा जमाया, तब भारतीय वीर सैनिकों ने जान की परवाह किए बिना दुश्मन को खदेड़ कर भारत की भूमि पुनः प्राप्त की। यह विजय संकल्प, साहस और बलिदान का प्रतीक बन चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की ओर से बार-बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया। वाजपेयी जी की ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा हो या मोदी जी की अचानक की गई लाहौर यात्रा, हर प्रयास के उत्तर में भारत को आतंकवाद, पीठ में छुरा और छल ही मिला। यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान शांति के योग्य नहीं, केवल कठोर नीति ही उसके लिए उपयुक्त उत्तर है। भारत को अब अपनी नीति में निर्णायक परिवर्तन करना होगा। जैसे हाल में निशा की पहलगाम यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की जल-आपूर्ति पर कार्रवाई की गई, वैसी ही कठोरता हर मोर्चे पर दिखाई जानी चाहिए। व्यापार, आवाजाही और कूटनीति, सब पर पूर्ण विराम लगाया जाना चाहिए। सीमा पर हर समय चौकसी रखनी होगी। सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि आवश्यक है।

– **विभूति पुपक्या**, खाचरोद, उज्जैन